निःस्वार्थ सेवा के 20 वर्ष

लोक नीति शोध केन्द्र

PUBLIC POLICY RESEARCH CENTRE

लोक नीति शोध केंद्र

मार्गदर्शनः
डॉ. सुमीत भसीन

संपादनः
अवनि सबलोक
राहुल कुमार दूबे
दीपा कौशिक
सत्यजीत लांडगे
नैंसी शर्मा
शुभम जानी

अक्टूबर, 2021

विषयसूची

1	भूमिका	6
2	जमीन से जुड़े नेता एवं एक मार्गदर्शक	8
3	अंतिम छोर तक संपर्कः देश सेवा को समर्पित	13
4	राष्ट्र निर्माणः आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम	24
5	नागरिकों का सशक्तिकरणः व्यवस्था में अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना	30
6	भारत की ताकत को मजबूती देनाः वैश्विक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए सबक	41
7	आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंसः आधुनिक भारत के रक्षक	56
8	समस्या को सुलझाने वाले नेताः एतिहासिक गलतियों का समाधान	60
9	संदर्भ	66

प्रस्तावना

श्री नरेंद्र मोदी, जो शुरुआत में गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर भारत के प्रधानमंत्री बने, दुनिया भर में एक आम नाम बन चुके हैं। उनके जीवन के शुरुआती अनुभवों ने उन्हें न केवल कठिन परिश्रम का महत्व सिखाया, बल्कि उन्हें आम लोगों के अपरिहार्य दुखों से भी अवगत कराया, जिसने उन्हें बचपन से ही लोगों और देश की सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी सेवा का उल्लेख करने से पूर्व इस स्तर तक पहुँचने की उनकी यात्रा अपने आप में प्रेरणादायी है। देश के लिए अपनी दो दशक की सेवा के दौरान उन्होंने गुजरात के विकास मॉडल की सफलता को भारत के समग्र विकास के लिए आगे बढ़ाया है। उनके उत्कृष्ट नेतृत्व में हमारे देश ने अभूतपूर्व स्तर की जन-केंद्रित और राष्ट्र-निर्माण की गतिविधियों को देखा है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास" की राह पर चलकर समावेशी, विकासात्मक और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के लिए शासन में एक आदर्श परिवर्तन की शुरुआत की। योजनाओं और सेवाओं को लोगों तक उनके घर तक पहुँचाना सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री तेज गति से काम कर रहे हैं। आज, भारत 'आयुष्मान भारत' जैसी योजनाओं का साक्षी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है, जो भारत के वंचितों और नव-मध्यम वर्गों को उच्च गुणवत्ता वाली सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। मोदी सरकार की व्यापार-समर्थक नीति के कारण भारत विदेशी निवेशकों के लिए एक चुंबक बन गया है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मानिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की, जो कि 2019-20 में भारत के GDP का लगभग 10% है।

लोक नीति शोध केंद्र में हमने 20 वर्षों के दौरान हमारे माननीय प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को संकलित किया, साथ ही साथ इस बात पर भी ध्यान दिया गया है कि कैसे उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी देकर देश में एकता और शांति की भावना को उत्पन्न किया है। इसके अलावा, सरकार के प्रभावी निर्णय लेने से अयोध्या में राम मंदिर, जम्मू-कश्मीर के लोगों को समान अवसर का प्रावधान जैसे दशकों पुराने गतिरोधों को दूर किया गया है, साथ ही कोविड -19 महामारी के खिलाफ रक्षात्मक प्रणाली को कैसे लागू किया गया है। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम स्थापित किए। जमीनी स्तर पर चिंताओं को दूर करके सरकार ने जनता का विश्वास हासिल किया है और उनके साथ संवाद स्थापित किया है।

यह रिपोर्ट स्पष्ट मंशा और राष्ट्र को प्रभावित करने वाले सभी क्षेत्रों को विकसित करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किए गए और लागू किए गए प्रयासों को सूचीबद्ध करती है। रिपोर्ट उस दृढ़ता को दर्शाती है जिसके साथ श्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन और राष्ट्र-निर्माण के संबंध में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे प्रधानमंत्री द्वारा उनके प्रयासों की सराहना करने और न्यू इंडिया के उनके दृष्टिकोण को समझने के लिए उनकी उपलब्धियों और निर्णयों को पढ़ेंगे।

सुमीत भसीन, निदेशक, पीपीआरसी

भूमिका

हमारे देश में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित नेताओं में से एक श्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी राजनीति में एक लंबा सफर तय किया है, पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और अब प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल बेहद ही शानदार रहा है। 130 करोड़ लोगो का मजबूत राष्ट्र उनके करिश्मे और राजनीतिक कौशल से प्रभावित हुआ है, इस दौरान उन्होंने एक मजबूत राजनीतिक और आर्थिक संबंध विकसित किये है, जिससे वह दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गये है। उन्होंने भारत के सामाजिक और सुरक्षा परिदृश्य को पुनर्जीवित किया है, लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा किया है और भ्रष्टाचार मुक्त और जन-केंद्रित शासन प्रदान करने के लिए दिन-प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से काम किया है। देश की समृद्ध परंपराओं को पुनर्जीवित करके हमारे समाज और देश की समग्र विकास यात्रा के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दों को छुआ है जो देश को परेशान करने वाले सामाजिक मुद्दे है और उन्होंने सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित किया और एक सक्षम नेता के तौर पर हमारे राष्ट्र की यात्रा को समृद्ध किया है।

सांस्कृतिक पक्ष के अलावा, मोदी सरकार के दौरान भारतीय कूटनीति का मानवीय और करुणामय चेहरा भी हमारे सामने आया। इस भावना को केंद्र में रखते हुए प्रशासन ने दुनिया के 30 मिलियन भारतीय डायस्पोरा को भी आगे बढ़ाया, भारत से संबंधित होने की उनकी भावना को मजबूत किया और राष्ट्रीय पुनरुद्धार मिशन में उनकी मदद को सूचीबद्ध किया। इसके अलावा, प्रवासी भारतीयों को राष्ट्र का ब्रांड एंबेसडर बताते हुए और उनके जीवन को हर संभव तरीके से पोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते श्री नरेंद्र मोदी ने उनके जीवन को छुआ और उन्हें भारत के करीब लाने में सहयोग किया।

श्री नरेंद्र मोदी ने अतीत की सर्वोत्तम प्रथाओं को आगे बढ़ाया है और राष्ट्र के गौरवशाली भविष्य की दिशा में काम किया है। उन्होंने अलग-अलग मौकों पर दोहराया है कि कैसे गुजरात में उनके प्रशासनिक अनुभव ने उन्हें हर क्षेत्र की बारीकियों को बेहतर तरीके से समझने में मदद की। विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), और इसके अतिरिक्त भारत के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय पहल, विशेष रूप से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) के साथ गुजरात (2001) में भूकंप के दौरान कार्यान्वित क्षमता निर्माण के दौरान मालिक द्वारा संचालित पुनर्निर्माण दृष्टिकोण और बहु-खतरा प्रतिरोधी निर्माण पर जोर दिया गया है।

'विकास पथ' को सुदृढ़ करने के लिए न केवल मुख्य भूमि और तटीय क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, बल्कि आंतरिक इलाकों में भी बुनियादी ढांचे के त्वरित, केंद्रित और प्राथमिकता संचालित विकास के लिए समर्पित है, जिससे भारतीय उत्पादों को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलती है और रसद लागत और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार और सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ रणनीतिक स्थानों को सुरक्षित भी किया जा सकता है।

वह देश को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के प्रमुख प्रस्तावक हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी में वृद्धि के नेतृत्व में देश में इलेक्ट्रॉनिक रूप से बेहतर बुनियादी ढांचे ने देश के कोने-कोने में रहने वाले लोगों के दरवाजे पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। भारतनेट परियोजना, ऑप्टिकल

फाइबर नेटवर्क जैसे सरकारी कार्यक्रम और परियोजनाएं न केवल लगातार ग्राम पंचायत स्तर पर अपनी पहुंच बढ़ा रही हैं, बल्कि द्वीप संघ शासित प्रदेशों को प्रौद्योगिकी संचालित सेवाओं तक पहुंच भी प्रदान कर रही हैं, हाल ही में पहली बार अंडरसी ऑप्टिकल का उद्घाटन किया गया है। जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए फाइबर केबल परियोजना है। श्री नरेंद्र मोदी ने संकट को अवसर में बदलने के लिए जोश पैदा करने का मार्ग दिखाया है। महामारी के समय आत्मनिर्भर भारत के उनके आह्वान ने आयात पर भारत की अस्वस्थ और अतृप्त निर्भरता को सामने लाया और भारत को इसमें सुधार के लिए उपयुक्त क्षण दिया। आत्मानिर्भर कार्यक्रम स्वदेशीकरण से परे है, और इसका उद्देश्य भारत की अंतर्निहित शक्तियों को फिर से खोज और विकसित करते हुए राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। विचार अकेले चलने का नहीं है, बल्कि रणनीतिक रूप से निर्भर और रणनीतिक रूप से अन्योन्याश्रित होने के कारण पुनर्संतुलन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक एकजुट शक्ति रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्रौद्योगिकी तक समान पहुंच प्रदान करके, बिचौलियों को खत्म करके, पारदर्शिता को प्राथमिकता देकर, एक राष्ट्र एक संविधान की प्रतिज्ञा को पूरा करके और लोकतंत्र के जमीनी स्तर और शिकायत निवारण को साबित करके राष्ट्र को एक साथ बुना है।

श्री नरेंद्र मोदी के आगमन के साथ, पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और फिर भारत के प्रधान मंत्री के रूप में, जन-केंद्रित शासन, विकासात्मक कूटनीति, सक्रिय विदेश नीति की भागीदारी, जमीनी स्तर पर आउटरीच और प्रदर्शन आधारित राजनीति के एक नए युग की शुरुआत का संकेत दिया है। "सबका साथ, सबका विकास" के वादे को कायम रखते हुए, श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अपने लगातार दूसरे कार्यकाल में सुशासन की विरासत को जारी रखा है। उन्होंने निर्णय लेने में तेजी लाने के लिए समावेशी, विकासोन्मुख और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की सफलतापूर्वक शुरुआत की है। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने शासन, सार्वजनिक नीति और विदेश नीति के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अकादमिक साहित्य के प्रकार और मात्रा को पहले कभी उत्पन्न नहीं किया है।

जैसे ही श्री नरेंद्र मोदी संवैधानिक कार्यालय में अपने 20वें वर्ष के करीब पहुंच रहे हैं, उन उपलब्धियों को पहचानना महत्वपूर्ण है, जिनका उन्होंने नेतृत्व किया। अपने नेतृत्व के दौरान, उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने उन सभी को अच्छी तरह से संभाला और उत्कृष्ट शासन का एक मानक बनाया जो दुनिया भर के नेताओं को प्रेरित करता रहा। उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल का इस्तेमाल उन चुनौतियों का सामना करने के लिए किया जिनका लोग सामना कर रहे थे, और उन्होंने इसे किसी और की तुलना में अधिक सफलतापूर्वक किया। इसलिए, हम लोक नीति शोध केंद्र द्वारा निर्मित इस व्यापक अध्ययन में पिछले 20 वर्षों में उनकी उपलब्धियों और उनके नेतृत्व में सरकार द्वारा की गई कई पहलों का एक सिंहावलोकन प्रस्तुत कर रहे है ।

जमीन से जुड़े नेता एवं एक मार्गदर्शक

श्री नरेन्द्र मोदी जी ने बहुत ही कम उम्र में लोगों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने का निश्चय किया और तभी से एक गतिशील, निर्णायक और विकासोन्मुख नेता की भूमिका निभा रहे हैं, जो जोकि एक आशा की किरण बनकर उभरे हैं। एक अरब भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए पहले उन्होंने अपने गृह राज्य गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 13 सालों तक एक जमीनी कार्यकर्ता, एक आयोजक और एक प्रशासक के रूप में अपने दायित्व निभाए, जहां उन्होंने जन-समर्थक और सक्रिय सुशासन की दिशा में एक आदर्श बदलाव की शुरुआत की। 26 मई 2014 की शाम को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में इतिहास लिखा गया था क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता से प्राप्त ऐतिहासिक जनादेश के बाद भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और तब से वह देश में लोगों के जीवन में गुणात्मक अंतर लाने के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अपने नेतृत्व से उदाहरण पेश किया है, जिसमें हमारी प्राचीन परंपराओं से सीखते हुए कुछ बेहद सकरात्मक कार्य किए है, उदाहरण के लिए हर साल प्रधानमंत्री श्री मोदी दिवाली मनाने के लिए सैनिकों के पास जाते हैं, जिस परंपरा को उन्होंने 2014 में पीएम का पद संभालने के बाद से शुरू किया था। उन्होंने सेना के जवानों से बात करते हुए उल्लेख किया कि

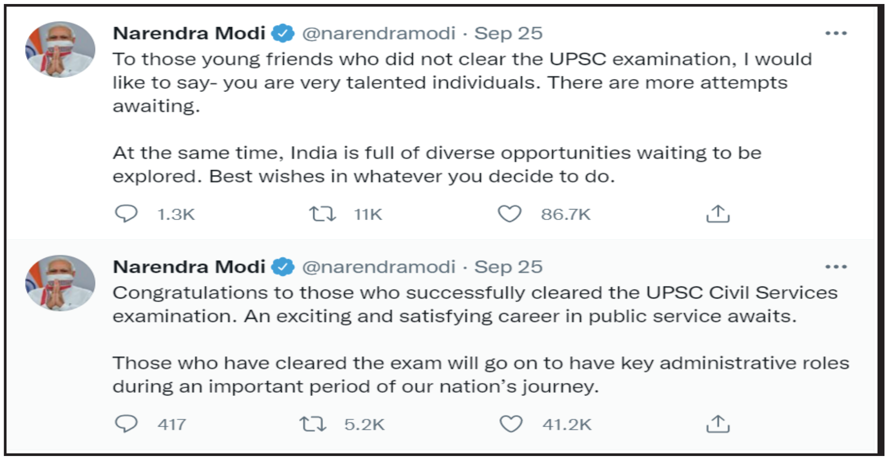

Narendra Modi @narendramodi · Sep 25
To those young friends who did not clear the UPSC examination, I would like to say- you are very talented individuals. There are more attempts awaiting.

At the same time, India is full of diverse opportunities waiting to be explored. Best wishes in whatever you decide to do.

1.3K 11K 86.7K

Narendra Modi @narendramodi · Sep 25
Congratulations to those who successfully cleared the UPSC Civil Services examination. An exciting and satisfying career in public service awaits.

Those who have cleared the exam will go on to have key administrative roles during an important period of our nation's journey.

417 5.2K 41.2K

'यह एक परंपरा है कि लोग अपने परिवार के साथ दिवाली मनाते हैं और मैंने भी इसे अपने परिवार के साथ मनाने का फैसला किया है। मैं यहां आपके साथ जश्न मनाने आया हूं। आप मेरा परिवार हो'।

एक प्रेरक

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन और आदर्शों से एकात्म मानववाद के उनके सिद्धांतों से प्रेरणा लेते हुए, श्री नरेंद्र मोदी ने यह सुनिश्चित किया है कि शासन विकास की यात्रा में कोई पीछे न रह जाए। समाज के हर वर्ग, चाहे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और यहां तक कि ट्रांसजेंडर समुदाय की जरूरतों और आकांक्षाओं को समायोजित करने के लिए 'न्यू इंडिया' का सपना हमारे प्रधानमंत्री ने देखा है।

सितंबर 2019 में चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग विफल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसरो अध्यक्ष को सांत्वना देने और प्रोत्साहित करने के प्रयास में उन्हें गले लगाने वाले पल ने दुनिया भर के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को छुआ और विश्वास, आशा तथा आशावाद की एक नयी संस्कृति को जन्म दिया। सफलता के दौरान प्रशंसा और प्रोत्साहन एक सामान्य बात है, लेकिन असफलता के थका देने वाले और कष्टदायक समय में एक दृढ़ समर्थन प्रदान करना दुर्लभ है, और जब यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से आता है, तो यह और भी विशेष हो जाता है। जब पीएम मोदी ने इसरो के अध्यक्ष के. सिवन की पीठ थपथपाई और अंतरिक्ष एजेंसी के बेंगलुरु मुख्यालय के बाहर उन्हें सांत्वना देते हुए देखा, तो दुनिया दंग रह गई। दृश्य पूरे देश के दिल को छू लेने वाले थे जिन्होंने नागरिकों को फिर से पुष्टि की, कि चाहे कुछ भी हो जाए, श्री मोदी अपने लोगों के लिए सदैव दृढ़ता से खड़े हैं।

हाल ही में, जब भारतीय महिला हॉकी टीम टोक्यो 2020 ओलंपिक में कांस्य पदक से चूक गई, तो हमारे देश की बेटियों को सांत्वना देने वाले प्रधानमंत्री जी को देख हर नागरिक की आंखों में आंसू आ गए। हर तबके से आने वाली इन बेटियों पर सभी नागरिकों को गर्व था क्योंकि उन्होंने उस मुकाम तक पहुंचने के लिए अथक प्रयास किए, जबकि प्रधानमंत्री ने उनके धैर्य और ताकत को बढ़ाया। इसके अलावा, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने एक साक्षात्कार में स्वीकार किया कि बेल्जियम से टीम की सेमीफाइनल में हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातों ने उनकी टीम के लिए अद्भुत काम किया और खिलाड़ियों में सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 41 सालों की पीड़ा समाप्त हुई।

एक समाज सुधारक

जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने माना कि खुले में शौच महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक था, और अपने पहले स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के अपने दृष्टिकोण को पेश किया। सौभाग्य से राष्ट्र ने प्रधानमंत्री की इस घोषणा पर उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने अपने मन की बात शो के माध्यम से उत्थानवर्धक कहानियों से जनता को रूबरू करने का सिलसिला जारी रखा, जिसमें उन्होंने इस बात को भी बताया कि कैसे भारत भर में लड़कियां और महिलाएं शौचालय को गरिमा के प्रतीक के रूप में चाहती हैं, या कैसे लोग उन्हें बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से विनम्र अनुरोध करते हुए देश को स्वच्छ और रोग मुक्त बनाने के लिए अपने आस-पास के माहौल को अपने घर

की तरह स्वच्छ बनाए रखने का आग्रह किया और लोगों को यह मंत्र दिया, "न गंदगी करेंगें, न गंदगी करने देंगे।"

जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को स्वच्छता अभियान में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, तो यह एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। स्वच्छ भारत आंदोलन ने लोगों में कर्तव्य की भावना पैदा की है, और प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से स्वच्छता अभियान में भाग लेकर देशवासियों को यह संदेश दिया है कि पर्यावरण और आसपास की सफाई कोई मामूली काम नहीं है जो सभी को करना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप पूरे देश में लोग सफाई से जुड़ी गतिविधियों में तेजी से सक्रिय हो गए है, जिससे महात्मा गांधी जी के "स्वच्छ भारत" के दृष्टिकोण को वास्तविकता के करीब लाया गया।

पवित्र गंगा के लिए प्रधानमंत्री का प्रेम और इसे साफ करने की उनकी इच्छा ने ही वाराणसी में एक सदी से भी अधिक समय से गंगा को प्रदूषित करने वाले विशाल नालों से मुक्ति दिलायी। उन्होंने नमामि गंगे परियोजना के लिए पीएम के रूप में प्राप्त वस्तुओं की ई-नीलामी से जुटाए गए धन को देकर अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रति अपने दायित्व का निर्वाहन किया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय नेताओं को पवित्र गंगा आरती में आमंत्रित करके दुनिया को इसकी संस्कृति से अवगत करवाया है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री की अपील की प्रशंसा हुई और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित करके योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी गई। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्थापित करने के बाद, योग के कई आयामों पर चर्चा और अच्छी समझ विकसित होना शुरु हुआ, इसके साथ ही योग पर अकादमिक रूप से चर्चा करना दुनिया भर में महत्वपूर्ण हो गया और 2015 से योग दिवस का विषय न केवल स्वास्थ्य लाभ पर बल्कि शांति, यूथ, हार्मनी, क्लाइमेट एक्शन और हाल ही में "वेलनेस" पर पर भी केंद्रित हुआ।

पूरी दुनिया को जोड़ने में योग का महत्व पीएम मोदी और 84 देशों के गणमान्य व्यक्तियों सहित लगभग 36,000 लोगों की भागीदारी से स्पष्ट होता है, जिन्होंने पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर 35 मिनट के लिए 21 आसन किए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने दो रिकॉर्ड बनाए, पहला एक ही स्थान पर सबसे बड़ी योग कक्षा के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और दूसरा सबसे अधिक संख्या में विभिन्न राष्ट्रों के नागरिकों ने इसमें भाग लिया।

अंतरिक्ष में खोज

- **भारत मंगलयान के साथ पहले प्रयास में मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया।**
- **इसरो ने एक ही उड़ान में 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है।**
- **अंतरिक्ष में भारत का झंडा फहराने वाला पहला स्वदेशी मिशन गगनयान।**

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हर साल मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि भारतीय सांस्कृतिक कूटनीति के हिस्से के रूप में योग ने विश्व के विभिन्न देशों के लोगों के बीच लोकप्रियता और स्वीकृति दोनों प्राप्त की है। प्रधानमंत्री ने अपने निजी जीवन में योग के महत्व को बार-बार रेखांकित किया है और राष्ट्र को इस पारंपरिक भारतीय अभ्यास का दैनिक आधार पर पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

लगभग एक साल तक चली महामारी के बावजूद करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। इस वर्ष के योग दिवस का विषय "योग फॉर वेलनेस" पर जोर देता है, जिसे दुनिया के विशेषज्ञों द्वारा अनुमोदित किया गया है, साथ ही हमारी श्वसन प्रणाली को मजबूत करने के लिए 'प्राणायाम' और 'अनुलोम-विलोम' जैसे श्वास अभ्यासों के महत्व पर भी जोर दिया गया है। दुनिया को एम-योग ऐप मिल रहा है जो कई भाषाओं में सामान्य योग प्रोटोकॉल पर आधारित योग प्रशिक्षण के कई वीडियो उपलब्ध कराएगा।

भारत में दिवाली का त्योहार अमावस्या (जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता) के दिन मनाया जाता है। दीयों और मोमबत्तियों की रोशनी अंधेरे की बुरी ताकतों पर जीत का प्रतीक है। "ताली और थाली बजाओ" से पहले जब लोग अपने घरों में बंद थे और उम्मीद खो रहे थे, तब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अपील पर, पूरे देश के नागरिकों ने 9 दीये, मोमबत्तियां जलाने के साथ अपने मोबाइल और टॉर्च की रोशनी से कोरोनावायरस से फैले अंधेरे को दूर करने का प्रतीकात्मक प्रयास किया। जिसने देश भर के नागरिकों के बीच एकता की एक मजबूत भावना को दर्शाया और भारतीयों के दिलों में एक नयी उम्मीद जगाई।

एक अन्य अपील में, श्री मोदी ने भारत में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण के दिन (1 मार्च, 2021) को पहला कोविड -19 वैक्सीन जैब प्राप्त करके एक उदाहरण स्थापित किया। टीकाकरण को लेकर संशय के माहौल में, टीके की अप्रभावीता और दुष्प्रभावों की कहानियों में, यह भारत के प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी थे, जिन्होंने खुद को टीका लगाया और देश के नागरिकों के बीच विश्वास पैदा किया, ताकि देश के नागरिकों को इस बीमारी को हराने में मदद मिल सके।

जेएएम (जन धन योजना- आधार-मोबाइल), डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण), प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना, ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर स्विच करने और यूपीआई-आधारित भीम एप्लिकेशन गेटवे जैसी नीतिगत पहल सरकार ने की है, हालांकि लोगों में इन पहलों को लेकर शुरुआती झिझक थी, फिर भी उन्होंने इन नीतियों और कार्यक्रमों पर भरोसा किया और इनके साथ आगे बढ़े। यहां तक कि महामारी के दौरान भी लोगों के भरोसे के साथ-साथ शासन प्रणाली में शुरू किए गए परिवर्तनों के प्रति दृढ़ संकल्प को भी मजबूत किया। इस प्रकार उपयुक्त सुधारों के माध्यम से परिवर्तनकारी प्रभाव डालना।

डिजिटल पाथवे ने महामारी के दौरान 'संपर्क-रहित' भुगतान और वितरण प्रणाली की आवश्यकता के लिए एक उपाय के रूप में काम किया। भारत ने अपनी लक्षित वितरण प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों को सफलतापूर्वक चिह्नित करके, उन्हें लाभ प्रदान किया, जिससे इस संकट के दौर में बहुत राहत मिली। आरोग्य सेतु, एक कोविड -19 संपर्क ट्रेसिंग एप्लिकेशन है, जिसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम द्वारा प्रशंसा की गई और कोविन ऐप ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ "दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान" को सफलतापूर्वक संचालित किया। डिजिटल स्वास्थ्य ढांचा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत न्यायसंगत, सुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने और भारत के स्वास्थ्य लक्ष्यों पर प्रगति में तेजी लाने में मदद करेगा। डिजिटलाइजेशन के जरिए पीएम द्वारा लाए गए क्रांतिकारी बदलावों की दुनिया भर में सराहना हो रही है।

सभी के लिए सम्मान

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सभी को सम्मान के अपने दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए सबसे पहले पद्म पुरस्कारों को लोगों के पुरस्कार में बदला। यह पहली बार था जब अधिकांश गुमनाम नायकों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो विनम्र पृष्ठभूमि से आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अद्वितीय क्षमताओं को पहचानने और उनकी सराहना करने का यह श्री मोदी का दृष्टिकोण है। जो लोग घने जंगल के बीच आदिवासी बच्चों के लिए पुस्तकालय चलाते हैं, जो स्वयं दिहाड़ी मजदूर होते हुए भी गरीबों के लिए अस्पताल चलाते हैं, कुछ जिन्होंने आयुर्वेद और पारंपरिक तकनीकों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है, और यहां तक कि वे भी जिन्होंने 97 वर्ष की उम्र में, दूरदराज के इलाकों में सैकड़ों गरीब महिलाओं को सुरक्षित बच्चों को जन्म देने में मदद की, पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। इस भाव से देशवासियों का मनोबल काफी बढ़ा है और देशवासियों में सहभागी शासन के मूल्यों का संचार हुआ।

नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया की ताकत को पहचानने वाले और इसका प्रयोग नागरिकों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के लिए करने वाले पहले राजनीतिक नेताओं में से एक थे। उनका

रचनात्मक मासिक रेडियो शो 'मन की बात', भारतीय नागरिकों के साथ चर्चा करने का एक मजबूत साधन हैं जिसमें वे सकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं और देश को प्रभावित करने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। उन्होंने छात्रों के लिए 'परीक्षा योद्धा' पुस्तक भी लिखी, जो परीक्षा के दौरान कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री का उद्देश्य केवल भारत में विकास और जीवन स्तर में सुधार करना नहीं है, बल्कि भारत की मूल ताकत का निर्माण करना है जो आज के युवाओं को एक समृद्ध नए कल के लिए मार्गदर्शन करती है। वह भारत को इस तरह से बदल रहे हैं कि घरेलू सीमाओं के अंदर बेहतर अवसर प्रदान करके 'ब्रेन ड्रेन' की श्रृंखला पर अंकुश लगा सके। पीएम सीधे लोगों तक पहुंचकर सूक्ष्म आर्थिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्होंने स्कूली छात्रों के साथ बातचीत की, शिक्षा की धारणा को बदल दिया, परीक्षाओं को एक तनावपूर्ण कार्य से व्यक्तिगत विकास के लिए एक साहसिक कार्य के तौर पर संबोधित किया और भविष्य के लाभों को प्राप्त करने की नीति के रूप में ईमानदार प्रयासों को बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री की गतिशील आभा युवाओं को प्रेरित करती है और उनमें यह विश्वास जगाती है कि वे अपने कार्यों से

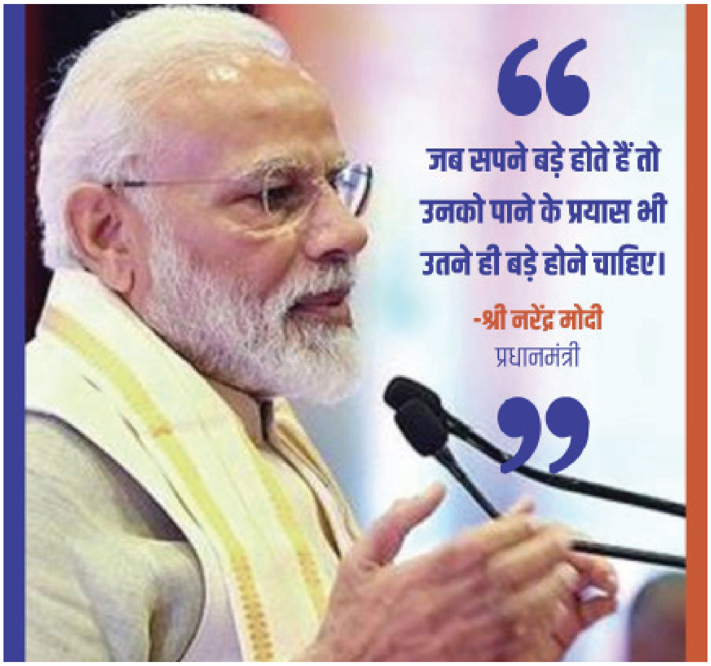

बदलाव ला सकते हैं।

न केवल भारत को आत्मनिर्भर होने तथा 'वोकल फॉर लोकल' और 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' की थीम पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि विदेशी मिशनों से भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने और वैश्विक आपूर्ति का समर्थन करने के लिए प्रवासी लोगों के साथ मिलकर काम करने का भी आग्रह किया। यह देश के लिए एक वाटरशेड घटना थी, जब प्रधानमंत्री ने अनुरोध किया कि सेंट्रल विस्टा के निर्माण में शामिल निर्माण श्रमिकों के नाम भवन पर अंकित किए जाएं, क्योंकि इससे एक स्पष्ट संदेश जाता है कि प्रत्येक कार्य का महत्व होता है और जब यह राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य को पूरा करता है तो इसकी सराहना की जानी चाहिए। ◆

अंतिम छोर तक संपर्क

(देश सेवा को समर्पित)

कंक्रीट, स्टील, बिजली, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के साथ-साथ फाइबर-ऑप्टिक केबल प्रमुख आर्थिक निर्माण तत्व हैं जो किसी राज्य के आर्थिक इंजन को चलाते हैं। अवसंरचना सुविधा कार्य में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है, कंपनियों को ऊर्जा प्रदान करती है, कार्यबल को उनके कार्यक्षेत्र से जोड़ती है, वंचित आबादी के लिए अवसर प्रदान करती है, और देश को तेजी से अस्थिर प्राकृतिक उदाहरणों से बचाती है। प्रत्येक निर्वाचित प्रशासन को एक ठोस बुनियादी ढांचे के निर्माण की शुरू करने की आवश्यकता होती है जो बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है और महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण सेवा को समय पर और बिना देरी के प्रदान करता है। श्री नरेंद्र मोदी की सरकार को हमेशा बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पहचाना गया है, जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे और भारत के प्रधान मंत्री बनने के बाद भी उन्होंने एक दूरदर्शी नेता के तौर पर भारत के बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए नीचे सूचीबद्ध की गई कई पहलों को आरंभ किया।

विकास की गाथा: गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी

1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में गुजरात राज्य के लिए इसके पर्यावरण की अस्थिर प्रकृति के कारण पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं की कमी थी और 2001 में कच्छ और भुज में आए भूकंपों ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया था। 2001 के भूकंप के बाद गुजरात को विकास के पथ पर राज्य को वापस लाने के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए तैयार होने का समय आ गया था।

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मजबूत बुनियादी ढांचे की यात्रा पूर्व पीएम श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना से शुरू हुई थी। हालांकि, इसमें कोई संदेह

Narendra Modi's experience of rebuilding Kutch post-2001 earthquake will serve him well in navigating pandemic crisis

In 2004, PK Mishra — who is currently Principal Secretary to Prime Minister Narendra Modi — wrote a book titled The Kutch Earthquake 2001: Recollection Lessons and Insights, which was published by New Delhi's National Institute of Disaster Management

चित्र 1 फर्स्टपोस्ट, मई 2020

नहीं है कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल ने बुनियादी ढांचे में निवेश और कल्याणकारी सुधारों के शक्तिशाली मिश्रण को सफलता की वर्तमान ऊंचाइयों पर पहुंचाया है।

यह सब तब शुरू हुआ जब श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के भौगोलिक और पर्यावरणीय रूप से अस्थिर राज्य गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, कच्छ और भुज में एक भयानक भूकंप आया, जिसने दुनिया को झकझोर दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से पहले पुनर्निर्माण और पुनर्वास के बीच लोगों द्वारा विकास को एक दूर का सपना माना जाता था। दूसरी ओर, गुजरात केवल तीन वर्षों में नई शासन पद्धतियों की शुरूआत के कारण तेजी से उबरने में सक्षम हुआ।

श्री नरेंद्र मोदी के पदभार ग्रहण करने के कुछ ही समय बाद गुजरात में रिक्टर पैमाने पर 7.7 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया, जिससे 8,000 से अधिक गांवों में व्यापक तबाही हुई। 2001 में भूकंप से उत्पन्न कठिन परिस्थितियों के जवाब में गुजरात सरकार ने विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र और अन्य द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संस्थानों की मदद से पुनर्वास के प्रयास शुरू किए। गुजरात पुनर्वास प्रयास का सबसे रचनात्मक घटक गृह पुनर्निर्माण था।

अपनी तरह के अनूठे भागीदारी कार्यक्रम के रूप में बहु-जोखिम प्रतिरोधी निर्माण और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया।

जनवरी 2004 के अंत तक, 1,86,967 घरों का पुनर्निर्माण किया गया और 9,01,150 घरों की मरम्मत की गई, जिसका काम तीन वर्षों में पूरा किया गया। कच्छ में सरकार ने केवल तीन वर्षों में मरम्मत और पुनर्निर्माण का 83 प्रतिशत काम पूरा किया था। अस्थायी और वैकल्पिक भवनों के साथ भूकंप के बाद थोड़े समय के भीतर सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं को चालू कर दिया गया।

एक दृष्टिकोण, प्रशासनिक कौशल और राजनीतिक संकल्पशीलता के साथ एक बेहतरीन दृष्टिकोण और उत्कृष्ट उदाहरण कच्छ जिले के चार शहरोंः अंजार, भचाऊ, भुज और रापर का पुनर्निर्माण था। एक मालिक द्वारा संचालित पुनर्निर्माण दृष्टिकोण के माध्यम से, लोगों ने सरकार की सहायता और सुविधा के साथ अपने घरों का पुनर्निर्माण किया।

विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास के इंजन हैं और गुजरात ने इसे 2004 में महसूस किया क्योंकि यह एसईजेड अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य था। 2004 में अधिनियमित, इस विधायी बढ़ावा का एकमात्र उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात, घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना और राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करना था।

वर्तमान में, राज्य में अतिरिक्त सेज के साथ 21 कार्यात्मक एसईजेड पाइपलाइन में हैं, जो खुद को देश की एसईजेड राजधानी के रूप में स्थापित कर रहे हैं।

जब श्री मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में राज्य का कार्यभार संभाला, तब राज्य प्रशासन ने एक अभूतपूर्व कदम में स्वतंत्रता के बाद से किसी भी राज्य का सबसे साहसिक और सबसे बड़ा ऊर्जा सुधार किया। उदाहरण के लिए, ज्योतिग्राम योजना, जिसने कृषि फीडर लाइनों को घरेलू और औद्योगिक लाइनों से रणनीतिक रूप से अलग कर एक नई समानांतर पारेषण प्रणाली का निर्माण किया। जिसमें 1000 दिनों से कम समय में 1,290 करोड़ रुपये की

लागात से 56,000 किमी उच्च संचरण लाइनें और 22,000 किमी कम संचरण लाइनों का निर्माण शामिल हैं। हालांकि खेतों को सब्सिडी वाली बिजली मिलती रही, गुजरात के 18,000 से अधिक गांवों को नाममात्र की कीमतों पर निर्बाध 3-चरण गुणवत्ता वाली बिजली मिली, जिसके परिणामस्वरूप रहने की स्थिति में सुधार हुआ और ग्रामीण उद्योग का पुनर्जन्म हुआ। इससे संयंत्र के लोड फैक्टर में सुधार, बुनियादी ढांचे को अद्यतन करने और बिजली चोरी को कम करने में मदद मिली।

श्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान गुजरात विद्युत बोर्ड का पुनर्गठन और अनबंडलिंग पीएसयू टर्नअराउंड का एक विशिष्ट उदाहरण है। गुजरात बिजली बोर्ड को 2001 में 2,543 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था जब श्री मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तो 2010-2011 में 624 करोड़ रुपये का लाभ कमाया। गुजरात एक बिजली अधिशेष राज्य बन गया है, जबकि देश के बाकी हिस्सों में गंभीर ऊर्जा की कमी का सामना करना पड़ रहा था, जबकि पारेषण और वितरण घाटे को 30.64 फीसदी से घटाकर 20.13 फीसदी कर दिया गया था।

गुजरात की सरकार ने राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम, गुजरात आपातकालीन भूकंप पुनर्वास परियोजना, प्रगति पथ, विकास पथ, किसान पथ, विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) सहित कई सड़क निर्माण परियोजनाओं पर महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की।

श्री मोदी के शासनकाल के दौरान शुरू किया गया विकास पथ, शहरों और कस्बों से गुजरने वाले राज्य राजमार्गों को बेहतर बनाने पर केंद्रित था। 2013 तक 132 नगरपालिकाएं थीं और इसमें तालुका मुख्यालय शामिल थे, साथ ही 400 राजमार्गों की कुल लंबाई 749.82 किलोमीटर थी। 2013 तक 391 सड़कों के 713.85 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका था।

किसान पथ, श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना था ताकि कृषि उत्पादों को कृषि उत्पाद बाजार केंद्र तक पहुंचाना आसान हो सके। जिन 10308 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन किया जाना था, जिसमें से 9139 किलोमीटर सड़कों उन्नयन 2013 तक कर लिया गया था।

राज्य राजमार्ग सड़क के हिस्सों को चौड़ा/मजबूत करने के उद्देश्य से, राज्य भर में पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए, प्रवासी पथ योजना शुरू की गई थी। परियोजना ने नवीनीकरण के लिए कुल

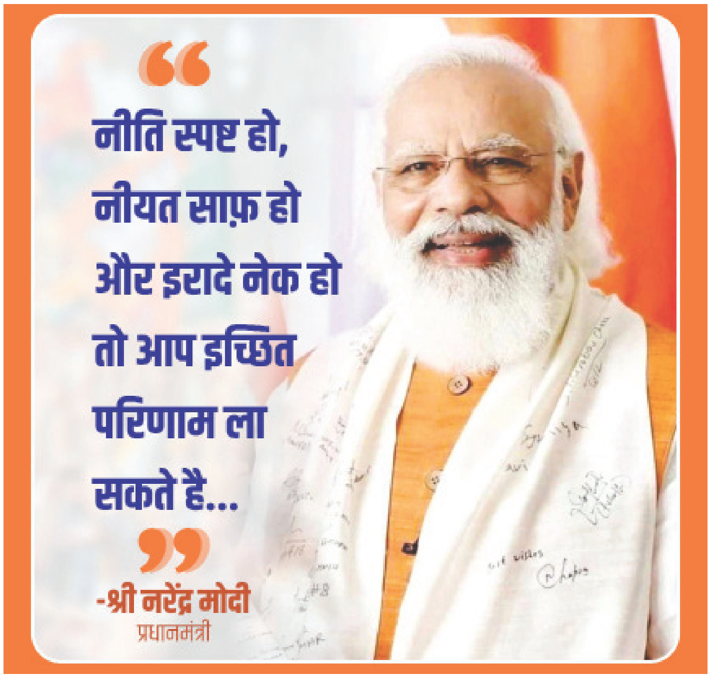

1122 किलोमीटर की लंबाई के साथ 96 सड़कों को नामित किया, 82 मार्गों में से 727 किलोमीटर पर काम 2013 तक समाप्त हो गया।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आर्थिक विकास संस्थान की रिपोर्ट द्वारा गुजरात की सड़कों को विश्व स्तर पर वांछनीय स्तर से अधिक दर्जा दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना को सक्षम तरीके से पूरा करने के लिए राज्य के सड़क और निर्माण विभाग की प्रशंसा की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में गुजरात ने "कार्यान्वयन पूर्णता और परिणाम" के मामले में अन्य राज्यों से बेहतर प्रदर्शन किया।

गुजरात के रोडवेज की सफलता को वैश्विक स्तर पर पहचाना गया। विश्व बैंक के आकलन के अनुसार गुजरात में उत्कृष्ट सड़क अवसंरचना थी। विश्व बैंक के स्वतंत्र मूल्यांकन समूह के निष्कर्षों के अनुसार गुजरात का IRI (अंतर्राष्ट्रीय खुरदरापन सूचकांक) 2013 में 4 मीटर प्रति किलोमीटर से कम था। 2000 से पहले, यह सूचकांक 6 से 20 मीटर प्रति किलोमीटर के बीच था।

कनेक्टिविटी की बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति श्री मोदी के झुकाव ने पूरे राज्य के लिए बदलाव का काम किया। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आभासी माध्यमों से संपर्क ने अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया। उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय में कम्प्यूटरीकरण की पहल करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य था। गुजरात उच्च न्यायालय की हीरक

जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वर्तमान प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कार्यवाही के डिजिटलीकरण से संबंधित गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए कदमों को याद किया और इस बात पर भी संतोष व्यक्त किया कि केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा डिजिटल बुनियादी ढांचे को स्थापित किया गया है। कोर्ट्स इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट को महामारी के दौरान अदालतों द्वारा जल्दी अपनाया गया है।

लोक शिकायत प्रणाली में सुधार के प्रयास में गुजरात सरकार ने स्वागत दिवस नामक एक नई संरचना को लागू किया, जिसमें लोग महीने के एक दिन आवेदक शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा समीक्षा के लिए लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को मुश्किल से हल करने के लिए प्रस्तुत कर सकते थे। मामलों को सीधे हस्तक्षेप के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा जा रहा है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आवेदक की चिंताओं को सुना, संबंधित सरकारी हितधारकों के साथ मामले को उठाया और फिर इस मुद्दे को ठीक किया। 2011 में 14वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान, SWAGAT वोन गोल्ड आइकन अवार्ड (श्रेणीः नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन)। SWAGAT को राष्ट्रमंडल दूरसंचार संगठन और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय द्वारा ई-पारदर्शिता के उत्कृष्ट प्रतिमान के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। सार्वजनिक सेवा के खुलेपन और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए SWAGAT को 2010 में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2010 का विजेता भी नामित किया गया था।

सौराष्ट्र और कच्छ में पानी की कमी के मुद्दे को हल करने के लिए, गुजरात सरकार ने 2011 में राज्य जल वितरण प्रणाली का निर्माण शुरू किया। इसके के लिए, श्री मोदी के नेतृत्व में स्वर्णिम गुजरात सौराष्ट्र-कच्छ जल ग्रिड परियोजना शुरू की गई थी। जिसके तहत 400 किलोमीटर से अधिक लंबी पाइपलाइन बिछाने की योजना थी। गुजरात जल ग्रिड परियोजना राज्य के शुष्क क्षेत्रों में पीने के पानी की आपूर्ति के मामले में एक बड़ी सफलता रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके पाइपलाइन नेटवर्क की लंबाई भारत के पूरे रेलवे नेटवर्क की लंबाई से ज्यादा है। राज्य प्रशासन की इस पहल के परिणामस्वरूप आवासीय जल कनेक्शनों की संख्या में वृद्धि देखी है। इसने लोगों की पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भूजल और वर्षा पर निर्भरता को भी कम किया है। वास्तव में, तेलंगाना और महाराष्ट्र सहित कई अन्य राज्य गुजरात के अनुभव से सीख लेकर जल ग्रिड का निर्माण कर रहे थे। नतीजतन, यह पहल देश भर में पानी की कमी की चिंताओं को कम करने में सहायता कर रही थी।

गुजरात की राज्य सरकार ने 2010 में "स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना" नामक समग्र सुधार से जुड़ी 7,000 करोड़ रुपये की योजना शुरू की, जिसके तहत सभी 159 नगर पालिकाओं के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे जल आपूर्ति और भूमिगत जल निकासी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया गया।

एशिया में पहली बार श्री मोदी के नेतृत्व में गुजरात ने पंचायती-राज संस्थानों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करके एक नए युग की शुरुआत की, जो संचार प्रौद्योगिकी में एक गेम-चेंजिंग प्रगति साबित हुई। ई-ग्राम विश्वग्राम (2009) ने सभी पंचायतों को कवर किया; वही आई.टी. सक्षम संचार उपकरण जो भारत के प्रधानमंत्री के लिए उपलब्ध थे, उन्हें राज्य के आम-आदमी को उपलब्ध कराया गया था। ग्रामीण परिवारों के बीच डिजिटल पहुंच बढ़ाने की दृष्टि से 23 जनवरी, 2009 को गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रूप से ई-ग्राम विश्वग्राम परियोजना का शुभारंभ किया, जिसकी शुरुआत हरिपुरा गांव में हुई और जिसने राज्य की 13693 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड एक्सेस प्रदान किया। इसने एक ही समय में 10,000 ग्रामीण उद्यमियों के रोजगार में भी सहायता की है, इस प्रकार एक ही समय में डिजिटल आउटरीच और रोजगार को संबोधित किया है। इसके अलावा, सभी बुनियादी सेवाएं जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन और कर भुगतान ई-पंचायतों में उपलब्ध हैं।

श्री मोदी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान गुजरात में अन्य राज्यों की तुलना में बड़ी और बेहतर बुनियादी ढांचा परियोजनाएं लागू की। सौनी योजना परियोजना सितंबर 2012 में नर्मदा नदी से सौराष्ट्र क्षेत्र में बाढ़ के पानी को पुनर्निर्देशित करके 115 मुख्य बांधों को भरने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी। नर्मदा के अतिरिक्त बाढ़ के पानी को ग्यारह सौराष्ट्र जिलों के 115 जलाशयों में 1126 किलोमीटर चार-लिंक पाइप के माध्यम से स्थानांतरित करने की परिकल्पना की गई थी, जिससे 10,22,589 एकड़ भूमि को लाभ हुआ।

विकास की गाथा: भारत के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी

तत्कालीन वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा पेश किया गया पहला

बजट जन-केंद्रित शासन के एक नए युग की शुरुआत का संकेत था। जनता के लिए कई कल्याणकारी उपायों की शुरुआत के साथ, भारत की विकास गाथा में एक नया अध्याय जुड़ गया।

देश के आर्थिक विकास में ऊर्जा को प्रमुख खिलाड़ी मानते हुए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की परिकल्पना की गई थी, ताकि सभी घरों में चौबीसों घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति की जा सके। आज की दुनिया में केवल एक क्लिक के साथ कार्यों को जल्दी और आसानी से पूरा करने के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचे की आवश्यकता थी। डिजिटल इकोसिस्टम के महत्व को देखते हुए, डिजिटल इंडिया अभियान को ग्रामीण स्तर पर ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करके, आईटी सक्षम प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाओं तक बेहतर पहुंच, सरकारी प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता, निर्यात के लिए आईटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करके डिजिटल डिवाइड को और पाटने के लिए शुरू किया गया था।

श्री नरेंद्र मोदी प्रशासन 2022 तक सार्वभौमिक आवास प्रदान करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए, 2014 में लोगों को विशेष रूप से युवाओं को अपने घरों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए गृह ऋण पर एक अतिरिक्त कर लाभ की पेशकश करने का प्रस्ताव किया गया था। 2014 में राष्ट्रीय आवास बैंक पर आधारित एक कम लागत वाले किफायती आवास मिशन की स्थापना का भी सुझाव दिया गया था। कम लागत वाले, किफायती घरों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन तैयार किया गया था।

श्री मोदी के नेतृत्व में विदेश मंत्रालय ने मिशन/पोस्ट (नों) और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ-साथ भारत में विदेशी राजनयिक और व्यापार मिशनों के बीच सुविधा प्रयासों के समन्वय के लिए अक्टूबर 2014 में एक नए 'राज्य प्रभाग' की स्थापना की। म्युनिसिपल बांडों को सीधे बाजार से धन जुटाने की अनुमति दी गई।

केंद्र सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए देश के समुद्र तट और अंतर्देशीय जलमार्गों का लाभ उठाने के लक्ष्य के साथ 2015 में सागरमाला पहल शुरू की थी। अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के साथ, सागरमाला को उत्पादों को स्थानांतरित करने की लागत और समय को कम करने, उद्योग और निर्यात / आयात वाणिज्य की मदद करने का अनुमान है। यह परियोजना बड़े पैमाने पर है, जिसमें 150 परियोजनाएं चार मुख्य क्षेत्रों में वितरित की गई हैं और कुल बजट 4 लाख करोड़ रुपये है। पहला, बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करना और छह नए बंदरगाहों को जोड़कर क्षमता का विस्तार करना। दूसरा, रेल कॉरिडोर, फ्रेट फ्रेंडली एक्सप्रेसवे और अंतर्देशीय जलमार्गों का निर्माण कर पोर्ट कनेक्शन को बढ़ाया जाए। तीसरा, मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में बंदरगाह के तहत औद्योगीकरण की अनुमति देने के लिए 14 तटीय आर्थिक क्षेत्र (सीईजेड) और उद्योग समूहों के साथ एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) का निर्माण। सूची में चौथे नंबर पर मछुआरों और अन्य तटीय और द्वीप के लोगों की क्षमताओं का विकास करना है।3

भारत सरकार ने अक्टूबर, 2017 में भारतमाला परियोजना चरण- I को लगभग 34,800 किमी (10,000 किमी अवशिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम सहित) की कुल लंबाई और अनुमानित परिव्यय 5,35,000/- करोड़ रुपये के साथ अनुमोदित किया था। इसके अलावा, भारतमाला परियोजना के दूसरे चरण की योजना पहले ही शुरू हो चुकी है, एनएचएआई ने दूसरे चरण के तहत 5,000 किलोमीटर नेटवर्क की पहचान की है।

भारतमाला परियोजना, राजमार्ग क्षेत्र के लिए एक कार्यक्रम है, जो आर्थिक गलियारों, इंटर कॉरिडोर के विकास और अन्य पहलों जैसे प्रभावी हस्तक्षेपों के माध्यम से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के अंतराल को पाटने के द्वारा देश भर में माल और यात्री आवाजाही की दक्षता को अनुकूलित करने पर केंद्रित है। जिसका लक्ष्य सुव्यवस्थित और विकसित सड़कों के रूप में देश में विकास करना है।

हमारे देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए 2016 में एकीकृत बाजारों में प्रक्रियाओं को सरल बनाने, खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सूचना विषमता को कम करने और वास्तविक मांग और आपूर्ति को पूरा करने, कृषि विपणन स्थिरता में सुधार के लिए ई-नाम बनाया गया था। कार्यक्रम का लक्ष्य पूरे देश में ई—नाम को एक ऑनलाइन बाजार मंच से जोड़ना था, जिससे कृषि वस्तुओं को अखिल भारतीय व्यापार की छूट मिलती है और उत्पाद की गुणवत्ता के साथ-साथ त्वरित ऑनलाइन भुगतान के आधार पर एक पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से बेहतर मूल्य प्राप्त होता है।

सागरमाला परियोजना की स्थिति

तब	अब
वित्त वर्ष 2014—15 में भारतीय बंदरगाहों द्वारा नियंत्रित यातायात की कुल संख्या 1052.1 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) थी।	भारतीय बंदरगाहों की वर्तमान कार्गो हैंडलिंग क्षमता अब 1,500 एमएमटीपीए है। साथ ही, बढ़ते यातायात को पूरा करने के लिए भारतीय बंदरगाह क्षमता को 2025 तक 3,300+ एमएमटीपीए तक बढ़ाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया है। इसमें बंदरगाह परिचालन क्षमता में सुधार, मौजूदा बंदरगाहों की क्षमता विस्तार और नए बंदरगाह विकास शामिल हैं। सागरमाला कार्यक्रम के तहत किए गए अध्ययनों के अनुसार 2025 तक भारतीय बंदरगाहों पर कार्गो यातायात लगभग 2,500 एमएमटीपीए होने की उम्मीद है।
पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी के कारणः उद्योगों तक माल पहुंचाने में हजारों करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आई है। देश के विकास की गति में दशकों तक इस क्षेत्र की वास्तविक क्षमता की अनदेखी की गई।	परियोजना उन्नति के तहत 12 प्रमुख बंदरगाहों के लिए दक्षता और उत्पादकता के प्रमुख प्रदर्शन सूचकांक (केपीआई) में सुधार के लिए वैश्विक बेंचमार्क अपनाए गए। दक्षता सुधार के माध्यम से 100 एमएमटीपीए से अधिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए 12 प्रमुख बंदरगाहों में लगभग 116 पहलों की पहचान की गई। जिनमें से 80 एमएमटीपीए से अधिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए 93 पहलों को लागू किया गया है पोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ाना पोर्ट आधारित औद्योगीकरण योजना सागरमाला के तहत औद्योगिक और समुद्री क्लस्टर स्थापित करने की योजना। विकास और मांग के अंतर को भरने के लिए महाराष्ट्र के वधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह की योजना।
बंदरगाहों के प्रशासन में सुधार दशकों से लंबित थे, जिसका विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ा। पुराने अधिनियमों और विनियमों ने भारतीय बंदरगाहों के विकास को प्रतिबंधित कर दिया था।	उद्योगों से सालाना करीब 40,000 करोड़ रुपये की बचत होगी। जीडीपी के 2% बढ़ने की उम्मीद है। 1 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सागरमाला परियोजना भारत में बुनियादी ढांचे में क्रांति ला रही है। देश के तटीय इलाकों में और बंदरगाहों के आसपास बेहतर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में छोटे शहरों में औसत व्यक्ति के लिए उड़ान को एक वास्तविकता बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। 'उड़ान' क्षेत्रीय विमानन उद्योग को विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। यह एक बाजार आधारित प्रणाली है जहां एयरलाइंस सीट सब्सिडी के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। अपनी तरह की इस वैश्विक पहल से सस्ती, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और आकर्षक क्षेत्रीय उड़ानों का सपना पूरा हो रहा है, जिससे छोटे क्षेत्रों में भी आम जनता के लिए उड़ान सुलभ हो गई है।

श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 2018 में 22,000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजारों (ग्राम) में पुनर्निर्मित करने और सुधारने की योजना की घोषणा की। इन ग्रामों में मनरेगा और अन्य सरकारी योजनाओं के माध्यम से भौतिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाया गया था। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने 2018 में 22000 ग्रामीण कृषि बाजारों (GrAMs) और 585 कृषि उपज बाजार समितियों (APMCs) में कृषि विपणन बुनियादी ढांचे के विकास और उन्नयन के लिए 2000 करोड़ रुपये के कोष के साथ एक कृषि-बाजार अवसंरचना कोष की स्थापना की घोषणा की।

स्वास्थ्य सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करने और अंतिम व्यक्ति तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने कई ऐप लॉन्च किए, जिनमें स्वस्थ भारत मोबाइल, लाभार्थी डेटा संग्रह के लिए एएनएम ऑनलाइन एप्लिकेशन (एएनएमओएल), गर्भावस्था के दौरान ऑडियो संदेशों के लिए किलकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल, ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली, और अन्य शामिल हैं।

21 फरवरी 2016 को माननीय प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) पहल का उद्घाटन किया। मिशन का लक्ष्य रूर्बन क्लस्टर्स स्थापित करना है, जो शहरी गांवों का एक समूह बनाकर इस क्षेत्र को और अधिक व्यापक रूप से विकसित करने में मदद करेगा, जो कि ग्रामीण सामुदायिक जीवन की भावना को बनाए रखने और बढ़ावा देने के साथ निष्पक्षता और समावेशिता पर जोर देता है, जो कि स्वाभाविक रूप से मानी जाने वाली सुविधाओं के साथ समझौता किए बिना है।

श्री मोदी के नेतृत्व में 2016 के रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम ने रियल एस्टेट निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ घर खरीदारों की सुरक्षा के लिए रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण की स्थापना की। रेरा क़ानून के तहत खरीदारों और निवेशकों के पैसे का कम से कम 70% एक अलग खाते में रखा जाएगा। इसके बाद इस पैसे का उपयोग केवल बिल्डरों द्वारा भवन और भूमि व्यय के लिए किया जाएगा। बिक्री समझौता पूरा होने से पहले डेवलपर्स और बिल्डर्स संपत्ति की लागत के 10% से अधिक अग्रिम भुगतान के रूप में नहीं मांग सकते हैं। बिल्डरों को उनके द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य के लिए मूल कागजात प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। बिल्डर्स को खरीदार की अनुमति के बिना ब्लूप्रिंट में संशोधन करने की अनुमति नहीं है।

भारत सरकार ने 2017 में श्री मोदी के नेतृत्व में हिमालयी क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्तर पूर्व विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना (एनईएसआईडीएस) को एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में मंजूरी दी। एनईएसआईडीएस नियमों के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को पानी की आपूर्ति, बिजली और कनेक्टिविटी जैसी भौतिक बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं के साथ-साथ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषण मिला। अब तक पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के लिए कुल 22 परियोजनाओं का केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषण किया गया है, जिनकी लागत 885.44 करोड़ है।

"सबका साथ, सबका विकास" पहल के बाद, सरकार ने भारतनेट जैसी ग्रामीण डिजिटल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ-साथ उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए पहल के माध्यम से डिस्कनेक्ट को जोड़ा। इसकी कल्पना एक सूचना सुपरहाइवे के रूप में की गई थी, जिसमें ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ने वाला एक शक्तिशाली बुनियादी ढांचा बनें। इसमें देश की सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ने और सभी ग्राम पंचायतों को 100 एमबीपीएस कनेक्शन प्रदान करने का प्रावधान किया गया, ताकि ग्रामीण इलाकों में ई-गवर्नेंस, ई-हेल्थ, ई-एजुकेशन,

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पूरी हुई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं
• पाक्योंग हवाई अड्डा (सिक्किम)
• रूपसी हवाई अड्डा (असम)
• लुमडिंग-होजई रेल लाइन दोहरीकरण (असम)
• 300 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना (अरुणाचल प्रदेश)
• 110 मेगावाट की पारे जल विद्युत परियोजना (अरुणाचल प्रदेश)
• मोरेह में आई.सी.पी
• मई 2021 तक सभी पूर्वोत्तर राज्यों को कवर करने वाली 1819 किमी सड़क परियोजना।
• अगरतला-सबरूम नई रेल लाइन परियोजना-112 किमी
• त्रिपुरा में गोमती नदी पर जलमार्ग
• ब्रह्मपुत्रा (असम) का बोगीबील पुल
• ढोला-सादिया पुल अरुणाचल प्रदेश के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा
• मेघालय में फूलबाड़ी और असम में धुबरी को जोड़ने वाले भारत के सबसे लंबे पुल की आधारशिला रखी गई
• जोरहाट जिले को असम के माजुली जिले से जोड़ने वाले दो लेन के पुल की आधारशिला रखी गई।
• भैरबी सैरंग रेलवे परियोजनाः मिजोरम राज्य में, राजधानी आइजोल में 51 किलोमीटर लंबी भैरबी सैरंग परियोजना के माध्यम से भारतीय रेलवे कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए, जिसके मार्च 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है।

ई-बैंकिंग, इंटरनेट और अन्य सेवाओं की डिलीवरी की जा सके।

भारतनेट की स्थिति

Usage

- No. of Gram Panchayat (GPs) for which agencies decided to install Wi-Fi/FTTH - **1,32,600**
- Wi-Fi Installed in GPs - **1,04,220**
- Wi-Fi Active in GPs - **64,798**
- No. of Wi-Fi/FTTH Users- **16,05,371**
- Total Data used per month - **4,430 TB**

भारत सरकार ने श्री मोदी के नेतृत्व में ई-जेल की शुरुआत की। यह एक सरकार द्वारा विकसित कार्यक्रम था जिसके तहत लंबे समय से प्रतीक्षित परिवर्तनों और छोटे अपराधों के आरोप में विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिए देश भर में सभी जेल डेटा को एकीकृत किया। राष्ट्रीय स्तर पर, साइबर अपराध के लिए एक शीर्ष समन्वय केंद्र स्थापित किया जा रहा था, और राज्यों को प्रत्येक जिले में ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अब तक इसका फैलाव 144 केंद्रीय जेलों तक किया जा चुका है, जिसमें 1193 जेल हैं, 5.1।4 लाख से अधिक कैदी, और 390 जिला जेल शामिल हैं।

श्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए देश भर में बाढ़ प्रबंधन कार्यों के साथ-साथ नदी प्रबंधन गतिविधियों और सीमा क्षेत्र के कार्यों के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (FMBAP)" को मंजूरी दे दी है। जिसके लिए 2019-20 में कुल 3342 करोड़ रुपये के परिव्यय का लक्ष्य रखा गया। यह योजना प्रभावी बाढ़ प्रबंधन, कटाव नियंत्रण और समुद्र विरोधी कटाव के लिए शुरू की गई थी। शहर, गाँव, औद्योगिक उद्यम, संचार संपर्क, कृषि क्षेत्र, बुनियादी ढाँचा और देश के अन्य क्षेत्रों को इस परियोजना से लाभान्वित किया गया, जो उन्हें बाढ़ और कटाव से बचाते हैं।

द्वीपों के समग्र विकास के लिए द्वीप विकास एजेंसी के बैनर तले 2017 में पहचाने गए द्वीपों में सतत विकास की पहल शुरू की गई थी। नीति आयोग को स्थायी तरीके से द्वीपों के समग्र विकास का मार्गदर्शन करने का काम सौंपा गया था।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई पुलों का उद्घाटन किया गया और जनता के लिए खोल दिया गया। जलमार्गों पर रो-रो सेवाएं चालू हो गईं। ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे लंबे रेल-सह-सड़क पुल बोगीबील रेल—सह—सड़क पुल का उद्घाटन किया गया। नए हवाई अड्डों को मंजूरी और उद्घाटन किया गया है।

रसद की लागत को कम करने के लिए भारत सरकार ने 33,000 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ देश भर के 15 स्थानों में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। 2017 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और तमिलनाडु सरकार ने इनमें से एक पार्क के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रस्तावित लॉजिस्टिक्स पार्कों का उद्देश्य कुल माल ढुलाई लागत में कटौती करना, वाहन प्रदूषण और भीड़भाड़ को कम करना और वेयरहाउसिंग खर्च को कम करना है। उल्लेखनीय है कि योजना को आगे बढ़ाने के लिए गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा जा रहा है।

समर्पित फ्रेट कॉरिडोर - श्री मोदी के नेतृत्व में आर्थिक विकास में यह एक गेम चेंजर साबित होगा, जिसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विकास की गति को बढ़ाने के लिए पश्चिमी डीएफसी (1506 रूट किमी) और पूर्वी डीएफसी (1875 रूट किमी) का निर्माण कर रहा है। डीएफसी की 2021 तक की उपलब्धियां नीचे दी गई हैं।

माल ढुलाई राजस्व का विवरण

Year	Freight (in Million Tonnes)	Freight Revenue (in Crores)
2017-18	1159.55	Rs. 1,17,055.40
2018-19	1221.48	Rs. 1,27,432.72
2019-20	1208.41	Rs. 1,13,487.89

जिले के समग्र विकास को बढ़ाने और लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए जनवरी 2018 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 'आकांक्षी जिलों का परिवर्तन' पहल शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य जिलों में तेजी से और कुशलता से सुधार करना था। कार्यक्रम के माध्यम से जिलों से आग्रह किया गया और प्रोत्साहित किया गया कि वे अपने राज्य में सर्वश्रेष्ठ जिले की पहचान करें, और फिर प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद की भावना में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करके और उनसे सीखकर देश में सर्वश्रेष्ठ में से एक बनने का लक्ष्य रखें।

श्री मोदी के नेतृत्व में फ्लेक्सी-फंड के माध्यम से 700 करोड़ रुपये की लागत से देश के 115 आकांक्षी जिलों में स्वजल कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इन परियोजनाओं का लक्ष्य बस्तियों में सौर ऊर्जा से चलने वाले पाइप से पानी पहुंचाना था। यह शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक सामुदायिक मांग संचालित, विकेन्द्रीकृत योजना है। परियोजना के हिस्से के रूप में सैकड़ों ग्रामीण तकनीशियनों को स्वजल उपकरणों के संचालन और रखरखाव के लिए प्रशिक्षित किया गया था।

श्री मोदी के नेतृत्व में 2022 तक 462 एकलव्य स्कूलों के चालू होने की उम्मीद है, जो पूरे भारत में 20,000 आदिवासी लोगों की सेवा कर रहे हैं। 2022 तक पूरे भारत में 163 आदिवासी बहुल जिलों में 5 करोड़ रुपये की लागत से खेल सुविधाओं का निर्माण होने की उम्मीद है।

विश्व जैव ईंधन दिवस 2018 के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने एकल-विंडो एकीकृत पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 'परिवेश' का शुभारंभ किया। जिसका उद्देश्य 'डिजिटल इंडिया' पहल और न्यूनतम सरकार और व्यापक आर्थिक विकास के सार को कैप्चर करना है।

यह एक वेब-आधारित, भूमिका-आधारित वर्कफ़्लो टूल है, जो केंद्र, राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों से पर्यावरण, वन, वन्यजीव और सीआरजेड मंजूरी की मांग करने वाले लोगों द्वारा दायर प्रस्तावों की ऑनलाइन प्रस्तुति और निगरानी के लिए बनाया गया था।

यात्रियों और आम जनता को डिजिटल सिस्टम से जोड़ने के लिए 6053 रेलवे स्टेशनों को वाई-फाई सक्षम किया गया है।

किसी भी देश का विकास उसके परिवहन नेटवर्क पर निर्भर करता है और उनका रखरखाव कितनी अच्छी तरह से किया जाता है। आर्थिक गलियारों, इंटर कॉरिडोर और फीडर रूट्स, नेशनल कॉरिडोर दक्षता में सुधार, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी सड़कों, तटीय और पोर्ट कनेक्टिविटी रोड, और ग्रीन-फील्ड एक्सप्रेसवे के लक्ष्यों के साथ भारतमाला परियोजना शुरू की गई थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में कहा था कि भारत 2030 तक 23 नहरों का संचालन करना चाहता है, बाकी दुनिया को देश के आर्थिक प्रक्षेपवक्र में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। उन्होंने कहा कि मुख्य बंदरगाह की क्षमता 2014 में 870 मिलियन टन से बढ़कर वर्तमान में 1550 मिलियन टन हो गई है। प्रधानमंत्री के अनुसार पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय ने 400 परियोजनाओं की एक सूची तैयार की है जिन्हें वित्त पोषित किया जा सकता है। इन परियोजनाओं में 31 अरब डॉलर (2.25 लाख करोड़ रुपये) की निवेश क्षमता है। उल्लेखनीय है कि 2019 तक 13 जलमार्गों का संचालन प्रारंभ किया जा चुका है।

सामाजिक-आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने 'स्वामित्व' योजना शुरू की। 'स्वामित्व' के तहत केंद्र सरकार ने छह राज्यों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक के 763 गांवों में 1.32 लाख संपत्ति कार्ड वितरित करने का लक्ष्य रखा है।

देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की बुनियादी समझ पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 'एआई फॉर ऑल' पहल की शुरुआत की। कार्यक्रम सीबीएसई और इंटेल इंडिया द्वारा संचालित किया गया था जो 4 घंटे का स्व-पुस्तक, सूक्ष्म-शिक्षण कार्यक्रम है।

सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (पीडीओ) के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से पीएम वानी योजना के ढांचे को दिसंबर 2020 में मंजूरी दी गई थी। इस योजना का उद्देश्य न केवल "ईज ऑफ डूइंग" को बढ़ावा देना है, बल्कि यह "ईज ऑफ लिविंग" भी करेगा। जिसमें पीडीओ के लिए कोई लाइसेंस, कोई पंजीकरण और कोई शुल्क लागू नहीं होगा, जो कि छोटी दुकानें या कॉमन सर्विस सेंटर भी हो सकते हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में सहकारी प्रशासन को सिंक्रनाइज़ और व्यवस्थित करने के लिए एक अलग 'सहकारिता मंत्रालय' बनाकर ऐतिहासिक कदम उठाया जो देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा।

पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) में ई-गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए ई-ग्राम स्वराज, पंचायती राज के लिए एक सरलीकृत कार्य आधारित लेखा आवेदन शुरू किया गया। ई-ग्रामस्वराज पंचायती राज संस्थाओं को अधिक से अधिक धनराशि के हस्तांतरण के माध्यम से पंचायत की विश्वसनीयता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह विकेंद्रीकृत योजना, प्रगति रिपोर्टिंग और कार्य-आधारित लेखांकन के माध्यम से बेहतर पारदर्शिता लाता है। इसके अलावा, एप्लिकेशन उच्च अधिकारियों द्वारा प्रभावी निगरानी के लिए एक मंच प्रदान करता है।

देश की सीमा के बुनियादी ढांचे को नई ताकत प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में 3,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर अटल सुरंग का उद्घाटन किया, जो दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है और मनाली को लाहौल-स्पीति घाटी से जोड़ती है। यह लाहौल-स्पीति की लैंडलॉक घाटी के

लिए हर मौसम में संपर्क प्रदान करती है, जो पहले साल में लगभग छह महीने तक बंद रहता था क्योंकि रोहतांग दर्रा नवंबर और अप्रैल के बीच आमतौर पर बर्फ से ढका रहता था। यह परियोजना हिमालय के पीर पंजाल रेंज में 3000 मीटर (10,000 फीट) की ऊंचाई पर अति-आधुनिक विनिर्देशों के साथ बनायी गयी है।

भारतमाला परियोजना चरण 2.0 को श्री मोदी के नेतृत्व में शुरू किया गया था, जिसकी अनुमानित लागत रु 5.35 लाख करोड़ रुपये है। इस परियोजना के माध्यम से प्रभावी हस्तक्षेपों कर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के अंतराल को पाटने और देश भर में माल और यात्री आवाजाही की दक्षता को अनुकूलित करने का लक्ष्य रखा गया है।

मेट्रो-रेल के विकास में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सभी उप प्रणालियों के मानकीकरण और स्वदेशीकरण की योजना बनाई, सभी मेट्रो रेल घटकों ने स्वदेशी खरीद को बढ़ावा दिया। इसके अलावा दो नई तकनीकों 'मेट्रो नियो' और 'मेट्रोलाइट' को विकसित किया जाना है ताकि टियर -2 शहरों और टियर -1 शहरों में बहुत कम लागत से मेट्रो रेल सिस्टम उपलब्ध कराया जा सके।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण की दृष्टि से प्रधानमंत्री ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (सीएएनआई) के लिए केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य ऑनलाइन शिक्षा, टेली-मेडिसिन, बैंकिंग प्रणाली, ऑनलाइन व्यापार और पर्यटन की सुविधा में सुधार के साथ-साथ सस्ती और बेहतर कनेक्टिविटी प्राप्त करना है।

उत्तर-पूर्वी राज्यों की स्थिति को मजबूत करने की दृष्टि से श्री मोदी के नेतृत्व में कई योजनाओं को शामिल किया गया।

2014 में दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के व्यापार में एक महत्वपूर्ण मंदी को देखते हुए केंद्र सरकार ने दूरगामी एक्ट ईस्ट पॉलिसी (एईपी) शुरू की, जिसका उद्देश्य दक्षिण, दक्षिणपूर्व और पूर्वी एशिया के देशों के साथ आर्थिक एकीकरण को बढ़ाना देना है। राजनीतिक रुख के बावजूद एईपी ने पूर्व में कामयाबी हासिल की। एईपी को शुरुआत से ही वाणिज्य और कनेक्टिविटी के व्यापक क्षेत्रों में बहुआयामी तरीके से आगे बढ़ाया गया है। उत्तर-पूर्व को सुदृढ़ बनाने का भारत सरकार का संकल्प, उत्तर-पूर्व के संबंध में किए गए कार्यों से स्पष्ट है।

श्री मोदी के मजबूत नेतृत्व में भारत सरकार उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास के अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है, जिसके लिए उसने अपने आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम के तहत इन क्षेत्रों के कई जिलों की पहचान की है, जिसमें बारपेटा, बक्सा, दरांग, धुबरी, ममित, किफिर, धलाई, पश्चिम सिक्किम, चंदेल आदि शामिल हैं। सरकार इसके विकास के लिए निरंतर काम कर रही है।

देश का रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य होने के बावजूद अरुणाचल प्रदेश में सड़कों का घनत्व सबसे कम है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ट्रांस-अरुणाचल राजमार्ग परियोजना में तेजी लाने की योजना बना रहा है। मंत्रालय 2,319 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले सड़कों और राजमार्गों के विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम चलाएगा।

जल जीवन मिशन, श्री मोदी के नेतृत्व में 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति करने के लिए शुरू किया गया था। यह सभी ग्रामीण भारतीय घरों के लिए है। इसके तहत भूजल प्रबंधन, जल संरक्षण और वर्षा जल संग्रहण के माध्यम से पुनर्भरण और पुनः उपयोग जैसे कार्यक्रमों को लागू करना है। जल जीवन मिशन एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार के साथ पानी के लिए एक समुदाय आधारित दृष्टिकोण पर बनाया जाएगा। जेजेएम के माध्यम से पानी को लेकर एक जन आंदोलन शुरु करने का लक्ष्य है, जो इसे सभी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बना देगा।

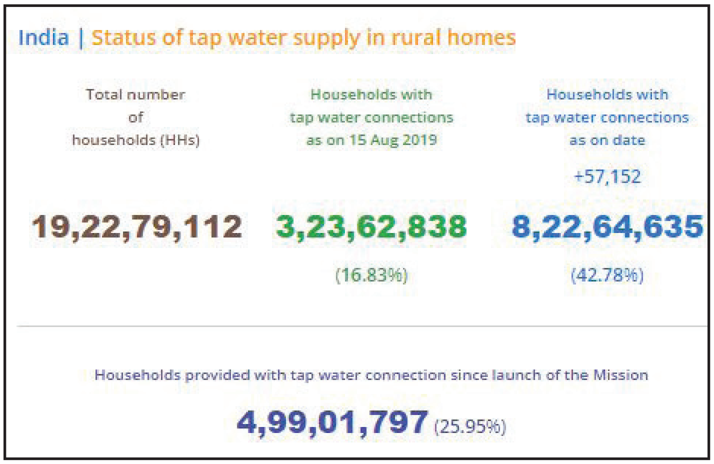

चित्र 4 जल जीवन मिशन डैशबोर्ड, 26 सितंबर 2021

एक संपन्न अर्थव्यवस्था के पीछे सबसे आवश्यक तत्वों 'नवाचार' है। भाजपा के घोषणापत्र के अनुसार आर्थिक और सामाजिक महत्व के क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा, विशेष रूप से वाणिज्यिक और सार्वजनिक संगठनों के बीच घनिष्ठ और उपयोगी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि (मिट्टी, जल प्रबंधन, मानव और पशु पोषण, और मत्स्य पालन सहित), जल,

स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, ऊर्जा (नवीकरणीय ऊर्जा सहित), संचार और परिवहन सभी पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) को 2021-22 से शुरू होने वाले अगले चार वर्षों की अवधि के लिए 1 अप्रैल 2021 से अनुमोदित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य स्टार्टअप को अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। भारत भर में पात्र इन्क्यूबेटरों के माध्यम से योग्य स्टार्टअप्स को सीड फंडिंग प्रदान करने के लिए अगले चार वर्षों में 945 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान है। इस योजना से लगभग 3600 स्टार्टअप को समर्थन मिलने की उम्मीद है।

सरकार ने दो नई आईटी पहलों 'ICEDASH' और 'ATITHI' का अनावरण किया। आयातित सामानों की सीमा शुल्क निकासी की निगरानी और गति में सुधार करने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की सीमा शुल्क निकासी और मुद्रा घोषणाओं के इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग द्वारा अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की सुविधा के लिए और अंतरराष्ट्रीय कार्गो की सीमा शुल्क निकासी को सुलभ बनाने के लिए इनकी शुरुआत की गयी है ICEDASH एक भारतीय सीमा शुल्क ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है जो जनता को दैनिक आयात कार्गो सीमा शुल्क निकासी समय का निरीक्षण करने की सहुलियत देता है। ATITHI एक साधारण स्मार्टफोन ऐप है जो विदेशी यात्रियों को समय से पहले अपनी सीमा शुल्क घोषणाएं जमा करने को सुलभ बनाता है। ◆

•	भारत सरकार ने बेंगलुरु में एक AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क (ARTPARK) की स्थापना की है जो AI और रोबोटिक्स में प्रौद्योगिकी नवाचारों को बढ़ावा देगा, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा, गतिशीलता, बुनियादी ढांचे, कृषि, खुदरा, साइबर सुरक्षा में महत्वाकांक्षी मिशन मोड शोध परियोजनाओं को क्रियान्वित करके सामाजिक बदलाव लाएगा।
•	एससी, एसटी और महिला उद्यमियों को स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से समर्थन दिया जा रहा है, जिसे वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है। 23 मार्च 2021 तक, स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत योजना की शुरुआत से अब तक 1,14,322 से अधिक खातों में 25,586 करोड़ रुपये मंजूर किए जा चुके हैं। अनुसूचित जाति के लिए 3335.87 करोड़ रु. एसटी के लिए 1049.72 करोड़, और महिलाओं के लिए 21200.77 करोड़ की मंजूरी दी गयी है।
•	इसके अलावा, नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड (एनईवीएफ), जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पहला और एकमात्र समर्पित वेंचर फंड है, को भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने इस क्षेत्र में व्यावसायिक उद्यमों और कौशल विकास के विकास को बढ़ावा देने के इरादे से लागू किया है।
•	लॉकडाउन अवधि के दौरान पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने उद्योग और पर्यटकों के साथ अपने निरंतर जुड़ाव के रूप में 'देखो अपना देश' के समग्र विषय पर वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार श्रृंखला का उद्देश्य भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों के बारे में जागरूकता पैदा करना और उन्हें बढ़ावा देना था, जिसमें कम-ज्ञात गंतव्य और लोकप्रिय स्थलों के कम-ज्ञात पहलू शामिल थे।

राष्ट्र निर्माण

(आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम)

देश और उसके नागरिकों को सही अर्थों में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मानबीर भारत (आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया और मई 12, 2020 में राष्ट्र के नाम अपने भाषण के दौरान इस पर जोर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। जब उन्हें कोविड -19 महामारी के दौरान इसी तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वहीं उन्होंने गुजरात को सबसे महान राज्यों में से एक बनाने में अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया और 2001 के विनाशकारी भूकंप के बाद देश को आत्मनिर्भर होने की राह पर ले जाने के लिए निवेश किया। आत्मानिर्भर भारत के पांच स्तंभों की पहचान करते हुएः अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, प्रणाली, जनसांख्यिकी और मांग पर जोर देने को कहा, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब हमारे स्थानीय उत्पादों को ग्लोबल करने का समय आ गया है सरकार ने इस अभियान के लिए एक अनूठे आर्थिक पैकेज को मंजूरी दी है जो कुटीर उद्योग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), मजदूरों, मध्यम वर्ग और उद्योगों सहित विभिन्न समूहों की मदद करेगा। यहां, हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के उन कदमों और प्रयासों पर एक नज़र डालेंगे जो भारत के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से उठाए गए थे।

आत्मनिर्भर गुजरात

भारत में विदेशी निवेश के लिए गुजरात को एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से, राज्य और राष्ट्र के समग्र विकास के लिए वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन 2003 में शुरू किया गया था। यह विस्तृत कार्यक्रम निवेश और पर्यटन को बढ़ावा

देने के उद्देश्य से साल 2003 शुरु किया गया।

2003 में शुरू हुए वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में बिजली, तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स, पर्यटन, जैव प्रौद्योगिकी, कृषि-खाद्य जैसे विविध क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन, आईईएम और ठोस व्यावसायिक योजनाओं के रूप में सरकार ने 55,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को पंजीकृत किया गया था। जिसमें अनुसंधान, रत्न और आभूषण और तकनीकी शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल थे। तब से शिखर सम्मेलन का विकास जारी है और यह अधिक एफडीआई लाने में सफल रहा है।

2004 की विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नीति श्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्यात-उन्मुख औद्योगिक परिक्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी। नतीजतन, मुंद्रा एसईजेड और बंदरगाह परियोजना में लगभग 20,000 करोड़ रुपये का निवेश आया, जिससे लगभग 150,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा हुआ। गुजरात को एक आकर्षिक निवेश राज्य के तौर पर बदलने के लिए सरकार ने व्यवसाय-समर्थक दृष्टिकोण को अपनाया और इसलिए राज्य में व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार के सिद्धांत की सराहना की जाती है।

गुजरात एक सूखाग्रस्त क्षेत्र होने के कारण सिंचाई और यहां तक कि पीने के लिए पानी की कमी का सामना कर रहा था। लेकिन, राज्य सरकार के दूरंदेशी दृष्टिकोण और नर्मदा नहर के पानी ने गुजरातियों के परिदृश्य और जीवन को बदल दिया। कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र में पानी की कमी को समाप्त करने के लिए गुजरात सरकार ने 2011 में स्वर्णिम गुजरात सौराष्ट्र-कच्छ जल ग्रिड परियोजना शुरू की। इस योजना के तहत 400 किलोमीटर से अधिक लंबाई की पाइपलाइनें बिछाई जानी थीं, जो हैं;

(1) 150 किमी की पाइपलाइन। धनकी से रतनपुर (राजकोट)

(2) 134 कि.मी. मालिया शाखा नहर के समानांतर धनकी से मालिया तक लंबी पाइपलाइन।

(3) 90 किमी धनकी से नवादा तक लंबी पाइपलाइन वल्लभीपुर शाखा नहर के समानांतर।

(4) 30 किमी की पाइपलाइन मालिया और ध्रांगध्रा शाखा नहर पर।

इतना ही नहीं, उन्होंने जनताा, पानी समितियों और जल उपयोगकर्ता संघों को शिक्षित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को शामिल करके जल संरक्षण, ड्रिप-सिंचाई और मौजूदा नहरों को मजबूत करने को भी प्रोत्साहित किया। इस संबंध में गुजरात सरकार की उपलब्धि झीलों के किनारों तक भरे पानी के नजारे से नजर आती हैं और जिन लोगों ने कुओं से पानी लेने के लिए संघर्ष किया, उनके पास अब नलों से पानी आ रहा है। इसके एक अन्य प्रभावी कदम के रूप में गुजरात के कृषि क्षेत्र में 9% से अधिक की वृद्धि हुई, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

गुजरात सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कन्या केलवनी निधि (2011) और विद्या लक्ष्मी योजना (2002) जैसी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा महिला सशक्तिकरण को भी प्राथमिकता दी। राज्य ने पिछले कुछ वर्षों में संस्थागत प्रसव की प्रवृत्ति में निरंतर वृद्धि को देखा है और इसके परिणामस्वरूप होम डिलीवरी की प्रवृत्ति में कमी आई। वर्ष 2005—06 में संस्थागत प्रसव की दर 63.24% थी जो चिरंजीवी योजना (2005) के कारण मार्च-2018 तक 99% तक पहुंच गई। मिशन मंगलम (2010) के माध्यम से सखी मंडलों को कॉर्पोरेट मूल्य श्रृंखला में जोड़ा गया है जिससे हितधारकों को लाभ हुआ है। मिशन मंगलम महिलाओं को उनकी आजीविका कमाने और स्वतंत्र होने में मदद कर रहा है। वर्ष 2013-14 में शहरी मिशन मंगलम के तहत सखी मंडलों को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। मुख्यमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के समावेशी और समग्र विकास के इच्छुक थे। उनके द्वारा शुरू की गई योजनाओं ने हर क्षेत्र पर जोर दिया और इससे जबरदस्त विकास हुआ।

गुजरात के कच्छ जिले में टुंडा वंधा मिट्टी से निर्मित घर वाला एक समान्य गांव था, जिसे पशुपालकों का गांव भी कहा जाता था। जो एक सामान्य गांव से एक समृद्ध औद्योगिक शहर में तब्दील हो गया है, जिसमें भारत की दो सबसे बड़ी कोयले से चलने वाली बिजली परियोजनाएं हैं। जिनकों टाटा पावर कंपनी लिमिटेड- इसकी सहायक कंपनी कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड (सीजीपीएल) और अदानी पावर लिमिटेड संचालित करती है। इन परियोजनाओं के आने से गांव में रोजगार सृजन हुआ, जिससे गांव की आय में वृद्धि हुई।

'आत्मनिर्भरता' की ओर- आत्म निर्भर भारत

मेक इन इंडिया

'मेक इन इंडिया' 25 सितंबर, 2014 को शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना, सर्वोत्तम श्रेणी के बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का केंद्र बनाना है। एक मजबूत विनिर्माण क्षेत्र का विकास भारत सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है। वहीं 'वोकल फॉर लोकल' जैसी पहलों ने भारत के विनिर्माण क्षेत्र को दुनिया के सामने उजागर किया। इस क्षेत्र में न केवल आर्थिक विकास को उच्च पथ पर ले जाने की क्षमता है बल्कि हमारे युवा श्रम बल के एक बड़े पूल को रोजगार प्रदान करने की भी क्षमता है।

भारत ने पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 2014-2015 में 45.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 81.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अनंतिम आंकड़ा) का अपना अब तक का उच्चतम वार्षिक एफडीआई प्रवाह दर्ज किया है। पिछले सात वित्तीय वर्षों (2014-20) में, भारत ने 440.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई प्रवाह प्राप्त किया है जो कि पिछले 21 वर्षों में रिपोर्ट किए गए एफडीआई का 58% है (763.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर)

मौजूदा प्रक्रियाओं का सरलीकरण देश में व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने के लिए किए गए उपाय हैं। नतीजतन, भारत विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (डीबीआर) 2020 के अनुसार 63वें स्थान पर पहुंच गया है, जो एक व्यवसाय शुरू करने, करों का भुगतान करने, सीमाओं के पार व्यापार करने और दिवाला समाधान के क्षेत्रों में सुधारों के कारण हुआ है।

हाल ही में सरकार ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, कॉरपोरेट टैक्स में कमी, एनबीएफसी और बैंकों की तरलता की समस्याओं को कम करने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत उपायों की शुरुआत की है। भारत सरकार ने सार्वजनिक खरीद आदेशों, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी), विभिन्न मंत्रालयों के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए योजनाओं के माध्यम से माल के घरेलू विनिर्माण को भी बढ़ावा दिया है।

इसके अलावा भारत में निवेश करने वाले निवेशकों को समर्थन, सुविधा और निवेशकों के अनुकूल वातावरण प्रदान करने की दृष्टि से सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में निवेश में तेजी लाने के लिए सचिवों के एक अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) और परियोजना विकास प्रकोष्ठों (पीडीसी) का गठन किया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच समन्वय, जून 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसका उद्देश्य एफडीआई प्रवाह को बढ़ाने के लिए भारत में निवेश योग्य परियोजनाओं के विकास को सुविधाजनक बनाना है।

श्रम सुधार

श्रम सुधारों का उद्देश्य बदलते कारोबारी माहौल के अनुकूल एक पारदर्शी प्रणाली प्रदान करना है। दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में सरकार ने 2014 से बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए हैं और 'श्रमेव जयते' और 'सत्यमेव जयते' को समान महत्व दिया है।

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 तीन पूर्ववर्ती कानूनों- ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926, औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की विशेषताओं को समायोजित करता है। छंटनी या बंदी के लिए किसी फर्म को मौजूदा प्रावधान 100 बढ़ाकर 300 श्रमिकों कर दिया गया है, जिससे रोजगार सृजन में वृद्धि और व्यवसायों के विस्तार जैसे फायदे होंगे।

कोड ने ट्रिब्यूनल से संबंधित प्रावधानों को सरल बना दिया है, जैसे कि औद्योगिक ट्रिब्यूनल में एक सदस्य के बजाय दो सदस्यों का प्रावधान, जिससे एक सदस्य की अनुपस्थिति में काम सुचारू रहे, मामले को सीधे ट्रिब्यूनल में ले जाना, ट्रिब्यूनल के आदेश के 30 दिनों में सुलह या कार्रवाई की जाए।

ट्रेड यूनियनों की बेहतर और प्रभावी भागीदारी के उद्देश्य से बातचीत के माध्यम से किसी भी विवाद का हल 'निगोशिएटिंग यूनियन' और 'नेगोशिएटिंग काउंसिल' का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कानून में पहली बार री-स्किलिंग फंड का प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य उन श्रमिकों को फिर से कुशल बनाना है जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, जिसमें 45 दिनों की अवधि के भीतर 15 दिनों के वेतन का प्रावधान है।

आत्मनिर्भर भारत

'आत्मानिर्भर भारत' एक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया कदम है, जो बाजार की ताकतों के बीच की खाई को पाटता है। मांग और आपूर्ति और आयातित वस्तुओं और सेवाओं पर निर्भरता को कम करताह है। एक नए भारत की दृष्टि को आत्मनिर्भर भारत को पांच स्तंभों द्वारा रेखांकित किया गया हैः अर्थव्यवस्था, बुनियादी

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता, 2020 राज्य सरकार को अधिक आर्थिक गतिविधि और रोजगार पैदा करने के लिए किसी भी नए कारखाने को संहिता के प्रावधानों से छूट देने का अधिकार देती है। इसमें एक निश्चित आयु से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए नियोक्ता द्वारा सालाना निःशुल्क स्वास्थ्य जांच का प्रावधान भी शामिल है, श्रमिकों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का कानूनी अधिकार और साथ ही दृश्य-श्रव्य श्रमिकों के रूप में सिने श्रमिकों का पदनाम भी शामिल है। प्रति वर्ष प्रत्येक 20 दिनों के काम के लिए एक दिन की छुट्टी प्रदान की जानी चाहिए और काम करने की स्थिति स्वच्छ और सुरक्षित होनी चाहिए।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं को तैयार करने का प्रावधान करती है। इन योजनाओं को लागू करने के लिए वित्तीय पक्ष पर एक "सामाजिक सुरक्षा कोष" बनाया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा के दायरे में "प्लेटफॉर्म वर्कर या गिग वर्कर" जैसी बदलती तकनीक के साथ बनाए गए रोजगार के नए रूपों को लाने के लिए कोड की कल्पना सामाजिक सुरक्षा संहिता में की गई है। भारत उन गिने-चुने देशों में से एक है जहां श्रमिकों को इस श्रेणी में सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का यह अभूतपूर्व कदम उठाया गया है। इसके अलावा, न्यूनतम सेवा अवधि के लिए बिना किसी शर्त के निश्चित अवधि के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी का प्रावधान किया गया है।

वेतन पर संहिता, 2019 ने सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन और समय पर वेतन भुगतान के प्रावधानों को सार्वभौमिक बना दिया, भले ही क्षेत्र और वेतन सीमा कुछ भी हो। यह प्रत्येक कर्मचारी के लिए "निर्वाह का अधिकार" सुनिश्चित करेगा और न्यूनतम मजदूरी के विधायी संरक्षण को मौजूदा लगभग 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया है।

- "नए श्रम सुधार हमारी श्रम शक्ति के जीवन को बदल देंगे। अभी तक केवल 30 प्रतिशत श्रमिकों के पास न्यूनतम मजदूरी गारंटी का कवरेज था। अब, यह असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों तक विस्तारित होगा"।

  प्रधानमंत्री

- हमारे श्रमबल को दशकों तक जटिल कानूनों के जाल में फंसा कर रखा गया था। नए श्रम संहिता उन्हें इससे मुक्त कर देंगे। श्रमिकों को अब उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, समानता और गरिमा के संबंध में कानूनी रूप से संरक्षित किया जाएगा।
- नए सुधारों के तहत संगठित और असंगठित करीब 50 करोड़ को अब समय पर वेतन मिलेगा। हमने मौजूदा 10,000 स्लैब को न्यूनतम मजदूरी से घटाकर लगभग 200 स्लैब कर दिया है। नया सुधार श्रम कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करेगा, महिला कार्यबल के लिए समानता लाएगा, अधिक रोजगार पैदा करेगा, और संगठित क्षेत्र का भी विस्तार करेगा।

ढांचा, प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली, जनसांख्यिकी और मांग। अभियान का उद्देश्य भारत को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार करना है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय व्यापार को पुनर्जीवित करने के लिए तीन चरणों में आत्मनिर्भर भारत पैकेज की शुरुआत की। भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 10% के बराबर 20 लाख करोड़ रुपये का विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज कोविड -19 महामारी से लड़ने के लिए 12 मई 2020 को घोषित किया गया था। वैश्विक लड़ाई में भारत द्वारा निभाई गई अनुकरणीय भूमिका को व्यापक रूप से मान्यता और सराहना मिली। भारत ने दृढ़ता और आत्मनिर्भरता की भावना के साथ कोविड-19 स्थिति का सामना किया है, इस तथ्य से स्पष्ट है कि मार्च 2020 से पहले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) के शून्य उत्पादन से भारत आज 2 लाख पीपीई किट प्रतिदिन उत्पादन करने की क्षमता रखता है, जो लगातार बढ़ भी रहा है।

आत्म निर्भर भारत अभियान ने एक हद तक महामारी के झटके को झेला और संकट के खिलाफ एक रक्षा तंत्र के रूप में काम किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 2021-22 के बजट भाषण में 13 चिन्हित क्षेत्रों के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI), (2021) योजना के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय की घोषणा की। जिसका उद्देश्य सरकार की आत्मानिर्भर भारत पहल के तहत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह योजना आयात खर्चो को कम करने और स्थानीय वस्तुओं की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा कंपनियों को अपने घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने के

लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। पीएलआई योजना भारत में निर्मित उत्पादों के लिए वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन प्रदान करती है।

खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान देने के साथ तिलहन और पाम तेल के क्षेत्र और उत्पादकता बढ़ाने के लिए खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है। कोविड-19 से उभर रहे भारत में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू की गई है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सरकार की ओर से उन सभी प्रतिष्ठानों को सब्सिडी दी जाएगी जो नई भर्तियां करेंगे। यह उन लोगों को सहायता प्रदान करेगा जिन्होंने कोरोना काल के कारण अपना रोजगार खो दिया था।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) जिन्हें लोकप्रिय रूप से एमएसएमई कहा जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। यह देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में चुपचाप काम करते हुए, 6 करोड़ से अधिक एमएसएमई की एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। इन छोटे आर्थिक इंजनों का देश के सकल घरेलू उत्पाद पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिसमें 29% का योगदान होता है। वे देश से लगभग आधे निर्यात में योगदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, एमएसएमई क्षेत्र में 11 करोड़ से अधिक लोग कार्यरत हैं। 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' (आत्मनिर्भर भारत अभियान) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को विशेष जोर देते हुए देश में व्यापार और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एमएसएमई भारत में प्रमुख रोजगार-सृजन खंड के रूप में उभरे हैं और हमारे विकासशील राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से स्थिर विकास दिया है। एमएसएमई पर जीएसटी का जबरदस्त असर रहा है।

उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट और 13 उपकर जैसे 17 मौजूदा अप्रत्यक्ष करों को शामिल करने और बदलने के लिए राष्ट्रव्यापी माल और सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था 2017 में शुरू की गई थी। जीएसटी भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक मील का पत्थर रहा है। इसने आम आदमी पर करों की संख्या, अनुपालन बोझ और समग्र कर बोझ को कम किया है, जबकि पारदर्शिता, अनुपालन और समग्र संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा जीएसटी जैसे बड़े सुधार करने के बाद भारी बहुमत के साथ फिर से निर्वाचित होने वाली दुनिया की पहली पार्टी बन गयी।

देश में खादी, ग्राम और कॉयर उद्योग के तहत संचालित एमएसएमई के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

बाजार संवर्धन एवं विकास योजना (एमपीडीए)

पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए निधि की पुर्नोत्थान योजना (SFURTI) -

कॉयर विकास योजना (CVY)

निर्यात बाजार संवर्धन (ईएमपी)

घरेलू बाजार संवर्धन (डीएमपी)

व्यापार और उद्योग से संबंधित कार्यात्मक सहायता सेवाएं (टीआईआरएफएसएस)

कल्याणकारी उपाय (प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

इसके अलावा, जेड प्रमाणन योजना में एमएसएमई को वित्तीय सहायता - जो 'मेक इन इंडिया' को आगे बढ़ाता है। इस योजना का उद्देश्य भारतीय एमएसएमई द्वारा किए गए निर्माण में शून्य दोष और शून्य प्रभाव (ZED) प्रथाओं को शामिल करना है। इस योजना के तहत, भारत सरकार (जीओआई) एमएसएमई को 80% तक सब्सिडी प्रदान करती है।

कोविड -19 महामारी ने एमएसएमई क्षेत्र को प्रभावित किया, जिससे उनकी कमाई का 20-50% कम हो गया. इस संबंध में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक राहत पैकेज की शुरुआत की, 15 उपायों में से 6 पूरी तरह से एमएसएमई को सशक्त बनाने पर केंद्रित थे अर्थातः

एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव

क्रेडिट और वित्त योजना

इक्विटी भागीदारी के लिए निधियों का आवंटन

अनर्जक संपत्ति में राहत

एमएसएमई का बकाया चुकाना

वैश्विक निविदाओं को अस्वीकार करना

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (पीएफएफएमई), 2021

एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और क्षेत्र की औपचारिकता को बढ़ावा देना तथा किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह और उत्पादक सहकारी समितियाँ अपनी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को सहायता प्रदान करना है। इसके लिए 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपये का का प्रावधान किया गया है, मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए 2,00,000 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की सीधे सहायता करने की योजना है। ◆

नागरिकों का सशक्तिकरण

(व्यवस्था में अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना)

लोकतंत्र की जड़ अपने नागरिकों के हितों और आकांक्षाओं में निहित होती है। अन्य लोकतंत्रों के विपरीत, भारतीय संविधान अपने लोगों को राष्ट्र के 'संप्रभु' के रूप में परिभाषित करता है। यूपीए शासन के 10 वर्षों के बाद, जिसके दौरान देश ने आजादी के बाद से सबसे भ्रष्ट शासन देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन का एक पारदर्शी बेंचमार्क बनाए रखा है, जिसकी पहुंच देश के कोने-कोने में दिखायी देती है।

'नागरिक पहल' के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, पीएम मोदी का मानना है कि सशक्त नागरिक हमारे लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ हैं।

मुख्यमंत्री के रूप में उनके 12 वर्षों के लंबे कार्यकाल के दौरान गुजरात ने नवउदारवादी राजनीति की नवीन व्याख्याओं को अपनाते हुए 15 प्रतिशत की विकास दर हासिल की। लेकिन जो बात श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को पिछले नेताओं से अलग करती है, वह यह है कि लोगों को गरीबी से बाहर निकालने और उनके समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई जन-केंद्रित पहल बहुत ही अनूठी थी। श्री नरेंद्र मोदी की सरकार हमारे नागरिकों की वित्तीय, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लेकर आई है, जिसमें राज्य प्रायोजित सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने से लेकर किसानों को उनके उत्पादन में सुधार के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने से लेकर उभरती कंपनियों स्टार्ट-अप के लिए धन उपलब्ध कराने तक शामिल हैं।

गुजरात पुनर्विकास

गुजरात भूकंप पुनर्निर्माण और पुनर्वास परियोजना (2001)

जैसे ही श्री नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता में आए, गुजरात को रिक्टर पैमाने पर 7.7 तीव्रता के भीषण भूकंप का

सामना करना पड़ा, जिससे 8,000 से अधिक गांवों में बड़े पैमाने पर विनाश हुआ।

2001 में भूकंप से उत्पन्न चुनौतीपूर्ण स्थिति के जवाब में गुजरात सरकार ने विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र और अन्य द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों के समर्थन के साथ राज्य के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया।

गुजरात पुनर्वास प्रयास का सबसे रचनात्मक घटक गृह पुनर्निर्माण था।

अपनी तरह के अनूठे भागीदारी कार्यक्रम के रूप में बहु-जोखिम प्रतिरोधी निर्माण और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया।

जनवरी 2004 के अंत तक, 1,86,967 घरों का पुनर्निर्माण किया गया और 9,01,150 घरों की मरम्मत की गई, जिसका काम तीन वर्षों में पूरा किया गया। कच्छ में सरकार ने केवल तीन वर्षों में मरम्मत और पुनर्निर्माण का 83 प्रतिशत काम पूरा किया था।

अस्थायी और वैकल्पिक भवनों के साथ भूकंप के बाद थोड़े समय के भीतर सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं को चालू कर दिया गया।

एक दृष्टिकोण, प्रशासनिक कौशल और राजनीतिक संकल्पशीलता के साथ एक बेहतरीन दृष्टिकोण और उत्कृष्ट उदाहरण कच्छ जिले के चार शहरों: अंजार, भचाऊ, भुज और रापर का पुनर्निर्माण था।

एक मालिक द्वारा संचालित पुनर्निर्माण दृष्टिकोण के माध्यम से, लोगों ने सरकार की सहायता और सुविधा के साथ अपने घरों का पुनर्निर्माण किया।

ग्रामीण ऊर्जा में सुधार के लिए गुजरात सरकार द्वारा समर्थित गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने 2003-04 में ज्योति ग्राम योजना (JGS) शुरू की। इस योजना में गैर-कृषि उपयोगकर्ताओं को 24 घंटे बिजली आपूर्ति और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किसानों को कम से कम आठ घंटे के लिए बेहतर गुणवत्ता वाली बिजली आपूर्ति का वादा किया गया था। गुजरात आज 13,000मेगावॉट की मांग के मुकाबले 22,524 मेगावॉट की क्षमता के साथ बिजली अधिशेष है। ऐसा मील का पत्थर दिल्ली की राजधानी सहित कई अन्य राज्यों के विपरीत है, जो लगातार बिजली कटौती का सामना करते है।

गुजरात ने बिजली क्षेत्र में जो प्रगति की है, उससे चकित होकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, पीयूष गोयल ने 2017 में गुजरात की प्रमुख योजना ज्योति ग्राम योजना (JGY) को राष्ट्रव्यापी स्तर पर अपनाने की योजना की घोषणा की।

स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997 से गुजरात में आधिकारिक रूप से चालू है। हालांकि, श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2007 से कार्यक्रम को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक छात्रों तक बढ़ा दिया गया है। 2009-10 तक 1.38 करोड़ बच्चों की जांच की गई और 15.03 लाख से अधिक बच्चों को मौके पर ही इलाज मुहैया कराया गया। 59893 लाख बच्चों को मुफ्त में चश्मा दिया गया। 4460 बच्चों का हृदय रोग, 1158 बच्चों का किडनी रोग और 229 बच्चों का कैंसर का इलाज किया गया है। 4 बच्चों को इलाज के लिए राज्य के बाहर सुपर स्पेशलिस्ट के पास रेफर किया गया। 8

श्री नरेंद्र मोदी ने लोगों तक आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करने की दृष्टि से आपातकालीन चिकित्सा सेवा अधिनियम, 2007 अधिनियमित किया। अधिनियम की मुख्य विशेषताओं में सार्वजनिक और निजी संसाधनों और बुनियादी ढांचे के माध्यम से एक राज्य-व्यापी आपातकालीन चिकित्सा सेवा नेटवर्क का निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के प्रशिक्षण के प्रावधान के माध्यम से देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और आपातकालीन देखभाल में शामिल अस्पतालों और एम्बुलेंस के लिए मानक निर्धारित करना शामिल है। इस योजना के तहत 'सेवा 108' की लगभग 400 एम्बुलेंस वैन और बड़ी संख्या में ट्रामा केयर यूनिट शुरू की गई हैं।

भारत में सुशासन के अग्रदूत के रूप में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2009 में "हमारे देश के विकास में युवाओं योगदान के लिए एक असाधारण अवसर" के रूप में मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की। 2009 के बाद, कई भाजपा और गैर-भाजपा राज्यों ने सुशासन की प्रथाओं को बढ़ावा देने वाले इस मॉडल को अपनाने की कोशिश की। यह कामकाजी पेशेवरों को मौजूदा मुद्दों को समझने और नवीन नीति प्रथाओं के माध्यम से समाधान की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है। श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित इस तरह की समस्या-समाधान दृष्टिकोण को बाद में कई अन्य राज्य सरकारों जैसे हरियाणा और पंजाब द्वारा जिला विकास फैलोशिप कार्यक्रम के साथ अपनाया गया।

सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं को प्रभावी ढंग से वितरित

करने के कार्यक्रम को जारी रखते हुए, राज्य सरकार ने 2010 में 'स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना' नामक समग्र सुधार से जुड़ी योजना शुरू की। इस योजना के तहत, जल आपूर्ति और भूमिगत जल निकासी परियोजनाओं और कार्यान्वयन के लिए सभी 159 नगर पालिकाओं का चयन किया गया, यह परियोजनाएं मौजूदा योजना से इतर थी। 12 योजना सफलतापूर्वक जारी रही और इनको 12वीं पंचवर्षीय योजना में कुल 15,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शामिल किया गया। । अगस्त 2014 में, सूरत नगर निगम ने पांडेसरा क्लस्टर में उद्योगों को 18.20 रुपये प्रति किलोलीटर पर घरेलू सीवेज पानी की आपूर्ति शुरू की, जो मार्च 2021 तक धीरे-धीरे बढ़कर 28.58 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई।

श्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही पारदर्शी शासन की प्रतिष्ठा को प्रभावी ढंग से बनाए रखा है। जबकि विपक्ष ने इस विशेषता को प्रकृति में निरंकुश माना, देश गुजरात में एक निर्णायक सरकार की उत्पत्ति का गवाह बन रहा था। 2009 में, राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के मामलों से निपटने के लिए अहमदाबाद और सूरत में दो विशेष अदालतों की स्थापना की। गुजरात उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल प्रदीप भट्ट ने इस कदम पर कहा कि "राज्य के मुख्य न्यायाधीश ने एक स्पष्ट संदेश भेजा है कि भ्रष्टाचार के सभी मामलों को पूर्ण न्याय और महत्व दिया जाएगा और अत्यधिक निष्पक्षता से निपटा जाएगा ताकि नागरिकों को न्यायपालिका और भ्रष्टाचारियों से निपटने की उसकी शक्ति पूर्ण विश्वास हो।"

24 अप्रैल 2003 को गुजरात भारत का पहला राज्य था, जिसने 'स्वागत' नामक कार्यक्रम के रूप में डिजिटल और संचार प्रौद्योगिकी के संयोजन को लॉन्च किया था। ऐसा पहली बार था, कि लोगों को शिकायत निवारण के लिए सीधे मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करने का एक मंच प्राप्त हुआ था। इसने कई पुरस्कार जीते, विशेष रूप से 2010 में लोक सेवा में पारदर्शिता, जवाबदेही में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार शामिल है।

नौकरशाही के साथ बेहतर संवाद के लिए श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में सुरक्षित आवाज संचार सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से सचिवालय एकीकृत संचार नेटवर्क (एसआईसीएन) नामक एक अभिनव तकनीकी को लागू किया। वर्तमान में 6800 वॉयस कनेक्शन के साथ, इस परियोजना ने सरकार को बिना किसी अतिरिक्त लागत के नेटवर्क के भीतर तेज और बेहतर संचार करने में सक्षम बनाया है। यह सुविधा हर दिन लगभग 1,25,000 आंतरिक कॉल और नेटवर्क के बाहर 70,000 कॉलों को संभालती है।

> "हमारा प्रयास है कि देश का हर व्यक्ति सशक्त हो। एक समावेशी समाज का निर्माण हो। 'सम' और 'मम' के भाव से समाज में समरसता बढ़े और सब एक साथ मिलकर आगे बढ़े।"
>
> **-श्री नरेंद्र मोदी**
> प्रधानमंत्री

भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के तहत, राज्य डेटा केंद्र (एसडीसी) की पहचान ई-गवर्नेंस के वितरण के लिए आवश्यक अनुप्रयोगों के समेकन और होस्टिंग के लिए आवश्यक मूल और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के घटकों में से एक के रूप में की गई है। गुजरात एसडीसी के लिए नीतियां बनाने वाला पहला राज्य बना। इसके अलावा, इसने भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण (डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम - 2008) सहित ई-गवर्नेंस नीतियों के व्यावहारिक कार्यान्वयन की शुरुआत की। सभी भूमि अभिलेखों को डिजिटाइज़ करने के बाद, तालुका मामलातदार कार्यालयों में ई-धारा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो भूमि अभिलेखों की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों जैसे म्यूटेशन और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स (आरओआर) जारी करते हैं।

राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी सरकारी विभागों, निगमों और सोसायटियों में खरीद के लिए एक ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम शुरू किया गया था और जो सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं।

हम 'कृषि चमत्कार' के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं, जिसे गुजरात ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हासिल किया, जब वे 7 अक्टूबर, 2001

से 22 मई, 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 2002—03 से 2013—2014 के दौरान गुजरात की कृषि जीडीपी ने 8% की अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की, जो भारत 3.3% प्रति वर्ष की तुलना बहुत अधिक थी। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि गुजरात का 64 प्रतिशत क्षेत्र सूखा प्रभावित है और कम वर्षा के बावजूद कृषि में प्रगति की है। पंजाब और हरियाणा जैसे अन्य राज्यों के विपरीत, जहां हरित क्रांति सरकार के समर्थन से आई, गुजरात का कृषि परिवर्तन बाजार मार्ग के माध्यम से आया है।

श्री नरेंद्र मोदी के व्यवसायिक दृष्टिकोण के कारण नीति-निर्माण की दृष्टि में कृषि में बदलाव आया - जिसे सरकार ने 2000 और 2013 के बीच 11.1% की उच्च विकास दर के साथ - और पानी की कमी के बावजूद पूरा किया है। विकास के दो महत्वपूर्ण घटकों अर्थात् पारदर्शी शासन और अच्छी राजनीति को मिलाकर, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात ने सफलतापूर्वक औद्योगिक समृद्धि और कृषि विकास का संतुलन बनाए रखा। नीचे नरेंद्र मोदी के निर्देशन में गुजरात सरकार के नीतिगत निर्णयों और पहलों उल्लेख किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र में कृषि गतिविधियों के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की कल्पना के साथ, शिक्षित, सक्षम और उत्साही युवाओं को 'ग्राम मित्र योजना' के तहत 'ग्राम मित्र-कृषि' के रूप में नियुक्त किया गया। वे मानदेय पर काम करते थे। ग्राम मित्र विभागों के तहत पांच विभाग अर्थात पांच स्तंभों को मजबूत करने में मदद करने के लिए शिक्षित युवाओं को कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास और मानव विकास और सेवाओं के प्रभावी वितरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार एवं गांवों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया।

राज्य में दुधारू पशुओं का उपयोग करने के लिए 2002-03 में 'गोबर बैंक' की अवधारणा प्रस्तावित की गई थी। गांव की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बायोगैस और उप-उत्पादों का उत्पादन करने के लिए गांवों के समूहों में पहल करने का प्रस्ताव रखा गया था और जिसमें गैर-दुग्ध पशुधन का उपयोग किया जाता था जिसे अक्सर वध के लिए बेचा जाता था। इस पहल की अवधारणा श्री मोदी द्वारा की गई थी और गोबर बैंक की स्थापना की गई थी। 4 मई 2001 को उत्तर गुजरात के साबरकांठा जिले के अकोदरा गांव में 'एनिमल हॉस्टल' में गोबर से बिजली पैदा की गयी।

राज्य को दूसरी हरित क्रांति की ओर बढ़ने के लिए और 5 वर्षों

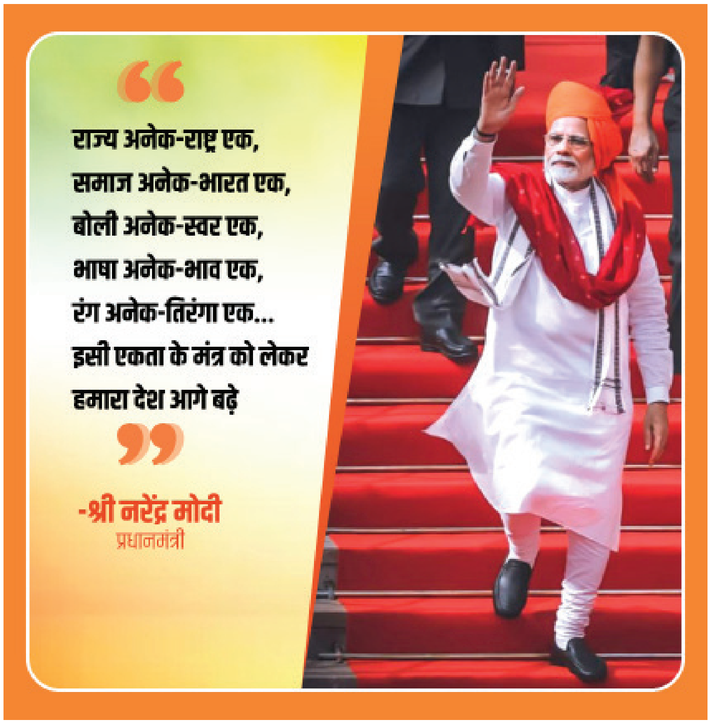

में किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से कृषि में एक अभिनव दृष्टिकोण के रूप में राज्य में कृषि महोत्सव -2005 की शुरुआत की गई थी। किसानों को सरकार के पास आने के बजाय, सरकार— कृषि वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ सभी मापदंडों पर इनपुट और जानकारी प्रदान करने के लिए कृषि रथों पर उनके दरवाजे पर गई। इस योजना ने 2003-2013 के 10 वर्षों में 12,000 हेक्टेयर से 7,00,000 हेक्टेयर की रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू करवाया।

सुजलम सुफलाम योजना के तहत मृदा स्वास्थ्य कार्ड परियोजना नवंबर 2003 में गुजरात नेतृत्व द्वारा शुरू की गई थी। इसके अभिनव दृष्टिकोण का उद्देश्य कृषि उत्पादकता, फसल की गुणवत्ता में वृद्धि करना और किसानों को उनकी भूमि के लिए उपयुक्त फसल और उर्वरकों के बारे में प्रमुख जानकारी देना था। यह परियोजना एक बड़ी सफल साबित हुई और इसके कार्यान्वयन के एक वर्ष के भीतर 1.8 लाख किसानों को कवर किया गया। राज्य के 12,70,000 किसानों को अब तक मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जा चुके हैं।

एक कृषि प्रधान देश में किसानों की आजीविका, उनकी उपज को समय पर बाजारों तक पहुंचाने पर निर्भर करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार द्वारा श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में

किसान पथ योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत परिवहन को मजबूत करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुविधाओं में सुधार का लक्ष्य रखा। इस योजना ने गांवों के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान की और तालुकों और जिला मुख्यालयों के बीच संपर्क में भी सुधार किया, इस प्रकार कृषि उपज को पास के कृषि उपज बाजार केंद्रों तक आसानी से पहुँचाया जा सका। इस योजना के तहत 7830 किलोमीटर सड़कों में बदलाव किया गया और जिसका लाभ 3364 गांवों को हुआ है। यह सफलता श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के बिना कभी संभव नहीं होती, जिन्होंने गुजरात की विकास यात्रा में राजमार्गों पर बहुत जोर दिया।

सागर खेडू योजना (2007) को राज्य की 1,600 किलोमीटर लंबी तटरेखा के साथ 60 लाख लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिसमें 3000 गाँव शामिल थे। इस परियोजना में मछुआरों को प्रशिक्षण, नावों के लिए सोलर लैंप, जीवन रक्षक उपकरण, रियायती दरों पर मिट्टी का तेल वितरण, विभिन्न बंदरगाहों का विकास शामिल है। योजना के क्रियान्वयन के लिए 11,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया था। राज्य मत्स्य विभाग द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों के अनुसार 2021 तक, परियोजना के तहत 235.68 करोड़ रुपये के काम किए गए हैं, जिससे 76,000 से अधिक व्यक्तियों को लाभ हुआ है।

सकल कृषि योग्य क्षेत्रः 108 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 148 लाख हेक्टेयर हुआ।

बागवानी उत्पादनः 2001—2011 के बीच सामरिक फसल विविधीकरण के माध्यम से 350% तक बढ़ा।

दुग्ध उत्पादनः पशु छात्रावासों, 30,000 पशु आरोग्य मेलों, 1.2 करोड़ पशुओं के उपचार और 122 पशु रोगों के उन्मूलन जैसे नवाचारों के माध्यम से 85% की वृद्धि।

'गुजरात मॉडल' श्री नरेंद्र मोदी के दिमाग की उपज, पारदर्शी शासन, समान विकास और आधुनिकीकरण का एक अनुकरणीय और व्यावहारिक उदाहरण है। राज्य ने प्रगतिशील विकास की एक लंबी यात्रा को देखा है, जिसने गुजरात राज्य को समृद्ध बनाने वाली नींव रखी है। यह बिजली, उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अन्य अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों से काफी आगे है। जबकि पूंजीवादी विकास की पृष्ठभूमि में ग्रामीण क्षेत्रों का अभाव होता है, श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात सरकार के निरंतर प्रयासों ने इसकी कृषि आजीविका और संसाधनों को सुगम और मजबूत किया। नतीजतन, गुजरात ने कृषि क्षेत्र में 9% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की, जबकि 2003-2013 के बीच राष्ट्रीय औसत सिर्फ 3.2 थी।

बड़े पैमाने पर 'गुजरात मॉडल' की सफलता के कारण अक्टूबर 2013 में नरेंद्र मोदी को 2014 के आम चुनावों के लिए भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था। 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' नवउदारवाद की एक अभिनव और प्रभावशाली व्याख्या है। एक लंबे दशक की खराब राजनीति के बाद 2014 के आम चुनावों में जनता ने श्री नरेंद्र मोदी में अपना विश्वास व्यक्त किया। तब से सुशासन की संस्कृति पूरे देश में फैली हुई है।

नये युग की शुरुआत

"सबका साथ, सबका विकास" के वादे को कायम रखते हुए, श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अपने लगातार दूसरे कार्यकाल में सुशासन की अपनी विरासत को जारी रखा। उन्होंने निर्णय लेने में तेजी लाने के लिए समावेशी, विकासोन्मुख और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की सफलतापूर्वक शुरुआत की है। दशकों में पहली बार, भारत सरकार नागरिकों को शासन के केंद्र में शामिल कर रही है। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और अध्यक्षता में महिला सशक्तिकरण, स्वच्छ भारत, उभरती विश्व शक्ति, नए भारत की औद्योगिक समृद्धि और कोविड के खिलाफ एकजुट भारत आदि विषयों में काफी सफलता हासिल की। 2014 से भारत सरकार द्वारा अपनाई गई प्रभावी शासन पद्धतियों का संक्षिप्त ट्रैक रिकॉर्ड नीचे दिया गया हैः

हमारे महान सैनिकों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए, जिन्होंने निःस्वार्थ रूप से देश को हर संभव खतरे से बचाया और साहसपूर्वक हमारे प्रियजनों की रक्षा की, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए 'वन रैंक वन पेंशन' योजना शुरू की, जो 4 दशकों से अधिक समय से ठप पड़ी थी। ओआरओपी का उद्देश्य एक ही रैंक में सेवानिवृत्त होने वाले सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए समान अवधि की सेवा के साथ समान पेंशन सुनिश्चित करना था, भले ही वे सेवानिवृत्त हों।

देश के सभी घरों में व्यापक वित्तीय समावेशन लाने के लिए और देश के युवाओं तक देश के विकास के मिशन मोड कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, श्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जन—धन योजना शुरू की। इस योजना में हर घर के लिए कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, वित्तीय साक्षरता, ऋण तक पहुंच, बीमा और पेंशन सुविधा

की परिकल्पना की गई थी। इसके अलावा, लाभार्थियों को एक लाख रुपये के दुर्घटना बीमा कवर के साथ रुपे डेबिट कार्ड मिला। योजना में सभी सरकारी लाभों (केंद्र / राज्य / स्थानीय निकाय से) को लाभार्थियों के खातों में प्रसारित करने और केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना को आगे बढ़ाने की भी परिकल्पना की गई है।

2016 में शुरू की गई, उज्ज्वला योजना की सफलता ने इसके विस्तार की अलख जगायी। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की पांच करोड़ महिला सदस्यों को तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) कनेक्शन प्रदान करना है। सांख्यिकीय रूप से योजना के प्रथम चरण में राज्य के गरीब परिवारों को 1,47,43,862 एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। 2019 तक, पूरे भारत में लाभार्थियों को 7,23,25,948 कनेक्शन जारी किए गए। सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में पीएमयूवाई 2.0 की घोषणा की गई थी। योजना के तहत अतिरिक्त 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शन का प्रावधान किया गया है।

हमारे देश के अन्नदाता को सशक्त बनाने के लिए श्री मोदी के नेतृत्व में पीएम किसान की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान योजना) एक सरकारी योजना है जिसके माध्यम से सभी छोटे और सीमांत किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रुपये तक मिलेंगे। 75,000 करोड़ रुपये की इस योजना का लक्ष्य भारत में 125 मिलियन किसानों को कवर करना है, चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो।

आयुष्मान भारत, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार की एक प्रमुख योजना, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश के अनुसार शुरू की गई थी। इस प्रयास का लक्ष्य सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पूरा करना है और "किसी को पीछे नहीं छोड़ना" का वादा है। आयुष्मान भारत एक समग्र, आवश्यकता-आधारित स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों पर महत्वपूर्ण पहलों को लागू करता है, जिसमें रोकथाम, पदोन्नति और देखभाल शामिल है।

डिजिटल परिवर्तन से लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया, डीबीटी, पहल, जैम ट्रिनिटी जैसी ई-गवर्नेंस पहल शुरू की गई हैं। 19 मार्च, 2019 को 6.46 लाख करोड़ रुपये सीधे डीबीटी के माध्यम से नागरिकों को हस्तांतरित किए गए हैं, जिसमें 439 से अधिक केंद्र सरकार की योजनाएं डीबीटी का उपयोग कर रही हैं।

सरकारी ई-मार्केटप्लेस पोर्टल को 22,420 करोड़ रुपये से अधिक व्यय के साथ आरंभ किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा आदि जैसी सरकारी परियोजनाओं की निगरानी के लिए जियो टैगिंग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए दिशा पोर्टल लॉन्च किया गया। इसके अलावा, सरकार और भारत की जनता के बीच एक संवादात्मक मंच - MyGov के माध्यम से शासन में नागरिक भागीदारी को एक वास्तविकता बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कम आय वाले व्यक्तियों, शहरी गरीबों और ग्रामीण गरीबों सहित समाज के गरीब और वंचित वर्ग को किफायती आवास प्रदान करने के लिए पीएम आवास योजना शुरू की गई थी। 31 मार्च, 2022 तक, योजना का लक्ष्य किफायती मूल्य पर लगभग 20 मिलियन घर बनाना था। संघीय सरकार से वित्त पोषण में यूएसडी 31 बिलियन प्राप्त करने की योजना की परिकल्पना की गई थी। प्रधानमंत्री

सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के उद्देश्य से श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार, सामाजिक सुरक्षा योजना 'अटल पेंशन योजना' के साथ आई। यह 60 वर्ष की आयु के लोगों को 1000 रुपये से 5000 रुपये तक की न्यूनतम गारंटी पेंशन प्रदान करता है। पेंशन की राशि अभिदाता की मृत्यु पर जीवन भर के लिए गारंटीकृत है और अभिदाता और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु की स्थिति में संपूर्ण पेंशन राशि का भुगतान नामांकित व्यक्ति को किया जाता है।

गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री द्वारा प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) शुरू की गई थी। योजना का उद्देश्य सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई), गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों / कंपनियों (एनबीएफसी), लघु वित्त बैंकों, आरबीआर, वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों आदि को योग्य संस्थाओं और सभी प्रकार के व्यवसायों को कम दर पर ऋण प्रदान करने में सक्षम बनाना है।

आवास योजना को दो भागों में बांटा गया हैः पीएम आवास योजना ग्रामीण और पीएम आवास योजना शहरी। पीएमएवाई-ग्रामीण का लक्ष्य 2022 तक सभी बेघर गृहस्थों और कच्चे और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का घर उपलब्ध कराना है, वहीं पीएमएवाई अर्बन ईडब्ल्यूएस/एलआईजी और एमआईजी श्रेणियों के बीच शहरी आवास की कमी पूरा करता है, जिसमें झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले भी शामिल हैं। इसके तहत वर्ष 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों के लिए एक पक्का घर सुनिश्चित करना है,यह वह समय होगा जब राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेगा।

सेवाओं के डिजिटल रूप से उन्मुख वितरण की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को मंजूरी दी गई थी। दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों में से एक के तहत 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए लक्षित किया गया था।

02.08.2021 तक, लगभग 5.01 करोड़ लाभार्थियों को नामांकित किया गया है और 4.21 करोड़ को पीएमजीदिशा योजना के तहत प्रशिक्षित किया गया है। अब तक 2.59 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थी पंजीकृत हैं जो कुल पंजीकरण संख्या का 52% है। उपरोक्त में से 1.78 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों को इस योजना के तहत प्रमाणित किया गया है जो कि पीएमजीदिशा योजना के तहत कुल प्रमाणित लाभार्थियों का 54% है।

बेरोजगारी बहुत लंबे समय से देश के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से सृजित लाखों आईटी-सक्षम युवा (ग्राम स्तर के उद्यमियों) ग्रामीण भारत में व्यापार के अवसरों और सरकार से उदार समर्थन के माध्यम से परिवर्तन-एजेंट बन गए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सुधारात्मक संस्थागत ढांचे के साथ सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) शुरू करने को मंजूरी दी है। एनपीसीएससीबी को सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण की नींव रखने के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया है ताकि वे भारतीय संस्कृति और संवेदनाओं के बारे में बेहतर समझ विकसित कर सकें और अपनी जड़ों से जुड़े रहें, जबकि वे दुनिया भर के सर्वोत्तम संस्थानों और प्रथाओं से सीखते हैं। यह पाठ्यक्रम एक एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण-आईजीओटी-कर्मयोगी मंच की स्थापना के द्वारा दिया जाएगा।

मुश्किल समय में राज्य सरकारों की सहायता के लिए एक मजबूत केंद्र के साथ संघवाद में लोकतंत्र का सार निहित है। वर्ष 2020 में वैश्विक महामारी कोविड -19 का सामना हमने किया, जिसने देश के कामकाज को बाधित कर दिया। ऐसे संकट में इस योजना का उद्देश्य उन राज्य सरकारों के पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देना है जो कोविड-19 महामारी से उत्पन्न कर राजस्व में कमी के कारण वित्तीय घाटे का सामना कर रही हैं।

अब तक वित्त मंत्रालय ने 27 राज्यों के 9,879.61 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत पहली किस्त के रूप में राज्यों को 4,939.81 करोड़ जारी किए जा चुके हैं।

देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी शेष गैर-विद्युतीकृत घरों में अंतिम मील कनेक्टिविटी और बिजली कनेक्शन द्वारा सभी तक ऊर्जा पहुंच प्रदान करने के लिए पीएम सौभाग्य योजना शुरू की गई थी। परियोजना का कुल परिव्यय रु. 16,320 करोड़ जबकि सकल बजटीय सहायता (GBS) रु. 12,320 करोड़ है। ग्रामीण परिवारों के लिए परिव्यय रु 14,025 करोड़ जबकि GBS रु. 10,587.50 करोड़ है। शहरी परिवारों के लिए परिव्यय रु. 2,295 करोड़ जबकि GBS रु. 1,732.50 करोड़ है। भारत सरकार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस योजना के लिए बड़े पैमाने पर धन उपलब्ध कराएगी।

अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, जल आपूर्ति, सिंचाई, बिजली, परिवहन, शिक्षा, शहरी विकास में पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

21वीं सदी की कराधान प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पारदर्शी कराधान योजना शुरू की गई है। कर सुधारों का मुख्य उद्देश्य करों की दरों में कमी और प्रत्यक्ष कर कानूनों के सरलीकरण पर नए पेश किए गए दस्तावेज़ पहचान संख्या (डीआईएन) के साथ अधिक पारदर्शिता लाने के लिए है।

इसके अतिरिक्त, यह देश के ईमानदार करदाताओं को लाभान्वित करता है, जिनकी कड़ी मेहनत से राष्ट्र की प्रगति होती है। इससे भारत में कर प्रणाली में सुधार और सरलीकरण होगा।

भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने की एक योजना प्रधानमंत्री मत्स्य

संपदा योजना के बैनर तले शुरू की गई थी।
योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैः

एक स्थायी, जिम्मेदार, समावेशी और न्यायसंगत मत्स्य पालन क्षमता का विकास।

भूमि और पानी के विस्तार, गहनीकरण, विविधीकरण और उत्पादक उपयोग के माध्यम से मछली उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना।

मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण - फसलोत्तर प्रबंधन और गुणवत्ता में सुधार।

मछुआरों और मछली किसानों की आय को दोगुना करना और रोजगार सृजन

कृषि जीवीए और निर्यात में योगदान बढ़ाना।

मछुआरों और मछली किसानों के लिए सामाजिक, भौतिक और आर्थिक सुरक्षा।

मजबूत मात्स्यिकी प्रबंधन और नियमित ढांचा।

स्वामित्व (गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण)योजना 24 अप्रैल, 2020 को एक सामाजिक-आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण लोगों को अपनी आवासीय संपत्तियों का दस्तावेजीकरण करने का अधिकार प्रदान करना था ताकि वे अपनी संपत्ति का उपयोग आर्थिक उद्देश्यों के लिए कर सकें। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व संग्रह को सुव्यवस्थित करने और संपत्ति के अधिकारों पर स्पष्टता सुनिश्चित करने में मदद करती है जिससे संपत्ति संबंधी विवादों का उचित समाधान किया जा सकें। यह योजना इस कार्यक्रम के तहत बनाए गए नक्शों के माध्यम से बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) के निर्माण में मदद करती है। लॉन्च के दिन, 4.09 लाख संपत्ति मालिकों को उनके ई-प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए।

12 मई, 2020 को केंद्र सरकार ने कोविड—19 महामारी से लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के एक विशेष और व्यापक आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 10% के बराबर था।

यह अभियान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित नए भारत की दृष्टि के अनुरूप था। सरकार ने कृषि के लिए आपूर्ति श्रृंखला सुधार, तर्कसंगत कर प्रणाली, सरल और स्पष्ट

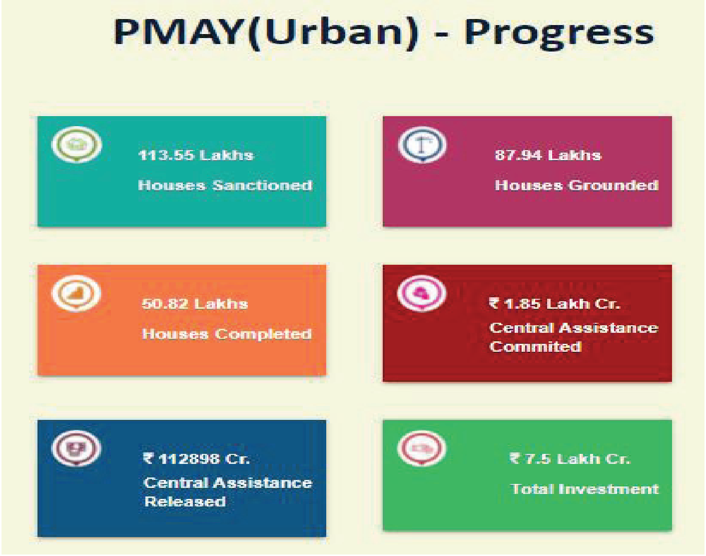

कानून, सक्षम मानव संसाधन और मजबूत वित्तीय प्रणाली जैसे कई साहसिक सुधार किए।

असंगठित श्रमिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की गई थी। यह योजना घर के कामगारों, रेहड़ी-पटरी वालों, मिड-डे मील वर्कर, हैड लोडर, ईंट भट्ठा कामगार, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, कृषि मजदूर के रूप में लगे लोगों, श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, दृश्य-श्रव्य श्रमिक या समान अन्य व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिक के लिए थी।

सभी स्तरों पर स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमताओं का निर्माण करने की दृष्टि से अर्थात प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक और वर्तमान और भविष्य की महामारियों / आपदाओं के लिए प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए प्रधान मंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना '(पीएमएएसबीवाई) योजना इस वर्ष शुरू की गई थी। इस योजना का लक्ष्य मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में ब्लॉक, जिला, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क विकसित करके और स्वास्थ्य इकाइयों को मजबूत करके, प्रभावी ढंग से बीमारी का पता लगाने, जांच करने, रोकने और मुकाबला करने के लिए एक आईटी सक्षम रोग निगरानी प्रणाली का निर्माण करना है। जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति और रोग प्रकोप जैसी परिस्थितियों को भी शामिल किया गया है। कोविड-19 और अन्य संक्रामक रोगों पर अनुसंधान भी इसका एक उद्देश्य है, जिसमें बायोमेडिकल अनुसंधान शामिल है,

जो महामारी जैसे कोविड-19 के लिए अल्पकालिक और मध्यम अवधि की प्रतिक्रिया को सूचित करने के लिए और एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण देने के लिए मुख्य क्षमता विकसित करने पर आधारित है। साथ ही जानवरों और मनुष्यों में संक्रामक रोग के प्रकोप को रोकने, पता लगाने और प्रतिक्रिया देने के लिए भी इस योजना की शुरुआत हुई है।

कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में गरीबों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना/पैकेज शुरू किया गया। यह मार्च 2020 में गरीबों तक भोजन और आर्थिक मदद के लिए आरंभ किया गया, ताकि उन्हें आवश्यक वस्तुओं को खरीदने और आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

इस प्रकार श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकारों के निरंतर प्रयासों ने देश को विकास को नयी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, जिससे समाज के प्रत्येक नागरिक की स्थिति मजबूत हुई है।

समावेशी भारत

2014 के आम चुनावों में प्रचंड जनादेश श्री मोदी के नेतृत्व पर हर तबके के लोगों के भरोसे का प्रमाण था। जिसके बाद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं को सरकार द्वारा लागू किया गया था। पिछले तीन वर्षों में अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित समाज के हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए काम किया गया है।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने छः मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन का सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण करने के लिए विभिन्न पहल और कार्यक्रम विकसित किए। उदाहरण के लिए:

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, योग्यता-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना - जिनकों प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है, जिससे छात्रों का शैक्षिक स्तर पर सशक्तिकरण किया जा सके।

मौलाना आजाद राष्ट्रीय फैलोशिप योजना - वित्तीय सहायता के रूप में फेलोशिप प्रदान करती है।

नया सवेरा - मुफ्त कोचिंग और संबद्ध योजना - इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों / तकनीकी/ चिकित्सा पेशेवर पाठ्यक्रमों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रवेश परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करना है।

पढो परदेश - विदेशी उच्च अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को ब्याज सब्सिडी की योजना।

नई उड़ान - संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), राज्य लोक सेवा आयोग (पीएससी) कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए सहायता।

नई रोशनी - अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिला नेतृत्व

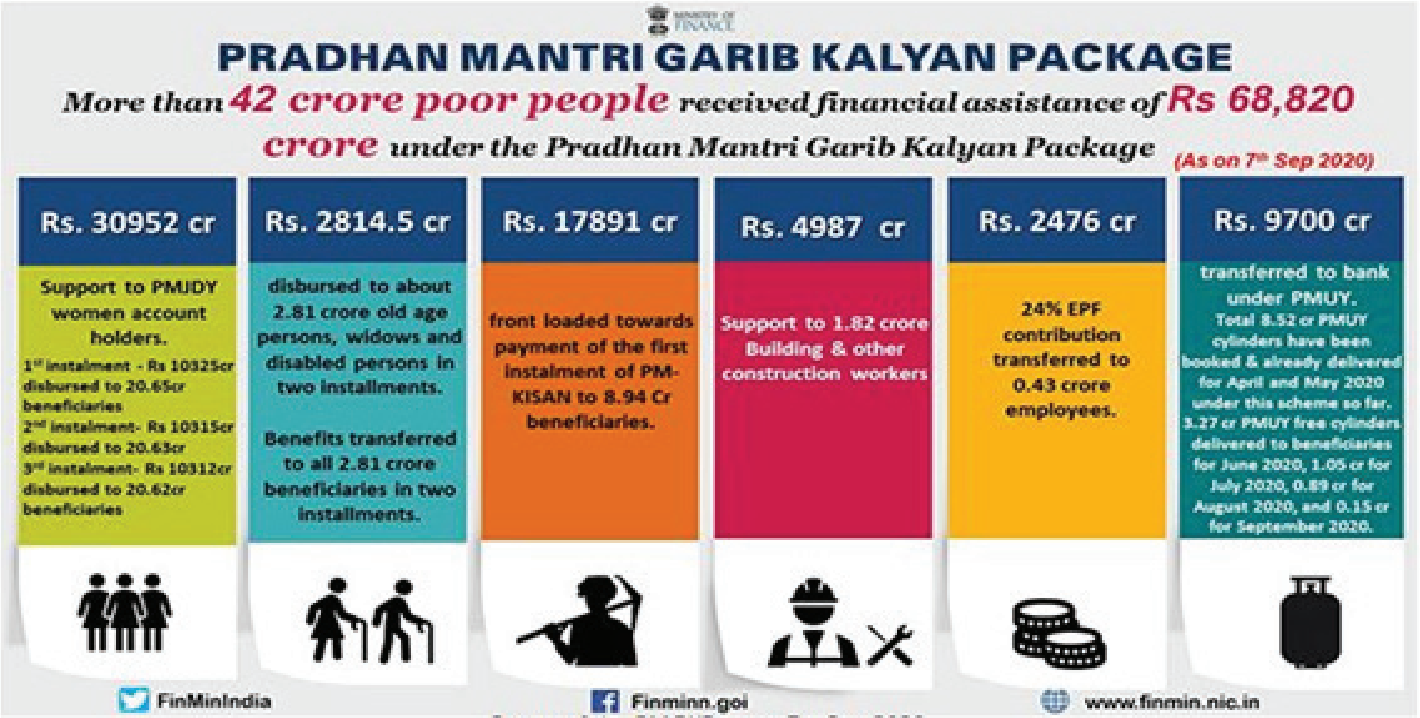

Status of the PMGKP as on 7th Sep 2020

विकास।

सीखो और कमाओ - 14 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं के लिए कौशल विकास योजना, जिसका उद्देश्य रोजगार के अवसर प्रदान करना, मौजूदा श्रमिकों, स्कूल छोड़ने वालों आदि की रोजगार क्षमता में सुधार करना।

प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) - वंचित क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, छात्रावास, सद्भाव मंडप, कौशल विकास केंद्र, पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इत्यादि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

जियो पारसी - भारत में पारसियों की जनसंख्या में गिरावट को रोकने के लिए योजना।

उस्ताद (विकास के लिए पारंपरिक कला/शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन)- शिल्पकारों को रोजगार के अवसर और बाजार उपलब्ध कराने के लिए देश भर में हुनर हाटों का आयोजन किया जा रहा है।

नई मंजिल - औपचारिक स्कूली शिक्षा और स्कूल छोड़ने वालों के कौशल विकास के लिए एक योजना।

हमारी धरोहर- भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने की एक योजना।

मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन (एमएईएफ) ने शिक्षा और कौशल से संबंधित योजनाओं को निम्नानुसार कार्यान्वित किया: - (ए) अल्पसंख्यकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित मेधावी लड़कियों के लिए बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (बी) गरीब नवाज स्वरोजगार योजना 2017-18 में शुरू की गई युवाओं को अल्पकालिक रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना (सी) मदरसा छात्रों और स्कूल छोड़ने वालों के लिए ब्रिज कोर्स।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) को अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार और आय पैदा करने वाले उद्यमों के लिए रियायती ऋण प्रदान करने के लिए इक्विटी है। ◆

गुजरात में मुसलमानों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं

उन गांवों में जहां मुस्लिम आबादी 2000 से अधिक है, गुजरात के 89.9% गांवों में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है, जबकि राष्ट्रीय औसत 70.7% है।

1000—2000 की जनसंख्या वाले 66.67% गांवों में चिकित्सा सुविधाएं हैं, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 43.5 है

1000 से कम मुस्लिम आबादी वाले 53% गांवों में चिकित्सा सुविधाएं हैं, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 20.2% है

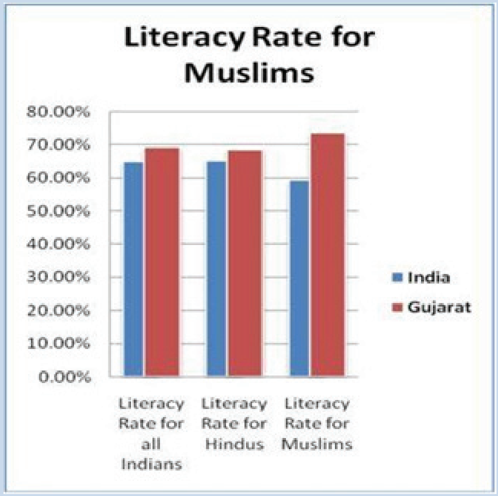

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी, 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की शुरुआत की। यह योजना उन किसानों पर प्रीमियम के बोझ को कम करने में मदद करती है जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं और उन्हें खराब मौसम से भी बचाते हैं। बीमा दावे के निपटान की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने का भी निर्णय लिया गया ताकि किसानों को फसल बीमा योजना के संबंध में कोई परेशानी न हो। यह योजना भारत के प्रत्येक राज्य में संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से लागू की गई थी। यह योजना भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत प्रशासित है।
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि योजना (पीएमबीजेपी)
यह योजना औषधि विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2008 में गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं के उत्पादन और उन्हें सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। जनऔषधि केंद्रों के रूप में पहचाने जाने वाले समर्पित आउटलेट सस्ती दरों पर जेनेरिक दवाओं के प्रावधान के लिए खोले गए हैं। 06.08.2021 तक पूरे भारत में 8012 जनऔषधि केंद्र कार्यरत थे। पीएमबीजेपी के उत्पाद समूह में 1451 दवाएं और 240 सर्जिकल आइटम शामिल हैं। इसके अलावा, इसका उद्देश्य शिक्षा और प्रचार के माध्यम से रोजगार पैदा करना और जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता फैलाना है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना / पैकेज
गरीबों को कोरोना वायरस की लड़ाई के खिलाफ लड़ने में मदद करने के लिए मार्च 2020 में 1.70 लाख करोड़ रुपये के व्यापक राहत पैकेज की घोषणा की गई, ताकि वे आवश्यक आपूर्ति खरीद सकें और अपनी आवश्यक जरूरतों को पूरा कर सकें। योजना के तहत निम्नलिखित घोषणाएं की गईं:
बीमा योजना के तहत कोविड-19 से लड़ने वाले प्रति स्वास्थ्य कार्यकर्ता को 50 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा - अप्रैल 2021 से प्रभावी एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया।
80 करोड़ गरीब लोगों को अगले तीन महीनों के लिए हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो पसंदीदा दाल मुफ्त मिलेगी - नवंबर 2021 तक बढ़ा दी गई (शुरुआत में, पैकेज को मई और जून 2021 तक बढ़ाया गया था; मूल रूप से इसे बढ़ा दिया गया था)।
20 करोड़ महिला जन-धन खाताधारकों को अगले तीन महीनों के लिए 500 रुपये प्रति माह दिया गया।
13.62 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए मनरेगा मजदूरी को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन किया गया।
3 करोड़ गरीब वरिष्ठ नागरिक, गरीब विधवाओं और गरीब विकलांगों को 1,000 रुपये की अनुग्रह राशि।
8.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने मौजूदा पीएम किसान योजना के तहत अप्रैल 2020 के पहले सप्ताह में किसानों को 2,000 रुपये का भुगतान किया।
केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्माण श्रमिकों को राहत प्रदान करने के लिए भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण कोष का उपयोग करने के आदेश दिए।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार को पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। यह लोग भारत की आबादी का 40% है। इसमें शामिल परिवार क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 (एसईसीसी 2011) और व्यावसायिक मानदंडों पर आधारित हैं। PM-JAY को पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (NHPS) के नाम से जाना जाता था। इसने तत्कालीन मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) को शामिल कर लिया गया, जिसे 2008 में लॉन्च किया गया था। इसलिए PM-JAY के तहत उल्लिखित कवरेज में ऐसे परिवार भी शामिल हैं जो RSBY में शामिल थे लेकिन SECC 2011 डेटाबेस में मौजूद नहीं हैं। PM-JAY पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है और कार्यान्वयन की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाती है।

भारत की ताकत को मजबूती देना

(वैश्विक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए सबक)

अंतर-राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के आदान-प्रदान के प्रयासों के समन्वय के लिए राज्यों की संभावित क्षमता में निवेश कर, पूरे देश को बदलने की क्षमता विकसित की जा सकती है। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहले एक मुख्यमंत्री के रूप में और फिर प्रधानमंत्री के रूप में, राज्यों ने नवाचार, प्रौद्योगिकी उन्नयन के क्षेत्र में अपनी निवेश क्षमता को बढ़ाया, युवा दिमागों को आकर्षित किया और उनकी क्षमताओं का उपयोग किया। जिससे न केवल राष्ट्र का बल्कि निकटवर्ती और विस्तारित पड़ोसियों का भी आर्थिक विकास संभव हुआ है।

मोदी जी ने 'सबका साथ, सबका विकास' के आदर्श वाक्य को यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली (यूएनजीए) में कहा, जिसमें दर्शाया गया कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है- 'जन कल्याण' न केवल भारत के लिए बल्कि 'जग कल्याण' पूरी दुनिया के लिए प्रगति का मानक है। पीएम मोदी ने तमिल कवि कन्या पुंगुंद्रनार को उद्धृत करते हुए "याधुम ओरे यावरुम केलीर" - "हम सभी स्थानों और सभी के हैं" - दुनिया के सामने प्रस्तुत किया कि भारत की प्रगति का सार सीमाओं से परे है, इसमें एक एकीकृत प्रगतिशील विश्व व्यवस्था शामिल है।

वाइब्रेंट गुजरात

सूक्ष्म और लघु उद्योग किसी भी राज्य के आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं जो बड़े पैमाने पर राज्य भर में रोजगार और निवेश को प्रभावित करते हैं। हालांकि ये छोटे उद्यम किसी भी आर्थिक प्रणाली का सबसे निचला हिस्सा होते हैं, लेकिन आर्थिक पिरामिड में उनकी संभावित वृद्धि महत्वपूर्ण हैं। इसलिए, इस क्षमता का उपयोग करना प्रत्येक देश के लिए एक समग्र एजेंडा होना चाहिए। गुजरात राज्य के संबंध में सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम (एमएसएमई) व्यवसाय प्रदर्शन और प्रौद्योगिकी और व्यापार से

संबंधित वैश्विक और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के रुझानों से काफी प्रभावित हैं।

श्री मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते गुजरात राज्य का लक्ष्य अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति से बढ़ाना था और इसका परिणाम यह हुआ कि गुजरात राज्य आज उद्योगों का केंद्र है और देश के संभावित कॉर्पोरेट, उद्योगपति और निवेशकों के बीच निवेश के लिए पहली पसंद बन गया है। मोदी सरकार के तहत गुजरात के विकास के लिए एक व्यावहारिक मानदंड द्विवार्षिक वाइब्रेंट गुजरात कॉन्क्लेव होता है, जो निम्नलिखित कारणों से 2003 में शुरू हुआ थाः -

गुजरात व्यापक सामाजिक और आर्थिक विकास का प्रकाशस्तंभ बनना चाहता है।

गुजरात में एक अत्यधिक विविध औद्योगिक संरचना है जो नवीन सार्वजनिक नीति पहल की मांग करती है।

यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि जापान और कनाडा ने 2013 के वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में राज्य के भागीदार के रूप में भाग लिया था, जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में मोदी सरकार के तहत राज्य के विकास की पुष्टि करता है। सीधे शब्दों में कहें तो, वाइब्रेंट गुजरात को अब महत्वपूर्ण उद्योगपतियों और निवेशकों के जमावड़े के लिए एक राष्ट्रव्यापी मंच के रूप में पहचाना जाता है, जो अपने भविष्य के निवेश ब्लूप्रिंट की तैयारी के लिए यहां आते हैं। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में राज्य अपने मजबूत बिंदुओं का प्रदर्शन करता है और हर साल सम्मेलन में प्रतिष्ठित व्यवसायी, संभावित निवेशक और इच्छुक उद्योगपति भाग लेते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि गुजरात का आर्थिक विकास लगभग चीन के औद्योगिक प्रांतों के बराबर है। एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया द्वारा किया गया एक सर्वेक्षण इस तथ्य की पुष्टि करता है कि गुजरात ने पिछले पांच वर्षों में भारत के अन्य सभी राज्यों में मूल्य और संख्या दोनों में सबसे अधिक निवेश प्रस्ताव गुजरात में आए हैं। गुजरात टाटा समूह और फोर्ड जैसे अंतरराष्ट्रीय दिग्गजों की वर्तमान पसंद है।

2003 में वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में 76 एमओयू प्राप्त हुए, जिसकी कीमत रु 66,000 करोड़, 2005 में इसे 227 एमओयू प्राप्त हुए, जिनकी कीमत रु 1.06 लाख करोड़ थी, इसी तरह 2007 में गुजरात राज्य सरकार ने 4.60 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में राज्य सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है, जिसे उच्च प्रोफ़ाइल निवेश सबमिट और नए कारखानों और अन्य विदेशी निर्माताओं के निर्माण ने

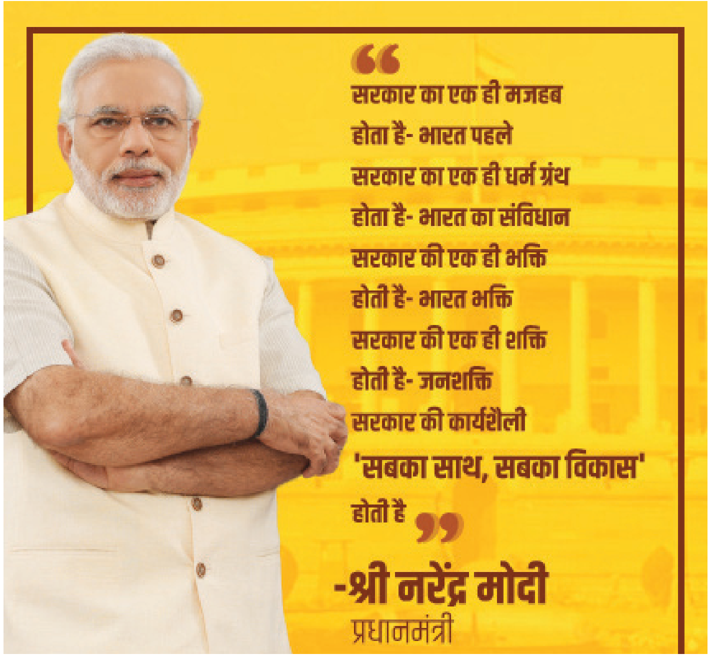

प्रोत्साहित किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को 'भारत का वैश्विक प्रवेश द्वार' बनाया था, इस संदर्भ में जापान और कनाडा द्वारा सह-भागीदार वाइब्रेंट गुजरात सबमिट - गुजरात सरकार का सबसे सफल कदम है, जिसने 20,000 लोगों को आकर्षित किया, जिसमें 19 भारतीय राज्यों और 60 देशों के प्रतिभागी थे। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के दौरान राज्य ने लगभग 100 बिलियन अमरीकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित किया।

इसके अलावा, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात संबंधित हस्तक्षेप और प्रदूषण प्रबंधन प्रथाओं की भूमि है। साथ ही, गुजरात ने बड़ी परियोजनाओं को विकसित करने वाली कंपनियों के लिए आसानी से भूमि अधिग्रहण करना संभव बना दिया है।

वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में वैश्विक व्यापार शो आयोजन भी इसी थीम पर हुआ। दुनिया के सबसे बड़े व्यापार शो में से एक में 25 से अधिक औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों को एक मंच प्रदान किया। 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया', 'स्टार्ट-अप इंडिया', 'सागरमाला प्रोजेक्ट', 'आयुष्मान भारत मिशन', 'इंद्रधनुष' जैसे केंद्र सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों

की विशेषता वाले 15 सहयोगी देश और भारतीय राज्य इसमें शामिल हुए।

संक्षेप में, व्यापार केंद्रित रवैया, अद्वितीय कार्यकारी शैली और श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता आज के उज्ज्वल गुजरात के पीछे का कारण है, एक ऐसा राज्य जो अन्यथा मोदी जी जैसे नेता के बिना समृद्धि के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर ब्रांडेड नहीं होता।

दूसरे शब्दों में, यह केवल एक आंकड़े भर नहीं है जो गुजरात की तरक्की को दिखाता है, यह इस देश के लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने वाले परिवर्तनकारी विकास के बारे में है। इसलिए, एक अनुकरणीय राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के अलावा, व्यापार करने में आसानी के मामले में लगातार बढ़ती रैंकिंग से स्पष्ट रूप से व्यापार के लिए एक अधिक अनुकूल माहौल को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार पर हमला और अर्थव्यवस्था का दीर्घकालिक दृष्टिकोण इसमें शामिल हैं। संरचनात्मक सुधारों के साथ, तत्कालीन सरकार ने विकास को जमीनी स्तर पर ले जाने के अपने इरादे का संकेत दिया है।

नवाचार और प्रौद्योगिकी

नवोन्मेष, कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी उन्नयन की आवश्यकता को गुजरात राज्य द्वारा श्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 2003 की शुरुआत में मान्यता दी गई थी, जब यह डिजिटल और संचार प्रौद्योगिकी के संयोजन को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया था।

स्वागत नामक कार्यक्रम के रूप में - प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा शिकायतों पर राज्यव्यापी ध्यान दिया गया। 2008 में गुजरात राज्य डेटा केंद्र (जीएसडीसी) का संचालन किया गया था, जो राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत परिचालन करने वाला भारत का पहला राज्य डेटा केंद्र है, जो गुजरात स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (जीएसडब्ल्यूएएन) के बुनियादी ढांचे के माध्यम से सभी सरकारी कार्यालयों से जुड़ा है और उनके बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। जो साइबर सुरक्षा के संबंध में असुरक्षित सार्वजनिक डोमेन और संवेदनशील सरकारी वातावरण के लिए बेहतर है।

इसके अलावा, राज्य के युवाओं को तकनीक की समझ रखने वाले और उन्हें बुनियादी कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 2012 में ऐमपावर पहल शुरू की गई थी, जहां गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी ने युवाओं के बीच योजना की स्वीकृति साझा करके प्रसन्नता व्यक्त की थी। .

प्रौद्योगिकी और नवाचार में ये प्रारंभिक निवेश प्रतिस्पर्धा के अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्राप्ति में मदद करने और प्रौद्योगिकी के समकालीन स्तरों की पेशकश करने में हमें सक्षम बनाता है। इस प्रकार, सरकार ने श्री मोदी के नेतृत्व में आर्थिक विकास में प्रौद्योगिकी और नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, नीति निर्माताओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहल करने के लिए निर्देशित किया और इसके लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गईं, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में युवा शोधकर्ताओं और महिला वैज्ञानिकों का पोषण करना और उन्हें बनाए रखना इसी पहल के घटक के रुप में पहचाने जाते हैं। 26 मई, 2015 को श्री मोदी के नेतृत्व में डीडी किसान की स्थापना की गई, ताकि किसानों को बेहतरीन तकनीक और कृषि पद्धतियां उपलब्ध कराई जा सकें। यह चैनल कृषि और संबंधित उद्योगों के लिए समर्पित है, और यह किसानों को अन्य विषयों के साथ नवीन कृषि तकनीकों, जल संरक्षण और जैविक खेती पर वास्तविक जानकारी प्रदान करता है। डीडी किसान की सामग्री का क्षेत्रीय दूरदर्शन केंद्रों द्वारा अनुवाद किया जा रहा है।

2021 तक देश भर में 8,700 से अधिक अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, जहां युवा अपने विचारों को साकार कर रहे हैं, 'स्वयं करें' मोड के माध्यम से युवा नवाचार कौशल सीखें

देश भर में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए श्री मोदी के नेतृत्व में अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार संस्थान (नीति आयोग) की एक प्रमुख परियोजना शुरू की गई थी। एआईएम का लक्ष्य स्कूलों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, एमएसएमई और उद्योग सहित सरकार के सभी स्तरों पर नवाचार और उद्यमिता के एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना और उसे बढ़ावा देना है।

अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) की स्थापना अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रमों और नीतियों को विकसित करने, विभिन्न हितधारकों के लिए मंच और सहयोग के अवसर प्रदान करने और नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र की देखरेख के लिए एक छत्र संरचना बनाने के उद्देश्य से की गई थी। भविष्य की दृष्टि और उद्देश्य के साथ वैज्ञानिक सोच पैदा करने और युवा मन में जिज्ञासा और नवीनता की भावना पैदा करने के लिए, स्कूलों और ऊष्मायन केंद्रों में अटल

टिंकरिंग प्रयोगशालाओं अपनी भूमिका को सुदृढ़ किया है।

जैसा कि मिशन ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्कूलों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, उद्योग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), गैर सरकारी संगठनों और मंत्रालयों को शामिल करते हुए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। इसके लिए केवल व्यक्तियों और समूहों के बीच समस्या निवारण दृष्टिकोण नहीं बनाया गया, बल्कि यह विभिन्न क्षेत्रों में नए उत्पाद और सेवा विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नवीन चुनौतियों का विकास करता है।

एआईएम की पहल ने नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को जन्म दिया जिसने 2015 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81 वें स्थान से 2021 में 46 की स्थिति में भारत की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

स्कूलों में एआईएम ने 12 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को प्रौद्योगिकी नवाचार की दुनिया से परिचित कराने के लिए अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं (एटीएल) का नेटवर्क स्थापित करने की सुविधा प्रदान की ताकि उन्हें भविष्य के प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों के साथ अवगत करवाया जा सके। नवंबर 2020 तक, एटीएल की स्थापना के लिए 14,916 स्कूलों का चयन किया गया था। इसके अलावा, 6,500 एटीएल स्वीकृत किए गए थे, जिसमें 110 आकांक्षी जिलों सहित 90% से अधिक जिले शामिल थे। सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में स्थापित ये प्रयोगशालाएं नवाचार के सामुदायिक केंद्र के रूप में काम कर रही हैं और नए भारत की रणनीति के अनुसार आने वाले समय में इनकी संख्या 10,000 से अधिक हो जाएंगी ताकि एमएसएमई क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित किया जा सके और उद्यमियों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जा सके। इसके तहत छोटे व्यवसाय के लिए, एआईएम ने एराईज और अटल न्यू इंडिया चैलेंज सहित कई चुनौतियों का शुभारंभ किया। भारतीय एमएसएमई और स्टार्टअप में अनुप्रयुक्त अनुसंधान और नवाचार की दिशा में यह प्रोत्साहन इस क्षेत्र से जुड़े मेक-इन-इंडिया नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए एक अग्रणी पहल है। जबकि एआईएम ने बड़े पैमाने पर समाज को नवाचार और प्रौद्योगिकी के लिए एक्सपोजर प्रदान किया, 'स्टार्टअप इंडिया' कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के लोगों की उद्यमशीलता क्षमता को बढ़ाना है और भारत की प्रतिभा को सपने देखने, उन्हें क्रियान्वित करने और उन्हें गेम चेंजिंग वेंचर्स में परिवर्तित करने में सक्षम बनाना था। इस प्रकार इसकों क्रियान्वित करते हुए, 16 जनवरी

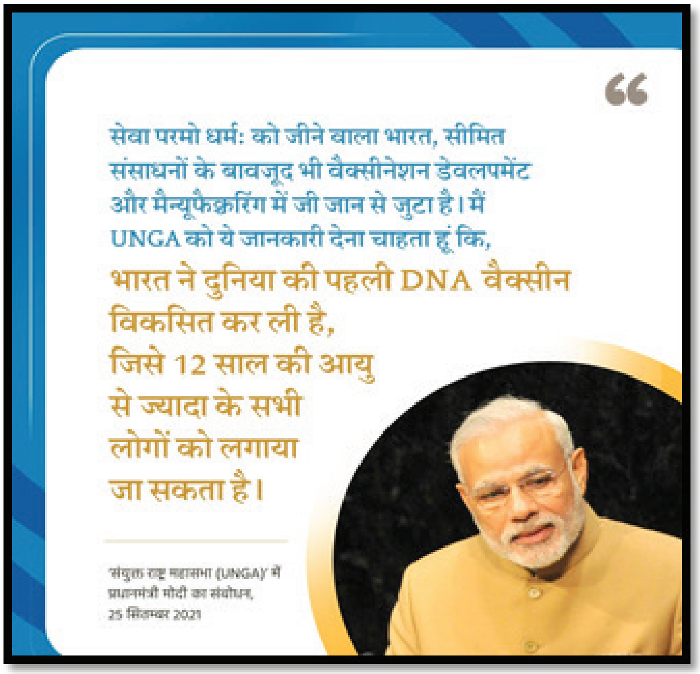

2016 को सरकार ने देश में नवाचार और स्टार्टअप के पोषण के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के उद्देश्य से 'स्टार्टअप इंडिया' कार्यक्रम शुरू किया, जो स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

'उद्यमिता समर्थक' दृष्टिकोण की दिशा में अपनी कार्य योजना को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से स्टार्टअप इंडिया ने एक त्रिस्तरीय रणनीति बनाई है- क) सूचना विषमता को कम करते हुए पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने के लिए एक साझा मंच की सुविधा, ख) लाभ प्रदान करने और अन्य आवश्यक समर्थन, और ग) अपने विचारों को व्यावसायिक उपक्रमों में बदलने के लिए क्षेत्रीय उद्यमियों को इसमें शामिल करना। जबकि पहले दो का उद्देश्य स्टार्टअप के लिए वन-स्टॉप शॉप प्रदान करना है, जिसमें वित्तीय प्रोत्साहन और अन्य लाभ प्राप्त करना शामिल है, तीसरे बिंदु का उद्देश्य आउटरीच और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से संदेश को महानगरों से टियर 2 और 3 तक ले जाना है। समग्र परिवर्तन में शहरों और क्षेत्रीय सरकारों को शामिल करना।

स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत कार्य योजना मुख्य रूप से उद्यमियों द्वारा अपने व्यवसायों के विभिन्न चरणों के दौरान सामना किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने और भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को विश्व स्तर पर सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र में से एक के रूप में विकसित करने

पर केंद्रित थी।

जनवरी 2016 में एक 19-सूत्रीय स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान शुरू किया गया था, जिसने भारतीय स्टार्टअप के लिए एक मजबूत, अनुकूल, विकासोन्मुख वातावरण बनाने के लिए कई नीतिगत पहलों की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया। माननीय प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया का अनावरण किया। 16 जनवरी 2021 को स्टार्टअप इंडिया के 5 साल पूरे होने पर भविष्य में स्टार्टअप्स को लेकर विभिन्न योजनाओं पर विचार किया गया, जिसमें व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने, विभिन्न सुधारों को क्रियान्वित करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका, हितधारकों की क्षमता निर्माण, एक डिजिटल आत्मानिर्भर भारत को सक्षम करना जैसे पहलू शामिल थे।

स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत और विभिन्न पहलों के बाद के कार्यान्वयन से समग्र स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में पर्याप्त सुधार हुआ है। इसके अलावा, भारत के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रैंकिंग में 2016 में 130 से 2020 में 63 तक एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई है, जिससे भारत में स्टार्टअप्स के प्रसार को और प्रोत्साहन मिला है। इसके अलावा भारत अब स्टार्ट-अप की संख्या के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश है। स्टार्ट-अप अनुकूल वातावरण को देखते हुए आने वाले वर्षों में यह संख्या तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा, गुजरात राज्य में प्रौद्योगिकी और नवाचार में प्रारंभिक निवेश को देखते हुए, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, यह भारत में स्टार्टअप के लिए सबसे अधिक मांग वाले राज्य के रूप में उभरा है। 14 जुलाई 2021 तक उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा 52,391 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है और 50,000 से अधिक स्टार्टअप द्वारा 5.7 लाख से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन किया गया है। अनुमानों के अनुसार, वर्तमान में भारत में 53 यूनिकॉर्न हैं, जिनका संभावित मूल्यांकन रु. 1.4 लाख करोड़ है।

गुजरात राज्य स्टार्टअप गंतव्यों सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक के रूप में उभरा है

- 8450 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हैं और 200 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता के साथ राज्य भर में 180 से अधिक केंद्रों या इनक्यूबेटरों का समर्थन किया है।
- विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में 100 से अधिक पेटेंट सूचना केंद्रों की स्थापना की।
- राज्य सरकार के समर्थन से 900 से अधिक पेटेंट दायर किए गए हैं।
- क्षेत्रीय और जिला स्तर पर 30 से अधिक वैज्ञानिक सामुदायिक केंद्रों की स्थापना की।
- विभिन्न कार्यक्रमों जैसे बूट कैंप, हैकाथॉन, त्वरण कार्यक्रम आदि आयोजित करने के लिए इनक्यूबेटरों और केंद्रों का समर्थन करना।
- स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए 'लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2017'।
- 2018 और 2019 में लगातार राष्ट्रीय स्टार्टअप रैंकिंग में 'सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन'

विकासशील देशों की सहायता

वसुधैव कुटुम्बकम (दुनिया एक परिवार है) के मूल्यों पर चलते हुए और अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री ने अपने पड़ोसियों के प्रति भारत सरकार की नीतियों को पेश किया, जिसमें 'पड़ोसी पहले' की भावना को जोड़ा गया था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया। इस प्रकार सरकार ने अपने सभी पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध विकसित करने और मजबूत संबंधों को विकसित करने के लिए अपने पड़ोसियों के साथ सभी मौजूदा मतभेदों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध दिखायी। प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले दो वर्षों के भीतर उन्होंने उनके साथ संबंध मजबूत करने के लिए कई पड़ोसी देशों का दौरा किया, 2014 में शपथ लेने के बाद वह अपनी पहली विदेश यात्रा पर भूटान गए। यहां तक कि "लुक ईस्ट पॉलिसी" को 'अधिनियम' के रूप में पुनः ब्रांडेड किया गया था। पूर्व नीति' विभिन्न स्तरों पर विशाल एशिया-प्रशांत क्षेत्र के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक राजनयिक पहल शुरू करने के लिए थी। इसने आसियान के साथ हमारे आर्थिक जुड़ाव को बढ़ाया- क्षेत्रीय एकीकरण और परियोजनाओं का कार्यान्वयन को हमारी प्राथमिकता बनाया। सेवा और निवेश में व्यापार पर आसियान-भारत समझौता 1 जुलाई 2015 से भारत और सात आसियान देशों के बीच लागू हुआ।

सभ्यता के समय से यथार्थवादी अंतरराष्ट्रीय राजनीति के ढांचे में वित्तीय और सांस्कृतिक संबंधों को विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हथियार मानते हुए, जहां उभरते देशों के बीच राजनीतिक संबंध आमतौर पर आर्थिक परिणामों और मूल्यों की समानता से निर्धारित

इस क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

- भारत आउटसोर्स अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बन गया है। वर्तमान में हमारे पास IBM, Google, Microsoft, Intel, Lupin, Wockhardt, आदि जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNC) द्वारा स्थापित 1,100 से अधिक शोध केंद्र हैं। ये शोध केंद्र सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, और एयरोस्पेस, ऑटोमोटिव सहित क्षेत्रों को कवर करते हैं। जो भारत की अपेक्षाकृत मजबूत बौद्धिक संपदा व्यवस्था एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास केंद्र के रूप में उभरने में मदद करेगी।
- भारतीय वैज्ञानिक कुछ वैश्विक महत्वपूर्ण कार्यों में सबसे आगे हैं। अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों का हालिया योगदान उत्साहजनक रहा है। उदाहरण के लिए, नौ भारतीय संस्थानों के 37 भारतीय वैज्ञानिकों ने 2017 में भौतिकी नोबेल पुरस्कार प्राप्त गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय वैज्ञानिकों ने भी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी (LIGO) में न्यूट्रॉन स्टार विलय की खोज में योगदान दिया।
- ब्रह्मोस का विकास, उन्नत वायु रक्षा सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल, विविध मिसाइल और रॉकेट सिस्टम, दूर से चलने वाले वाहन, हल्के लड़ाकू विमान, आदि सामरिक और रक्षा प्रौद्योगिकियों में भारत की प्रगति के शानदार उदाहरण हैं।
- अटल इनोवेशन मिशन (AIM) के तहत नीति आयोग ने देश भर में कुल 68 इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए हैं। कुछ एआईएम इन्क्यूबेटर डीप-टेक, एयरोस्पेस आदि से जुड़े क्षेत्रों से संबंधित हैं। कोडिसिया डिफेंस इनोवेशन और अटल इनक्यूबेशन सेंटर एक विशिष्ट इनक्यूबेटर है जो रक्षा नवाचारों और स्टार्ट-अप पर केंद्रित है।
- भारत अब उन मुट्ठी भर देशों में शुमार है जिनके पास अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्वसनीय क्षमताएं हैं। एसएलवी से एएसएलवी और पीएसएलवी को जीएसएलवी में अपग्रेड करना, पहला मून ऑर्बिटर प्रोजेक्ट चंद्रयान -1, मार्स ऑर्बिटर मिशन और हाल ही में 104 उपग्रहों का एक साथ लॉन्च भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं।
- भारत स्टार्टअप पेटेंट फाइलिंग फीस में 80% छूट और ट्रेडमार्क फाइलिंग फीस में 50% छूट दे रहा है। इसके अतिरिक्त, स्टार्टअप्स को पेटेंट देने में लगने वाले समय को कम करने के लिए पेटेंट आवेदनों की त्वरित जांच की सुविधा भी प्रदान की जाती है। स्टार्टअप्स को निःशुल्क सेवाएं प्रदान करने के लिए इस योजना के तहत मार्च 2021 तक 510 पेटेंट फैसिलिटेटर्स और 392 ट्रेडमार्क फैसिलिटेटर्स को पैनल में शामिल किया गया है।
- सरकार को उत्पाद और सेवाएं बेचने के लिए स्टार्टअप्स के लिए 'GeM स्टार्टअप रनवे' लॉन्च किया गया है। जून 2021 तक 10,154 स्टार्टअप ने GeM पोर्टल पर पंजीकरण किया है और 76,564 स्टार्टअप को ऑर्डर दिए गए हैं। स्टार्टअप्स द्वारा दिए गए ऑर्डर का मूल्य लगभग 3,481 करोड़ रुपये है।
- स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप 6 श्रम कानूनों और 3 पर्यावरण कानूनों के लिए अपने अनुपालन को स्व-प्रमाणित कर सकते हैं।
- वित्त अधिनियम, 2020 आयकर अधिनियम की धारा 80-आईएसी में संशोधन का प्रावधान करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त धारा के तहत कटौती एक योग्य स्टार्ट-अप के लिए लगातार 3 मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध होगी। उस वर्ष से शुरू होने वाले 10 वर्षों में से जिसमें इसे शामिल किया गया है। जून 2021 तक 387 स्टार्टअप को आयकर में छूट दी गई है।
- कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर 14वें और 15वें वित्त आयोग में 10,000 करोड़ रुपये के कुल कोष के साथ स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस) की स्थापना की गई थी। इसका प्रबंधन सिडबी द्वारा किया जाता है। 02 जून 2021 तक सिडबी ने रु 5409.45 करोड़ से 71 सेबी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ)में निवेश का लक्ष्य रखा है।
- स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना का उद्देश्य स्टार्टअप को अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। भारत भर में पात्र इन्क्यूबेटरों के माध्यम से योग्य स्टार्टअप्स को सीड फंडिंग प्रदान करने के लिए अगले 4 वर्षों में 945 करोड़ रुपये की राशि को विभाजित किया जाएगा। इस योजना से लगभग 3600 स्टार्टअप को समर्थन मिलने की उम्मीद है।
- राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 लॉन्च किया गया है। महामारी के दौरान अभूतपूर्व चुनौतियों की अवधि में स्टार्टअप्स द्वारा प्रदर्शित प्रयासों, पहलों और लचीलेपन को स्वीकार करते हुए, एनएसए 2021 में अतिरिक्त श्रेणियां पेश की गई हैं। इसका उद्देश्य आत्मानिर्भर भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नवाचारों को पहचानना भी है।
- भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को अब व्यापक रूप से तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में मान्यता प्राप्त है। 14 जुलाई 2021 तक उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा 52,391 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है और 14 जुलाई 2021 तक 50,000 से अधिक स्टार्टअप द्वारा 5.7 लाख से अधिक रोजगार के आवसरों का सृजन किया गया। एक अनुमानों के अनुसार, वर्तमान में भारत में 53 यूनिकॉर्न हैं, जिनका संभावित मूल्यांकन रु. 1.4 लाख करोड़ है।

होते हैं, केंद्र सरकार ने अन्य देशों की मदद करना शुरू कर दिया, विशेष रूप से पड़ोसी देशों के साथ यह सहयोग आगे बढ़ने लगा। इसके लिए गैर-पारस्परिक और परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण को अपनाया गया है, जबकि नए शुभचिंतकों को बनाने के लिए प्रत्यक्ष प्रोत्साहन के रूप में भी कार्य किया गया।

भारत की सहायता उसके भागीदार राष्ट्रों की आवश्यकताओं पर आधारित है, और इसका उद्देश्य तकनीकी और वित्तीय रूप से इन देशों के अधिक से अधिक अनुरोधों को पूरा करना है। लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी), अनुदान सहायता, लघु विकास परियोजनाएं (एसडीपी), तकनीकी परामर्श, आपदा राहत और मानवीय सहायता, साथ ही भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत क्षमता निर्माण कार्यक्रम भारत की विकास सहायता के प्रमुख उपकरण हैं।

नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत अपने पड़ोसियों की सहायता भारत के संबंधों का एक अनिवार्य हिस्सा था। क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं, जो लोगों से लोगों के बीच संपर्क और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देते हुए क्षेत्रीय विकास और विकास के लिए गुणक के रूप में कार्य करते हैं, पर विशेष ध्यान दिया गया। भारत सरकार द्वारा भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (IDEAS) के तहत एक्ज़िम बैंक ऑफ़ इंडिया के माध्यम से रियायती लाइन ऑफ़ क्रेडिट के रूप में विकास सहायता प्रदान की।

जहां तक सहायता अनुदान का संबंध है, पिछले पांच वर्षों में सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, मॉरीशस और सेशेल्स को सहायता अनुदान के माध्यम कनेक्टिविटी, ऊर्जा, सड़कें, कृषि, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, संस्कृति, क्षमता निर्माण, सुरक्षा और प्रशिक्षण पहलों में मदद की है। ये पहल अपने पड़ोसियों की विकास मांगों के साथ-साथ क्षेत्र में इसके व्यापक रणनीतिक हितों को देखते हुए की गयी हैं।

इसके अलावा, भारत अपने सभी पड़ोसियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, आपदा प्रबंधन और आजीविका विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं (एचआईसीडीपी) के निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

इस क्षेत्र की कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं

1. नेपाल:

मोतिहारी (भारत) से अमलेखगंज (नेपाल) पर पहली सीमा पार पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन।

व्यापार और लोगों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस विराटनगर, बीरगंज, नेपालगंज और भैरहवा में फिट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण।

तराई रोड परियोजना।

जयनगर-बिजलपुरा-बरदीबास रेल लिंक।

जोगबनी-विराटनगर रेल लिंक और रक्सौल-काठमांडू रेल लिंक।

पनौती में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का निर्माण।

हेटौडा में नेपाल भारत मैत्री पॉलिटेक्निक संस्थान।

70 हायर सेकेंडरी स्कूलों और करीब 147 स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण।

2. बांग्लादेश

12 किमी अगरतला-अखौरा रेल लिंक।

अंतर्देशीय जलमार्गों का निर्माण।

भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन और भारत-बांग्लादेश मैत्री सेतु का निर्माण। भारत 109 एम्बुलेंस की आपूर्ति भी कर रहा है।

3. म्यांमार

कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और भारत, म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ने वाला त्रिपक्षीय राजमार्ग।

यामेथिन में महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र का उन्नयन।

रखाइन राज्य विकास कार्यक्रम (आरएसडीपी) को पुनर्निर्माण सहायता और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम को सहायता।

4. अफगानिस्तान

हबीबिया स्कूल और काबुल में इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्थान को सहायता अनुदान।

शतूत बांध परियोजना।

सलमा बांध परियोजना

अफगानिस्तान की संसद का निर्माण।

स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति/पुरानी बसों का नवीनीकरण।

बंद-ए-आमिर को बामयान-याकावलंग राजमार्ग से जोड़ने वाली 16.9 किलोमीटर सड़क का पुनर्वास।

अफगान शरणार्थियों की वापसी के लिए 4000 घरों का निर्माण।

कंधार में अफगान राष्ट्रीय कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (ANASTU) की स्थापना।

5. श्रीलंका

श्रीलंका के विभिन्न हिस्सों में 60 से अधिक अनुदान परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और 20 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न

चरणों में हैं। इसमें इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट भी शामिल है।

आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा।

जाफना सांस्कृतिक केंद्र (जेसीसी)।

हटोना में डिकोया अस्पताल।

उत्तरी प्रांत में 27 स्कूलों का नवीनीकरण।

पोलोनारुवा में बहु-जातीय त्रि-भाषी विद्यालय का निर्माण।

बट्टिकलोआ टीचिंग हॉस्पिटल में सर्जिकल यूनिट का निर्माण।

श्री दलदा मालिगावा के तहत पल्लेकेले में कंडियन नृत्य संकाय के लिए भवनों का निर्माण और 28 संस्कृति विरासत स्थलों का जीर्णोद्धार।

6. मालदीव

भारत नियंत्रण रेखा के माध्यम से मालदीव में 34 द्वीपों के लिए जल और सीवरेज सुविधाओं के माध्यम से 9 बड़े बुनियादी ढांचे और सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अड्डू के सबसे दक्षिणी प्रवाल द्वीप में सड़क और सुधार।

हुलहुमले में क्रिकेट स्टेडियम।

सार्वजनिक क्षेत्र के मत्स्य प्रसंस्करण उद्योग का उन्नयन।

मौजूदा माले बंदरगाह से भीड़भाड़ कम करने के लिए गुलहीफाल्हू में एक नए बंदरगाह का निर्माण।

ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (जीएमसीपी) के तहत पुलों और सेतुओं के नेटवर्क का निर्माण।

हनीमाधू हवाई अड्डे का विस्तार और अड्डू में गण हवाई अड्डे का विस्तार। इसके अलावा, भारत उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं (एचआईसीडीपी) सहित अनुदान योजनाओं के तहत 30 से अधिक सामुदायिक स्तर की परियोजनाओं का समर्थन कर रहा है।

सुरक्षा और कानून प्रवर्तन अध्ययन संस्थान (आईएसएलईएस) का निर्माण और 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय पैकेज जिससे दिसंबर 2019 में बढ़ाया गया है जिसमें बजटीय सहायता, ट्रेजरी बिलों में निवेश, मुद्रा स्वैप और लाइन ऑफ क्रेडिट शामिल हैं।

7. भूटान

द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए व्यापार सहायता सुविधा के लिए वित्तीय सहायता।

मौजूदा तीन जल विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण और अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता।

उपरोक्त सहायता के अलावा भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के बाद अपने पड़ोसियों की आर्थिक स्थिति करने के लिए कई कदम उठाए। भारत ने जुलाई 2020 तक आरबीआई और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के बीच यूएस 400 मिलियन डॉलर का मुद्रा स्वैप समझौते का विस्तार करके मालदीव की सहायता की है। भारतीय स्टेट बैंक ने भी वित्तीय सहायता की पेशकश की है, जिसके तहत वह मालदीव सरकार के बांडों में एक रियायती निवेश के रूप में 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि देगा। इसके अलावा, अगस्त 2020 में भारत और मालदीव के बीच हवाई यात्रा बबल का निर्माण किया जाएगा। यह उद्योग को पुनर्जीवित करके उसकी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर मालदीव की सहायता करेगा।

कोविड-19 महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में श्रीलंका को भारत से सहायता मिली है। जिसके तहत श्रीलंका को कोविड-19 महामारी के दौरान देश की वित्तीय स्थिरता की रक्षा के लिए 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान की है।

इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व प्रभाव को कम करने के लिए, जी20 देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने आधिकारिक द्विपक्षीय लेनदारों के मुद्दे पर सबसे गरीब देशों के लिए ऋण सेवा भुगतान को निलंबित करने के मुद्दे पर सहमति व्यक्त की, जिसका निर्णय 15 अप्रैल को एक बैठक में हुआ। भारत सरकार ने G20 डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव के अनुरूप पड़ोसी देशों को कर्ज निलंबन सहायता दी है।

भारत ने अपने पड़ोसियों को महत्वपूर्ण दवाएं, चिकित्सा आपूर्ति और भोजन भी उपलब्ध कराया है। कोविड -19 महामारी के दौरान भारत ने दवाओं, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), परीक्षण किट और चिकित्सा उपकरणों के रूप में चिकित्सा सहायता / मानवीय राहत के तौर पर लगभग 20.1 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है।

टीकाकरण की उपलब्धता/अनुमोदन के साथ भारत ने अपने पड़ोसी देशों को "मेड इन इंडिया" टीकों के रूप में विकासात्मक सहायता प्रदान की है।

वैक्सीन मैत्री

भारतीय सॉफ्ट पावर को सार्वभौमिक बनाने की क्षमता हाल ही में वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान स्पष्ट तौर पर सामने आयी, जिसमें भारत अपने परिवार के रूप में दुनिया की रक्षा करने के लिए आगे आया है। मोदी जी के नेतृत्व में 'भारतीय सांस्कृतिक

परंपराओं पर निर्भरता' ने 'वैकल्पिक वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं पर नए विचारों को विकसित करने' और 'वैश्विक व्यवस्था की साझा दृष्टि के निर्माण में योगदान' की क्षमता को बढ़ाया है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और एकजुटता, जैसा कि भारतीय विरासत की रेखांकित अवधारणा, वैश्विक महामारी जैसी स्थितियों में सबसे अधिक दिखायी देती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नजरिये ने हमारे देशों को यमन, नेपाल, मोजाम्बिक या फिजी में मानवीय सहायता और आपदा प्रतिक्रियाओं में परिलक्षित व्यावहारिक पहल और गतिविधियों के संदर्भ में एक अग्रणी देश बनाने की पहल की है।

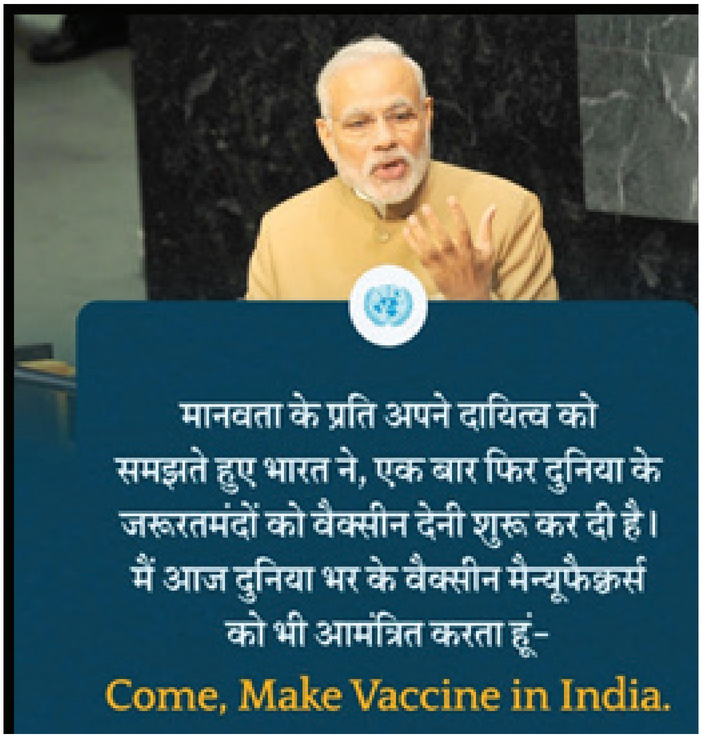

स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत के वैक्सीन मैत्री ऑपरेशन ने एक परिवार के रूप में इस मुद्दे को सामूहिक रूप से संबोधित करने के लिए दुनिया के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है। जैसे, 'वसुधैव कुटुम्बकम' के दर्शन को दुनिया भर में पहचान मिली है। यह भारत की पहल के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सकारात्मक प्रतिक्रिया में परिलक्षित होता है। इस मानवीय पहल के हिस्से के रूप में भारत दुनिया भर के देशों को भारत निर्मित टीकों की आपूर्ति और दान कर रहा है, जिसमें हमारे पड़ोसी देश मालदीव और भूटान पहले प्राप्तकर्ता बन गए हैं, जो पीएम की "पड़ोसी पहले" नीति के अनुरूप है, जिसे उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में बताया था।

भारत द्वारा बांग्लादेश को उपहार में दी गई दो मिलियन खुराक भारत द्वारा किसी भी देश को उपलब्ध कराए गए टीकों की अब तक की सबसे बड़ी खेप थी, जिस पर बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्री ने टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान और आज इस महामारी के प्रकोप के बीच उनके देश के साथ खड़ा रहा। भारत ने अपने पड़ोसी देशों के अलावा, करीबी रणनीतिक साझेदार ब्राजील और मोरक्को को भी 22 जनवरी को 2 मिलियन खुराक दीं। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने प्रधानमंत्री मोदी जी को वैक्सीन की आपूर्ति भेजने के लिए धन्यवाद दिया और इसकी तुलना भगवान के साथ की। हनुमान पवित्र 'संजीवनी' ला रहे हैं। डोमिनिकन गणराज्य के प्रधान मंत्री रूजवेल्ट स्केरिट ने कहा भारत से 'बड़ी विनम्रता और सम्मान के साथ...हमारी आबादी को सुरक्षित बनाने के लिए' सहायता का मिली है।

इसके अलावा अमेरिकी विदेश विभाग, डब्ल्यूएचओ, बिल गेट्स और कई अन्य लोगों ने निस्वार्थ तरीके विकासशील देशों को टीका उपलब्ध कराने के लिए भारत की सराहना की है। भारत न केवल इस चुनौती से निपटने में सफल रहा, बल्कि 150 से अधिक देशों को चिकित्सा और अन्य सहायता और 95 देशों को वैक्सीन प्रदान की। इस तरह का व्यवहार भारतीयों की सच्ची भावना और ताकत को प्रदर्शित करती हैं और इस बात पर भी मुहर लगाती है कि भारत अपने हितों की रक्षा के अलावा दुनिया की परवाह करता है। तकनीकी पहलुओं के संदर्भ में 142 देशों, 20 दूतावासों और संयुक्त राष्ट्र के 400 प्रतिभागियों की सभा के साथ ऐतिहासिक ग्लोबल कोविन कॉन्क्लेव भारत के 'वसुधैव कुटुम्बकम' के प्राचीन दर्शन का एक उदाहरण था है। भारत के कोविड—19 टीकाकरण अभियान के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म CoWIN को सभी देशों के उपयोग, अनुकूलन और उपयोग के लिए एक खुला स्रोत बनाया गया था।

यह शायद पहली बार था कि किसी देश ने सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म को दुनिया के लिए खुला बनाया है। जैसे ही स्वदेशी रूप से विकसित CoWIN प्लेटफॉर्म ग्लोबल हो गया है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मैक्सिको सहित 50 से अधिक देशों ने इसमें रुचि दिखाई है। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 76वें सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की स्थिति पर प्रकाश डाला। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा में प्रगति और नवाचार को लेकर घोषणा की कि भारत ने दुनिया का पहला डीएनए वैक्सीन विकसित

किया है, जिसे 12 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, और एक एमआरएनए वैक्सीन जो विकास के अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि कोविड वैक्सीन निर्माता भारत में आकर निवेश करें।

एक ओर, इस वैश्विक संकट ने हमें सिखाया कि जोखिम प्रबंधन और शमन दोनों के लिए वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य में रुचि और निवेश को फिर से सक्रिय करने के लिए वैश्विक साझेदारी को और गहरा करने की आवश्यकता होगी और दूसरी ओर, हमें अधिक लचीला और बेहतर तैयार होने की सीख प्रदान की। भारत सरकार ने इसके प्रकोप के बाद से कोविड -19 के प्रभाव को कम करने के लिए कड़ी मेहनत की और वैश्विक महामारी को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत के पुनरुत्थान ने अन्य देशों के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है। निस्संदेह, भारत ने दुनिया को करुणा का मार्ग दिखाया है और दुनिया को एक परिवार के रूप में खुले तौर पर गले लगाया है, जो 'वसुधैव कुटुम्बकम' का मूल दर्शन है। अब, दुनिया को पता चल गया है कि वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए सामूहिक और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।

बचाव अभियान

सांस्कृतिक पहुंच के साथ-साथ भारतीय कूटनीति का मानवीय और करुणामय चेहरा असंख्य तरीकों से दुनिया के सामने आया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपने नागरिकों को बचाने और विदेशों में बचाव और राहत कार्यों को कुशलतापूर्वक चलाने का एक शानदार रिकॉर्ड है। भारत "वसुधैव कुटुम्बकम" (दुनिया एक परिवार है) में विश्वास करता है और इसके सभी मानवीय मिशन इस सिद्धांत द्वारा निर्देशित किए गए हैं। पिछले सात वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में संकट और संघर्ष की स्थितियों में फंसे भारतीयों तक पहुंचने के लिए सक्रिय प्रयास किए गए। उदाहरण के लिए, ऑपरेशन राहत के तहत यमन संकट (2015) के दौरान बचाव अभियान, जिसमें 4,748 भारतीयों और 48 देशों के 1,962 नागरिकों को बचाया गया था। मोदी सरकार ने 2015 में नेपाल में आए भूकंप के बाद ऑपरेशन मैत्री के माध्यम से अब तक की सबसे बड़ी आपदा राहत सहायता प्रदान की है। इसी भावना से सरकार ने दुनिया भर में 30 मिलियन भारतीय प्रवासियों तक भी पहुंच बनाई है, जिससे उनकी भावना को फिर से जागृत किया गया है। भारत और राष्ट्रीय पुनरुत्थान के मिशन में उनके समर्थन को सूचीबद्ध किया। वैश्विक महामारी की अनिश्चित अवधि के दौरान भारत ने वंदे भारत मिशन के तहत लोगों को महामारी से बचाने के लिए अभ्यास किया, जिसमें कोविड-19 के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाना शुरू किया गया और यह आपरेशन एक देश द्वारा नागरिकों की सबसे बड़ी निकासी में से एक बन गया। पिछले साल जुलाई के अंत तक भारत ने दुनिया भर में 88,000 से अधिक उड़ानों का संचालन किया था, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी हर सावधानी बरती गई थी और डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देशों का पालन किया गया था। वंदे भारत मिशन के तहत 100 से अधिक देशों को कवर किया गया और लगभग 70 लाख भारतीयों को स्वदेश लाया गया। और इतना ही नहीं - कई भारतीयों को वुहान से निकाला गया, जो कि कोविड -19 के प्रकोप का उपरिकेंद्र था। भारत ने हाल ही में ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत काबुल से अपने नागरिकों और अफगान भागीदारों को निकालने के लिए एक जटिल मिशन चलाया। भारत सरकार ने न केवल भारतीयों को बल्कि अफगानिस्तान से अन्य देशों के नागरिकों को भी बचाया।

2014 के बाद से भारतीयों की निकासी और बचाव की ये सभी असाधारण प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रत्यक्ष देखरेख में किये गये हैं और संकट के दौरान भारत के धैर्य और सफल राजनयिक हस्तक्षेप को दर्शाती हैं। महामारी के दौरान यूक्रेन से सैकड़ों भारतीय छात्रों का बचाव हो या इराक और सीरिया से भारतीयों की निकासी, मोदी सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए दृढ़ है। इस प्रकार भारत सरकार ने दुनिया को दिखाया है कि जब उसके नागरिक विदेश में फंसे होते हैं तो उस संकटों का तेजी से कैसे जवाब दिया जाता है। पिछले सात वर्षों में दुनिया भर में संकटग्रस्त इलाकों से भारतीयों की लगातार सफल निकासी ने हमारे नागरिकों को विश्वास दिलाया है कि आज हमारे पास एक मजबूत सरकार और एक वैश्विक नेता है जो अपने लोगों को बचाना और उनके हितों की रक्षा करना जानता है।

वैश्विक मुद्दों को सुलझाने में भारत की भूमिका

2016 में गोवा में ब्रिक्स की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के विषय को संबोधित करते हुए कहा, "यह सभी सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे अपनी सीमाओं से आतंकवादी कृत्यों को रोकें।" ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से आतंकवाद द्वारा प्रस्तुत खतरे को स्वीकार किया और कहा कि सीमा पार आतंकवाद और उसके समर्थकों का मुकाबला करना समूह के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

गोवा घोषणापत्र ने सभी राज्यों से न केवल प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने का आग्रह किया, बल्कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन (सीसीआईटी) को जल्द से जल्द मंजूरी देने का भी आग्रह किया। आतंकवाद पर ब्रिक्स संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई और 14 सितंबर, 2016 को नई दिल्ली में इसकी उद्घाटन बैठक आयोजित की गई थी। नतीजतन, सार्क में पाकिस्तान राजनीतिक रूप से अलग-थलग पड़ गया, दक्षिण कोरिया ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से अपना निवेश वापस ले लिया और अंतरराष्ट्रीय मदद रोक दी गई।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के सहयोगियों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध सूची (मई 2019) में मसूद अजहर को इसमें शामिल करवाया।

विकासशील देशों में परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए 100 मिलियन डॉलर फंड सुविधा "भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी निधि" जून 2017 में संयुक्त राष्ट्र के पहले एकल-देश दक्षिण-दक्षिण सहयोग कार्यक्रम के रूप में स्थापित की गई थी। अप्रैल 2018 में फंड ने कॉमनवेल्थ गरीब देशों में एसडीजी से संबंधित पहल की जिसके लिए 50 मिलियन डॉलर कॉमनवेल्थ विंडो की स्थापना की गई।

अनुसंधान के क्षेत्र में ब्रिटेन पहले से ही भारत का दूसरा सबसे बड़ा भागीदार है, दोनों देशों के बीच विज्ञान और नवाचार में सहयोगात्मक निवेश पिछले दशक की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए इस तरह के एक रिश्ते का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा भारत और यूनाइटेड किंगडम ने अफ्रीका को एक प्रमुख स्थान के रूप में चुना है जिसमें उनका लक्ष्य अपने तीसरे देश के सहयोग का विस्तार करना है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 74वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी (22-27 सितंबर 2019) ने किया। पीएम ने उच्च स्तरीय कार्यक्रमों जैसे क्लाइमेट एक्शन समिट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर उच्च स्तरीय बैठक और आतंकवादी और हिंसक चरमपंथी घटनाओं पर नेताओं की बातचीत में भाग लिया। पीएम ने डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर (सीडीआरआई) और "लीडरशिप ग्रुप" के लिए गठबंधन के गठन की भी घोषणा की, जिसे भारत ने क्लाइमेट एक्शन समिट में स्वीडन के साथ सह-नेतृत्व किया। पीएम ने अपने संयुक्त राष्ट्र महासभा दौरे के दौरान दो महत्वपूर्ण बहुपक्षीय कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें प्रशांत छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (PSIDS) के नेताओं के साथ एक बैठक (24 सितंबर 2019) और कैरेबियन समुदाय (CARICOM) के नेताओं के साथ एक बैठक (25 सितंबर 2019) शामिल है। यह पहली बार था जब ये समूह शिखर सम्मेलन स्तर पर मिले, और प्रधानमंत्री ने इन राष्ट्रों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए कई पहलों की रूपरेखा तैयार की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए प्रशासन ने 'विकासात्मक कूटनीति' विकसित की है, जो विकास संबंधी आवश्यकताओं पर आधारित कूटनीति है। भारत के गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) मुख्यालय के निर्माण के साथ, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) ने अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में समानता और न्यायपूर्ण ऊर्जा व्यवस्था के लिए रास्ता खोलकर भू-राजनीतिक महत्व हासिल कर लिया है। सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में अपने सचिवालय के साथ आईएसए के बाद दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) की स्थापना की।

अक्टूबर 2020 में, ISA ने अपनी तीसरी सभा का आयोजन किया, जिसमें ISA के चार सदस्य मंत्रालयों ने भाग लिया। सभा में 53 सदस्य देशों के साथ-साथ 5 हस्ताक्षरकर्ता और भावी सदस्य देशों ने भाग लिया। विश्वव्यापी महामारी के बाद में ISA ने ISA CARES लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य LDC/SIDS ISA सदस्य देशों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम का लक्ष्य सदस्य देशों के जिलों में से प्रत्येक में एक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को सोलराइज करना है।

हर साल आईएसए की वैश्विक पहुंच बढ़ती जा रही है, जैसा कि वित्तपोषण और प्रौद्योगिकी की लागत को कम करने, बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परिनियोजन के लिए निवेश जुटाने, और भविष्य की प्रौद्योगिकियों के लिए मार्ग प्रशस्त करने का लक्ष्य है जो वर्तमान समय के अनुकूल हैं। 2019 में दूसरी सभा के बाद से आईएसए की सदस्यता में वृद्धि जारी है, और संगठन में अब 68 सदस्य राष्ट्र हैं, अन्य 20 देश शामिल होने के कगार पर हैं। जहाँ तक धरती माता के संरक्षण का सवाल है, भारत कुछ जी20 देशों में से एक है, जो देश पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने की राह पर हैं। ◆

भारत ने विशेषज्ञों और डब्ल्यूएचओ मानकों की सलाह के आधार पर चरणबद्ध टीकाकरण के विश्व स्तर पर स्वीकृत मानदंडों का पालन किया:

- पहला चरण: हेल्थकेयर/फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण
- दूसरा चरण: 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक/कॉमरेडिटीज
- तीसरा चरण: 45 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक
- चौथा चरण: सभी वयस्क नागरिक का टीकाकरण
- 1 अक्टूबर, 2021 तक प्रशासित कुल टीके 890 मिलियन से अधिक हैं। इस उपलब्धि की उल्लेखनीय प्रकृति को समझने के लिए हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि भारत द्वारा प्रशासित खुराक की कुल संख्या विकसित पश्चिमी देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका (330 मिलियन), कनाडा (38 मिलियन), यूके (67 मिलियन) और जर्मनी (83 मिलियन) की पूरी आबादी से अधिक है। 17 सितंबर 2021 को भारत ने एक ही दिन में वैक्सीन की 25 मिलियन खुराक दी जो ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी के लगभग बराबर है।
- भारत के सामने चुनौती पश्चिमी दुनिया की तुलना में बहुत बड़ी है और पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के साथ-साथ तेजी से वैक्सीन विकास ने भारत को इस चुनौती से लड़ने में सक्षम बनाया है।

वैक्सीन विकास:

- 9 महीने की छोटी अवधि के भीतर, दो मेड-इन-इंडिया टीके (कोविशील्ड और कोवैक्सिन) विकसित और स्वीकृत किए गए और फिर जनवरी 2021 से प्रशासित किए गए।
- जाइडस कैडिला, जॉनसन एंड जॉनसन और बायोलॉजिकल-ई के टीके भी पाइपलाइन में हैं।
- उपरोक्त के अलावा स्पुतनिक-वी और मॉडर्न वैक्सीन को भी मंजूरी मिल चुकी है।
- भारत ने दुनिया का पहला डीएनए वैक्सीन विकसित किया है, जिसे 12 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, और एक एमआरएनए वैक्सीन जो विकास के अंतिम चरण में है।

सार्क नेटवर्क को मजबूत बनाना:

- मार्च 2020 में जब कोविड-19 वायरस ने पहली बार देश को प्रभावित किया, तब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सार्क देशों से कोरोनावायरस से लड़ने के लिए एक मजबूत रणनीति तैयार करने का आह्वान किया। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि इन रणनीतियों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की जा सकती है और सार्क राष्ट्र एक साथ आकर दुनिया के लिए एक उदाहरण स्थापित कर सकते हैं और एक स्वस्थ ग्रह के निर्माण के लिए योगदान कर सकते हैं।
- उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सार्क सदस्य देशों की सरकारों के प्रमुखों के बीच पहली बार वीडियो सम्मेलन को संबोधित करते हुए सार्क देशों के लिए कोविड-19 आपातकालीन कोष के लिए भारत के योगदान के रूप में 10 मिलियन डॉलर का प्रस्ताव रखा।
- अन्य पहलों में सार्क वीडियोकांफ्रेंसिंग से पहले ही भारत ने महामारी से लड़ने में सहायता करने के लिए डॉक्टरों और पैरामेडिक्स सहित अपने रक्षा बलों से 14 सदस्यीय चिकित्सा दल को मालदीव भेजा था। यह पहल महत्वपूर्ण है क्योंकि शायद यह किसी दूसरे देश में जाने वाली पहली भारतीय चिकित्सा टीम है।
- भारत ने कोविड-19 के प्रकोप से लड़ने में नेपाल की सहायता के लिए चिकित्सा पेशेवरों की एक रैपिड रिस्पांस टीम (RRT) भेजने का भी प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा असाधारण नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए भारत ने मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, अमेरिका, मेडागास्कर, श्रीलंका, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका और पेरू सहित अन्य देशों के 50 से अधिक नागरिकों को बचाव अभियान के तहत निकाला।

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो पड़ोसी देशों- म्यांमार और नेपाल के साथ स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR), भारत और म्यांमार के स्वास्थ्य और खेल मंत्रालय के चिकित्सा अनुसंधान विभाग (DMR) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के उद्देश्य में संक्रामक रोगों के उन्मूलन के साथ-साथ नेटवर्क के विकास जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं।
- इसके अलावा, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), भारत और नेपाल स्वास्थ्य अनुसंधान परिषद (एनएचआरसी), नेपाल के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) सीमा पार स्वास्थ्य मुद्दों जैसे पारस्परिक हित की संयुक्त अनुसंधान गतिविधियों पर सहयोग पर जोर देता है। जिसमें आयुर्वेद/पारंपरिक चिकित्सा और औषधीय पौधे, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य, साथ ही मानसिक स्वास्थ्य शामिल है।

2014 के बाद के कुछ बचाव अभियान

- जून-जुलाई 2014 का "ऑपरेशन संकट मोचन" जिसमें 46 भारतीय नर्सों को युद्ध से तबाह इराक में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) के चंगुल से निकाला गया था।
- अप्रैल 2015 में भारतीय नौसेना और वायु सेना ने 4,600 से अधिक भारतीयों और 41 देशों के 950 से अधिक नागरिकों के तारणहार बनी। भारत ने सऊदी अरब द्वारा सैन्य हस्तक्षेप के बाद यमन संकट के बीच अपने नागरिकों को निकालने के लिए "ऑपरेशन राहत" चलाया।
- मोदी सरकार ने 2015 में नेपाल भूकंप के बाद ऑपरेशन मैत्री के माध्यम से अब तक की सबसे बड़ी आपदा राहत सहायता की।
- 2017 में बांग्लादेश राहत अभियानः पूर्वानुमान के आधार पर आईएनएस सुमित्रा को चक्रवात 'मोरा' के बाद में तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए बंगाल की उत्तरी खाड़ी में तैनात किया गया था। इस तैनाती के दौरान जहाज ने समुद्र में फंसे 33 बांग्लादेशियों को बचाया और एक शव भी बरामद किया। समुद्र में खोज और बचाव अभियान पूरा होने पर सुमित्रा एचएडीआर सहायता प्रदान करने के लिए 01 जून 17 को चटगांव में प्रवेश किया। बांग्लादेश सरकार ने कठिन परिस्थितियों में बांग्लादेशी नागरिकों को समुद्र में बचाने और राहत सामग्री के लिए भारत सरकार और आईएन जहाज सुमित्रा के चालक दल के सदस्यों का आभार व्यक्त किया।
- ऑपरेशन संकल्प (2020): खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते अमेरिका-ईरान तनाव के बीच जून 2019 में भारतीय ध्वज मर्चेंट वेसल्स (आईएफएमवी) के सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा ऑपरेशन कोड-नाम ओप संकल्प शुरू किया गया। इस आपरेशन के बाद से आईएन ने 16 युद्धपोतों को तैनात किया है और 156 आईएफएमवी पर लगभग 161 लाख टन कार्गो को एस्कॉर्ट किया है, जिससे हमारे नाविकों में आश्वासन की भावना प्रदान हुई है।
- ऑपरेशन समुद्र सेतु (2020): भारतीय जहाजों जलाश्व शार्दुल, ऐरावत और मगर को ईरान, मालदीव और श्रीलंका से कोविड-19 के मद्देनजर फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापिस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु मई – जुलाई 2020 के बीच शुरु किया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु के लिए तैनात आईएन जहाजों ने 3551 पुरुषों, 387 महिलाओं और 54 बच्चों सहित 3992 भारतीय नागरिकों को निकाला।
- जनवरी 2020 में आईएन ऐरावत, जिसे दक्षिण पश्चिमी आईओआर में तैनात किया गया था, को चक्रवात डायने के कारण हुई तबाही के बाद प्रभावित आबादी को एचएडीआर प्रदान करने के लिए 'ऑपरेशन वेनिला' के लिए अंतसिरानाना, मेडागास्कर की ओर मोड़ दिया गया था। मेडागास्कर गणराज्य के प्रधानमंत्री, महामहिम क्रिश्चियन लोइस नत्से की उपस्थिति में आपदा राहत भंडार, कपड़े, भोजन और दवाओं से युक्त राहत सामग्री 01 फरवरी 2020 को मेडागास्कर सरकार को सौंपी गई थी। इसके अलावा आईएन जहाज शार्दुल को दक्षिण में तैनात किया गया था। मार्च 2020 में पश्चिमी आईओआर ने देश में बाढ़ की स्थिति में अंतसिरानाना, मेडागास्कर को 600 टन चावल वितरित किए।
- एमवी वाकाशियो की ग्राउंडिंग के कारण होने वाले पर्यावरणीय खतरे की पृष्ठभूमि में मॉरीशस सरकार को सहायता प्रदान करने के लिए आईएनएस पर्यवेक्षक को 13 अगस्त से 18 सितंबर, 2020 तक तैनात किया गया था। जहाज ने नाविकों को समुद्री सुरक्षा, खोज और बचाव कवर प्रदान किया और गोताखोरी कार्यों के लिए सहायता भी प्रदान की। जहाज ने खराब मौसम की स्थिति में रात में डाइविंग ऑपरेशन भी किया। मॉरीशस सरकार की तेल रिसाव आकस्मिक योजना के समर्थन में डूबे हुए टग के चारों ओर भारी सीमेंट ब्लॉक लगाए थे।
- तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने की स्थिति में ऑपरेशन देवी शक्ति (2021) के तहत काबुल से अपने नागरिकों और अफगान भागीदारों को निकालने के लिए एक जटिल मिशन को अंजाम दिया गया। भारत सरकार ने न केवल भारतीयों को बल्कि अफगानिस्तान से अन्य देशों के नागरिकों को भी निकाला।

अभूतपूर्व आउटरीच

क्वाड समिट

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्वास व्यक्त किया कि क्वाड के चार लोकतांत्रिक देश, जिसे 'एशियाई' या 'मिनी नाटो' के रूप में भी जाना जाता है, के सहयोग से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि सुनिश्चित होगी।

एससीओ शिखर सम्मेलन

भारत, एक महत्वपूर्ण वैश्विक शक्ति के रूप में, भू-राजनीतिक पुनर्गठन को संतुलित कर रहा है और रूस और अन्य मध्य एशियाई सदस्य देशों के साथ एससीओ में एक महत्वपूर्ण भागीदार के तौर पर शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 नवंबर, 2020 को 'सरकार के प्रमुखों की एससीओ परिषद' में अपनी प्रस्तुति में एससीओ में आर्थिक विकास के लिए भारत के दृष्टिकोण को अभिव्यक्त किया, जिसमें दीर्घकालिक विकास के लिए कनेक्टिविटी परियोजनाओं के विविध घटकों पर महत्व दिया गया।

बिम्सटेक

बिम्सटेक का निर्माण बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे संस्थापक सदस्यों के साथ हुआ, और बाद में म्यांमार, नेपाल, और भूटान को इसमें शामिल किया गया। 30 मई को नई दिल्ली में श्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बिम्सटेक, जिसमें वर्तमान में पांच दक्षिण एशियाई राष्ट्र और दो आसियान सदस्य शामिल हैं, ने संकेत दिया कि आने वाले वर्षों में यह क्षेत्रीय समूह भारत की विदेश नीति में एक प्राथमिकता होगी।

परमाणु शक्ति का शांतिपूर्ण उपयोग

मोदी सरकार द्वारा केंद्रित राजनयिक प्रयासों के कारण, भारत चार निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में से तीन में शामिल हो गया- मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, वासेनार समझौता और ऑस्ट्रेलियाई समूह- और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता के लिए वह काम कर रहा है, चीन इस संबंध में केवल एक रोड ब्लॉक है।

अफ्रीकी राष्ट्रों को जोड़ना

पहली भारत-अंगोला संयुक्त आयोग की बैठक सितंबर 2020 में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री और अंगोला के उनके समकक्ष ने की थी। बैठक के दौरान स्वास्थ्य, राजनयिकों के प्रशिक्षण और वीजा सुविधा पर 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। साओ टोम प्रिंसिपे, सिएरा लियोन और टोगो में तीन और मिशनों के उद्घाटन के साथ 2020 में अफ्रीका में हमारी राजनयिक उपस्थिति और बढ़ गई। 17 अफ्रीकी देशों ने अफ्रीका के लिए टेली-एजुकेशन और टेलीमेडिसिन में भारत की प्रमुख परियोजना के तहत समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं जिन्हें ई-विद्या भारती और आरोग्य भारती नेटवर्क परियोजना कहा जाता है। भारत ने लगभग 3 बिलियन अमरीकी डालर के विभिन्न एलओसी की घोषणा करके अफ्रीका के साथ अपने विकास साझेदारी सहयोग को जारी रखा।

भारत ने 35 अफ्रीकी देशों को कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में अनुदान के आधार पर लगभग 1.8 मिलियन अमरीकी डालर की कोविड दवाएं प्रदान करके चिकित्सा सहायता प्रदान की है। आईटीईसी कार्यक्रम के तहत कम से कम 16 अफ्रीकी देशों को भारत में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए गए। वंदे भारत मिशन के तहत 4000 से अधिक भारतीय नागरिकों को भारत वापस लाया गया। भारत ने इथियोपिया, केन्या, रवांडा और तंजानिया के साथ एयर बबल व्यवस्था की स्थापना की।

आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस

(आधुनिक भारत के रक्षक)

श्री नरेंद्र मोदी जी के 13 साल के लंबे कार्यकाल में गुजरात काफी समृद्ध हुआ। बुनियादी ढांचे, बिजली के साथ-साथ उद्योगों के क्षेत्रों में राज्य के विकास ने नित नए मानक स्थापित किये और आने वाले वर्षों में कई राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना दिया है। गुजरात शासन मॉडल में आर्थिक उत्थान के साथ-साथ कानून और व्यवस्था की स्थिति का विशेष ध्यान दिया गया।

एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो 2002 में गुजरात में हुई जो अभी भी बहस और विवादों को जन्म देती है, उसमे भाजपा सरकार पर गुजरात में दंगों को जानबूझकर भड़काने का आरोप लगाया गया था। उस कठिन दौर में भी श्री नरेंद्र मोदी शासन के प्रति प्रतिबद्ध किया और धैर्यपूर्वक अपना पक्ष साबित करने के लिए कानूनी तरीके का पालन किया। वर्ष 2019 में, न्यायमूर्ति नानावती मेहता के नेतृत्व में एक आयोग ने उन्हें 2002 के दंगों को भड़काने वाले किसी भी घृणित अपराध के लिए निर्दोष घोषित किया। 1500-पृष्ठ लंबी रिपोर्ट में कहा गया है कि "यह कोई नहीं कह सकता कि ये हमले या तो प्रेरित थे या राज्य सरकार द्वारा उकसाए गए थे।

सांप्रदायिकता के कथित आरोप के अलावा, हालाँकि वो भी अब न्यायपालिका ने ख़ारिज कर दिया है, श्री नरेंद्र मोदी ने अपने 13 साल के प्रशासन के दौरान गुजरात को एक सुरक्षित और सुचारु से चलने वाला जहाँ कोई भी दंगा ना हो यानि 2002 से पहले जिस गुजरात में आये-दिन दंगे होते थे और शहरों में कर्फ्यू लगाया जाता था वहीँ मोदी जी के कार्यकाल के दौरान 2002 के बाद से गुजरात में कर्फ्यू के एक भी मामला सामने नहीं आया और प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर होता गया।

उनके कार्यकाल के अंत तक, गुजरात देश के सबसे युवा और सबसे बड़े पुलिस बल के रूप में उभरा। प्रशिक्षुओं में 61 पुलिस

उपाधीक्षक (डीएसपी) शामिल थे, जिनमें 20 महिलाएं, 177 पुलिस उप-निरीक्षक, 116 महिला लोक रक्षक और 33 खुफिया अधिकारी शामिल थे।

साथ ही, अपराध दर भी सबसे कम उन्ही के कार्यकाल के दौरान हुई, आंकड़ों की बात करें तो 2000 से पहले के दौर में गुजरात में कानून-व्यवस्था एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। श्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में प्रदेश को रहने के लिए एक सुरक्षित जगह बनाने के लिए सख्त और सुधारात्मक कदम उठाए। सांख्यिकीय रूप से कहें तो, उनके कार्यकाल में राज्य की अपराध दर 11.8 फीसदी थी जबकि राष्ट्रीय दर 19.6% थी। गुजरात में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले की दर 0.7% थी जबकि राष्ट्रीय दर 2% थी। यह गुजरात सरकार के विधायी और नीतिगत कार्यक्रमों के कारण ही संभव हुआ। मीडिया घरानों ने सुरक्षा और सुरक्षा के मुद्दे से निपटने में राज्य की सफलता पर बहुत से लेख प्रकाशित किए।

2014 में अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी, नरेंद्र मोदी जी अपने मूल राज्य की सुरक्षा और विकास के प्रति समय समय पर गहरी रुचि रखते हैं। कानून और व्यवस्था की स्थिति को बढ़ाने के लिए संशोधनों को पेश करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की मदद और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के काल में राज्य सरकार ने गुजरात गुंडा और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 2020, गुजरात भूमि हथियाने निषेध अधिनियम 2020, धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2003 संशोधन के साथ साथ महिलाओं और बच्चो की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये। कुछ उल्लेखनीय आंकड़े संशोधनों की सफलता की बात करते हैं जैसे कि सांप्रदायिक अपराधों में 61 फीसदी की कमी और 95.2% लापता बच्चे जो ऑपरेशन 'मुस्कान' के तहत पाए गए।

श्री नरेंद्र मोदी के उल्लेखनीय कार्यकाल के दौरान पारदर्शी शासन की प्रथाओं के माध्यम से एक सुरक्षित और सुरक्षित स्थान के लिए नींव रखी गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता में आने के बाद उनके हाथों में एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई और लोग उन्हें आधुनिक भारत के रक्षक के रूप में देखने लगे।

मई 2014 में, सुधारात्मक और मूर्त परिवर्तन की उम्मीदों के बीच, श्री नरेंद्र मोदी ने अपना पहला कार्यकाल संभाला। लगभग साल भर में उन्होंने सबसे वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की द्विवार्षिक बैठक में एक अग्रगामी भाषण दिया, जिससे आसन्न परिवर्तन के बारे में समय-समय पर अटकलें लगाई गईं। उन्होंने रक्षा के क्षेत्र में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर बाहरी और आंतरिक खतरों के प्रति असहिष्णु के इरादे का संकेत दिया।

लंबे समय से प्रतीक्षित वन रैंक वन पेंशन को लागू करना जो बीते 4 दशकों से रुका हुआ था, रक्षा क्षेत्र में मेक-इन-इंडिया को बढ़ावा देना, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति, रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उद्योग के साथ सहयोग बढ़ाना, रक्षा अधिग्रहण में अधिक पारदर्शिता के साथ तेजी लाने के उपाय, सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं विकास में परिवर्तन, दूरस्थ स्थानों तक राष्ट्रीय कैडेट कोर के विस्तार और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में नागरिक प्रशासन डिफेन्स फोर्सेज द्वारा दी गई सहायता, श्री नरेंद्र मोदी ने भारत की रक्षा शक्ति के निर्माण पर अत्यधिक जोर दिया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की सांख्यिकीय रिपोर्ट के अनुसार, भारत को पिछले चार दशकों में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक होने का गौरवपूर्ण गौरव प्राप्त है।

यूपीए और एनडीए के दौरान रक्षा बजट की तुलना

श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने नई शुरुआत की है। कानून- व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम किया गया, साथ ही रक्षा मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन तेजी से बढ़ाया गया।

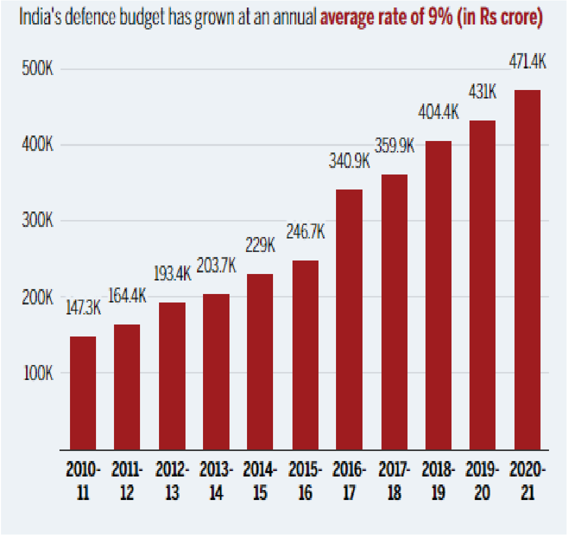

रक्षा बजट 2010-2020

ऊपर दिया गया ग्राफ पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा अपनी रक्षा आकांक्षाओं के लिए दिए गए बजटीय आवंटन को दर्शाता

है। ऊपर की ओर तेजी से बढ़ता ग्राफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत सेना की प्राथमिकता को स्पस्ट रूप से दिखता है। पिछले वर्षों की तुलना में जहाँ औसतन बजट लगभग 200000 करोड़ के करीब था वहीं 201617 में बड़ाकर 340900 करोड़ किया गया। पिछले साल, रक्षा मंत्रालय का बजट बाकि सभी मंत्रालयों की तुलना में सबसे अधिक था। यह कुल बजट व्यय का 15.5 फीसदी यानी 4,71,400 करोड़ रुपये था। 2021-22 में सभी आकड़ों को पीछे छोड़ कर रक्षा बजट 4.78 करोड़ किया गया।

जम्मू-कश्मीर में सुधार- यथास्थिति में बदलाव

5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने संसद में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को रद्द करने का प्रस्ताव रखा और संसद के दोनों सदनों में इसे पारित करवाकर जम्मू कश्मीर से धरा 370 को समाप्त किया, जो जम्मू-कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। नेहरू जी के वक्त से चले आ रहे इस विवादस्पद निर्णय को समाप्त किया गया, जम्मू -कश्मीर में विकास के लिए इस महत्वपूर्ण कदम को उठाकर श्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास के पन्नो में सुनहरे अक्षरों में अपना नाम अंकित किया। इस कदम का पूरे देश में बड़े पैमाने पर स्वागत किया गया। इस निर्णय से राष्ट्र के साथ जम्मू-कश्मीर की अखंडता के प्रति भारत का संदेश जोर से और स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया।

2016 में जैश-ए-मोहम्मद (JeM) द्वारा सेना के अड्डे पर आतंकवादी हमला किया गया जिसमे सेना के 19 जवान शहीद हो गए। उरी में हुए इस घातक आतंकी हमले के फौरन बाद, पीएम मोदी ने देश की जनता से वादा किया कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय सेना ने मुँह तोड़ जबाब देते हुए सर्जिकल स्ट्राइक करी, जिसने पाकिस्तान को गहरा घाव दिया। समूचे विश्व ने भारत के इस कदम को सही ठहराया और किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं किया।

26 फरवरी 2019 की सुबह भारतीय युद्धक विमानों ने जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा को पार किया और पाकिस्तान के अंदर घुसकर बालाकोट शहर के आसपास के क्षेत्र में निर्देशित बम दागे और आतकवादियों के प्रशिक्षण शिविर को तहसनहस कर उन्हें करारा जबाब दिया। भारत ने यह एयर स्ट्राइक पाकिस्तान द्वारा पुलवामा में किये गए आतंकवादी हमले के जबाब में थी जिसमे क्रप्फ 40 जवान शहीद हुए थे। बालाकोट में भारत की साहसिक प्रतिक्रिया ने पाकिस्तान द्वारा किये जा रहे छद्म युद्ध से निपटने के लिए एक नया आयाम स्थापित किया और ये कहा की ये नया भारत है जो ईंट का जबाब पत्थर से देना जानता है। हालांकि पाकिस्तान इतनी आसानी से अपनी हरकतों से कहाँ बाज आने वाला फिर भी संभावित प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना यह अत्यंत सहासिक और रणनीतिक कदम था जिससे यह संकेत गया कि अगर भारत की सीमाओं और जनता का मुकसान होगा तो भारत हर उस कृत्य की जवाबी कार्रवाई करेगा।

सीमाओं को सुरक्षित करने और अनिश्चितता की हर दृष्टि से अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से लैस करने के महत्व को ध्यान में रखते हुए, भारतीय वायु सेना के मौजूदा स्क्वाड्रन को मजबूत करने और भारत के हवाई प्रभुत्व को बढ़ावा देने के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित राफेल जेट फ्रांस से खरीदे गए। खरीदे गए 36 जेट विमानों में से 26 इस साल जुलाई 2021 में भारत आ चुके हैं

रक्षा साइबर, अंतरिक्ष एजेंसियों और एक विशेष संचालन प्रभाग बनाने के आदेश दिया यह एक और ऐसी मांग थी जो लम्बे वक्त से चली आ रही थी। इन तीनों त्रि-सेवा संगठनों के प्रमुखों को मई 2019 में तैनात किया गया, इनको स्थायी अध्यक्ष, चीफ्स ऑफ स्टाफ को रिपोर्ट करना है, यह रणनीतिक स्तर पर बहुत आवश्यक विशिष्ट क्षमताओं के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है। समय के साथ, इन्हें ट्राई-सर्विसेज कमांड के स्तर तक अपग्रेड किया जाएगा।

1960 में प्रस्तावित होने के बाद भी वर्षों तक लंबित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को बनाने का फैसला अक्टूबर 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया। इंडिया गेट के पास बने इस राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्मारक का अनावरण 25 फरवरी 2019 को पीएम मोदी द्वारा किया गया। जैसे ही उन्होंने स्मारक में शाश्वत ज्योति जलाई, राष्ट्र ने उन सभी बहादुरों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद से युद्धों और संघर्षों में भारत की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी।

श्री नरेंद्र मोदी ने देश में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने पर अधिक बल दिया। मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने कई नई शुरुआत की है। हालांकि कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र भी अपनी तरफ से ऐसी पहल करता रहा है जिससे पूरे

देश की कानून-व्यवस्था की स्थिति को मजबूत किया जा सके। देश भर में कई फोरेंसिक विज्ञान कॉलेज स्थापित किए जाएंगे जो राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गुजरात से संबद्ध होंगे। सरकार की परिकल्पना है कि 2024 से पहले देश भर के आधे राज्यों में फॉरेंसिक साइंस कॉलेज खोले जाएंगे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की शुरुआत 2020 में हुई थी। यह विश्वविद्यालय देश भर के कॉलेजों को जोड़ने का भी काम करेगा, जिससे हमें प्रशिक्षित जनशक्ति भी मिलेगी।

श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि देश में आतंकवादी हमलों के मद्देनजर किसी भी व्यक्ति को अपनी जान नहीं गंवानी पड़े। ◆

- भारत ने तीन दशकों के बाद आर्टिलरी गन का एक बैच शामिल किया है।
- रूस ने 2021 के अंत तक एस-400 की आपूर्ति करने को कहा है, जो सीमापार से आने वाले शत्रु विमानों, मिसाइलों और यहां तक कि ड्रोन को 400 किमी तक की सीमा के भीतर नष्ट करने में सक्षम है, जिसकी ट्रैकिंग क्षमता लगभग 600 किमी है।
- भारत ने सफलतापूर्वक एक एंटी-सैटेलाइट (ASAT) मिसाइल परीक्षण किया, जिसका नाम मिशन शक्ति है, जो कक्षा में उपग्रहों को मार गिराने की क्षमता प्रदर्शित करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है।

समस्या को सुलझाने वाले नेता

(एतिहासिक गलतियों का समाधान)

चाहे वह संकट प्रबंधन हो या लंबे समय से चले आ रहे विवादित मुद्दों को हल करना हो या वादों को पूरा करना, वर्षों के अनुभव से यह कुशाग्रता उपजती है, यह अनुभव ही विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का सही तरीका है। लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए लोकतांत्रिक जवाबदेही और राज्य की प्रभावशीलता को साथ-साथ चलना होगा। इस प्रकार, कच्छ और भुज भूकंप के साथ-साथ कोविड महामारी जैसे संकट को 'बेहतर निर्माण' की दिशा में अवसरों में बदलना और आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, अनुभव और कौशल से ही उपजा है, जबकि सामाजिक मुद्दे जैसे नागरिकता (संशोधन) अधिनियम जैसे निर्णय हो या न्यायालय के फैसले के बाद श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना यह देश की जनता के प्रति की गई प्रतिबद्धता से उपजा है।

कच्छ और भुज भूकंप के बाद गुजरात कैसे आत्मनिर्भर हुआ

52 वां गणतंत्र दिवस पूरे भारत में मुस्कान और उत्सव लेकर आया, वहीं इसके विपरीत, देश के पश्चिमी हिस्से में एक खतरनाक सुबह हुई जब कच्छ और भुज में 7.7 रिक्टर पैमाने के भूकंप में 13805 से अधिक लोग मारे गए और 167000 घायल हो गए। 11,43,624 निजी एवं वाणिज्य परिसर, 4020 स्वास्थ्य सुविधा केंद्र, दो बांधों सहित 312 जल आपूर्ति योजनाओं, दो जल उपचार संयंत्रों और 1500 किमी से अधिक जल आपूर्ति पाइपलाइन, बिजली आपूर्ति सुविधाओं, परिवहन सुविधाओं, 18304 शैक्षिक परिसर, 62 नगरपालिका भवन, ऐतिहासिक स्मारक, पर्यटन स्थल और अन्य 7796 सरकारी प्रतिष्ठान क्षतिग्रस्त और ध्वस्त हो गए, जिससे वित्तीय नुकसान 28,423 करोड़ से अधिक हुआ। अपने समुद्र तट के पार भीषण भूकंप का अनुभव करने के बाद गुजरात मुश्किल में था और उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो इस मुश्किल समय में मजबूती से प्रदेश को संभाल सके।

इस त्रासदी के सात महीने बाद 2001 में अक्टूबर का महीना था,

जब श्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात की कमान संभाली। भूकंप से प्रभावित क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। मुख्यमंत्री ने स्थायी आपदा-लचीला विकास के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए "मालिक द्वारा संचालित पुनर्निर्माण" के साथ "बेहतर निर्माण" के उद्देश्य से पुनर्वास चरण की शुरुआत की। उन्होंने प्रभावित जनता के राहत और पुनर्वास कार्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी का इस्तेमाल किया। अपने नेता में पूर्ण विश्वास रखते हुए, कई नागरिक समाज समूहों, पेशेवर संघों, सामुदायिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों ने गुजरात के पुनर्निर्माण के लिए मुख्यमंत्री के हाथ से हाथ मिलकर काम करना शुरू किया। राज्य के मुखिया के रूप में तेरह साल के कार्यकाल में, श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को इस भीषण त्रासदी से बाहर निकलने के साथ साथ विकास के मार्ग पर तेजी से बढ़ाया। आवास, सिंचाई, बुनियादी ढांचा, कृषि, सामाजिक कल्याण और पर्यटन क्षेत्र में सुधारों और योजनाओं की श्रृंखला के साथ, गुजरात चौतरफा समृद्धि के साथ नए सामान्य युग में वापस आ गया। अगर आवास योजना की बात करें तो यह शायद गुजरात पुनर्निर्माण कार्यक्रम का सबसे नवीन पहलू था। यह बहु जोखिम प्रतिरोधी निर्माण और क्षमता निर्माण पर जोर देने वाला एक सहभागी कार्यक्रम था। लोगों के प्रयासों को मुख्य रूप से सरकार द्वारा आवश्यक सामग्री के रूप में सस्ती दरों पर वित्त के साथ समर्थन किया गया था। उन्हें सरकार द्वारा इंजीनियरों के माध्यम से तकनीकी सहायता भी दी गई। श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण ही यह आश्चर्यजनक गति संभव हुई। इसके अलावा, मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गरीब समृद्धि योजना और स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना जैसे विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों के तहत गरीबों को आवास सुविधाओं की परिकल्पना की। 2001 के भूकंप के बाद राज्य में बहुत अधिक शिक्षा संस्थान नष्ट हो गए थे और स्कूली शिक्षा अत्यधिक प्रभावित हुई। सरकार ने प्रथम वर्ष में ही प्राथमिक विद्यालयों की 42,678 कक्षाओं की मरम्मत की। जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है तो सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं को भूकंप के बाद थोड़े समय के भीतर अस्थायी और वैकल्पिक संरचनाओं के साथ क्रियाशील बना दिया गया। विशेष रूप से, राज्य सरकार ने कच्छ के जिला अस्पताल, जी के जनरल अस्पताल का पुनर्निर्माण किया था, जो भूकंप के दौरान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, बेस आइसोलेशन तकनीक संरचनात्मक तकनीक का उपयोग किया जो इमारतों को भूकंप प्रतिरोधी बनाती है।

गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2003 देश के आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के ब्लूप्रिंट के तौर पर काम किया जो बाद में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अस्तित्व में आने में सहायक बना। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं।

बाद में गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले नागरिकों के बेहद खराब स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं, लड़कियों, बच्चों और दिव्यांगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू कीं। इनमें चिरंजीवी योजना, मातृ वंदना योजना, कस्तूरबा पोषण सहाय योजना, कर्मयोगी तालीम योजना और मिशन बालम सुखम प्रमुख हैं।

कच्छ के साथ-साथ सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पेयजल और कृषि के लिए सिंचाई की सुविधा जैसी दो प्रमुख चुनौतियां थी। कच्छ और सौराष्ट्र की गृहणियों के पास पेयजल के लिए मीलों पैदल चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद इसे प्राथमिकता देते हुए कच्छ और सौराष्ट्र में पानी की समस्या दूर करने के लिए स्वर्णिम गुजरात सौराष्ट्र-कच्छ जल ग्रिड परियोजना-2011 शुरू की। इस योजना के तहत 400 किलोमीटर लंबी कई पाइपलाइंस बिछाई गई जिनमें धनकी से रतनपुर (राजकोट) की 150 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, मालिया नहर के समानांतर धनकी से मालिया की 135 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, वल्लभीपुर नहर के समानांतर धनकी से नवादा की 90 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन और मालिया से धारंगध्रा को जोड़नेवाली 30 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन शामिल है। राज्य सरकार की आर्थिक मदद से 2015 में तैयार इस परियोजना पर 25 अरब की लागत आई। इस परियोजना से घरों में नलों के कनेक्शन में काफी वृद्धि हुई और पेयजल की जरूरतों को लेकर भूजल और बारिश पर लोगों की निर्भरता भी कम हुई। पेयजल और कृषि के लिए सिंचाई सुविधाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए सरदार पटेल सहभागी जल संचय योजना, खेत तलवड़ी योजना और सुजलाम सुफलाम योजना शुरू की गई।

इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए किसानों के फसल को बाजारों तक सुगमता से पहुंचाने के लिए किसान पथ योजना के तहत आधुनिक सड़कों का निर्माण किया गया। इसके अलावा मोदी जी ने ज्योति ग्राम योजना के तहत गांवों में 24 घंटे बिजली पहुंचायी। उन्होंने

अपनी ओर से कोई भी प्रयास नहीं छोड़ते हुए कृषि और मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करते हुए पर्यटन के क्षेत्र में कच्छ को नई ऊंचाई प्रदान की। 2001 के विनाशकारी भूकंप से लेकर पर्यटन के क्षेत्र में 2012 में रिकॉर्ड 13.6 फीसदी की विकास दर तक, करीब 2.5 करोड़ पर्यटक गुजरात आए। मुख्यमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में रण ऑफ कच्छ का सुंदर रुपांतरण हुआ। 2005 में शुरू दो दिवसीय महोत्सव सह पर्यटक आयोजन कच्छ का रण उत्सव पश्चिमी राज्य का पूर्णकालिक सर्वोत्कृष्ट पर्यटक आयोजन बन गया है। हर साल अक्टूबर से फरवरी तक चार महीने के लिए रण उत्सव का आयोजन होता है। यह उत्सव इस क्षेत्र के लोगों को आर्थिक और रोजगार के कई सुअवसर प्रदान करता है। रण के एक असुरक्षित स्थान की अवधारणा को बदलने के लिए मुख्यमंत्री जी ने रण ऑफ कच्छ नाम से एक महोत्सव मनाने की योजना बनाई जो देश और दुनिया के अन्य क्षेत्रों के पर्यटकों को आकर्षित कर सके। और इसलिए जो भी पर्यटक एकबार रण ऑफ कच्छ घूम कर जाता है वो दूसरों को यह कहकर चिढ़ा सकता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। भुज के विनाशकारी भूकंप ने आने वाले समय के लिए राज्य को एक सीख दी है। भूकंप जैसी विनाशकारी प्राकृतिक आपदा से गुजरने के बाद भविष्य की आशंकाओं के मद्देनजर अपनी दूरदृष्टि का परिचय देते हुए मोदी जी ने इनसे निपटने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार किया। कार्यान्वयन, अनुश्रवण और पुनर्निर्माण व पुनर्वास कार्यों के प्रभावी आपदा प्रबंधन और खतरे को कम करने के लिए गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2003 बनाया गया। इस अधिनियम के जरिये आपदा प्रबंधन में सभी प्रमुख हिस्सेदारों की भूमिका तय की गई। इस प्रकार आपदा प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचा तैयार कर रास्ता दिखाने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बना।

सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर राज्य के सर्वांगीण विकास को मजबूती प्रदान की गई। मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं, लड़कियों और बच्चों के आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य और साफ-सफाई पर विशेष जोर दिया। इन पहलूओं को बेहतर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए सखी मंडल योजना, कुवरबाई नू ममेरु योजना, मिशन बालम सुखम, निर्मल गुजरात शौचालय योजना, चिरंजीवी योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (किलकारी) और गरीब कल्याण मेला का आयोजन किया गया।

जनवरी 2004 के अंत तक 1 लाख 86 हजार 967 घरों का निर्माण हुआ और 9 लाख 1 हजार 150 घरों को मरम्मत किया गया। इस प्रकार लगातार तीन सालों में 95 फीसदी काम पूरा हुआ। कच्छ में सरकार ने मात्र 3 सालों में 87 फीसदी मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम पूरा किया।

इस प्रकार भुज जैसी विनाशकारी भूकंप से तबाह गुजरात, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से खड़ा होने में जूझ रहा था, दहाड़ता हुआ देश के विकसित राज्यों की सूची में पहले नंबर पर पहुंच गया। आज गुजरात 2001 की त्रासदी को पीछे छोड़ता हुआ विकास की नई ऊंचाईयां छू रहा है। यह संभव हो सका सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की दृढ़ इच्छाशक्ति और बिना थके निरंतर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए गए उनके कार्यों से और वे कोई और नहीं बल्कि देश के प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी हैं।

तीन तलाक को समाप्त करना

सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का मूलमंत्र रहा है। यह समाज के लिए संपूर्ण, कल्याण उन्मुख और श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सरकार का यह प्रयास रहा है कि वो समाज के हर वर्ग के नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करे। इनमें महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय सभी शामिल हैं। अच्छे शासन व्यवस्था का एक सकारात्मक पहलू देखना है तो आप श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के कुछ ऐतिहासिक फैसलों को देख सकते हैं जिनमें प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरेजेस एक्ट 2019 के तहत तीन तलाक की परंपरा को समाप्त कर इसे अपराध की श्रेणी में शामिल करना है।

22 अगस्त 2017 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक बार में ही तीन तलाक (तलाक ए बिद्दत) को असंवैधानिक ठहराते हुए इसे संविधान की धारा 14 और 15 का उल्लंघन बताया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने तीन तलाक जैसी असंवैधानिक और पक्षपातपूर्ण परंपरा से मुस्लिम महिलाओं को निजात दिलाने के लिए द मुस्लिम वीमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरेज) एक्ट 2019 लाई। तीन तलाक (तलाक ए बिद्दत) के जरिये शादी को समाप्त करने की परंपरा पूरी तरह से मुस्लिम महिलाओं के प्रति

धारा 370 और धारा 35ए की समाप्ति के बाद

- जम्मू-अखनूर रोड और चेनानी-शुद्धमहादेव जैसी परियोजना बड़ी ही तेज गति से जारी है। सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाकर दो स्थानों की दूरियों को तेजी से कम करने का प्रयास किया जा रहा है। जम्मू रिंग रोड का 30 फीसदी से अधिक काम पूरा हो चुका है। 5979 करोड़ की लागत वाली 2273 परियोजनाओं का आवंटन हुआ था जिसमें से 506 परियोजनाओं को अबतक पूरा किया जा चुका है।
- पांच दशकों से चल रही उझ और शाहपुर कांडी जैसी हाइड्रो परियोजना को भी गति प्रदान की गई है। पर्यटन, हाइड्रोपावर, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य उन 14 उद्योगों में शामिल हैं जिनमें निवेश का लक्ष्य है। व्यापार को सुगम और आसान बनाने के लिए 130 से ज्यादा प्रशासनिक सुधार किए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 7 नये मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं जिनमें 4 में पढाई शुरू भी हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या को बढ़ाकर 500 से 955 कर दिया गया है जबकि सामान्य डिग्री संस्थानों में 25000 सीट बढ़ाई गई है।

अन्याय और अत्याचार था। सरकार का मूलमंत्र रहा है उनके लिए काम करने का जिन्हें न्याय की सख्त जरूरत है और इसलिए ये ऐतिहासिक कदम उठाते हुए तीन तलाक को गैरकानूनी घोषित करते हुए समाप्त कर दिया गया। 1 अगस्त 2019 को मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक जैसी सामाजिक कुरीतियों से निजात मिला जब सरकार ने इस बिल को पेश किया और संसद ने इसे पारित किया। और इसलिए 1 अगस्त का दिन देश के इतिहास में मुस्लिम वीमेन राइट्स डे के रूप में दर्ज हो गया। पिछले 6 साल के दौरान 3 करोड़ 87 लाख अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप दी गई जिनमें करीब 60 फीसदी छात्राएं हैं। हुनर हाट के माध्यम से बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं को रोजगार और रोजगार के अवसर मुहैया कराए गए। "सीखो और कमाओ", "गरीब नवाज स्वरोजगार योजना", "उस्ताद", "नई मंजिल", "नई रौशनी" आदि जैसी कौशल विकास योजनाओं के द्वारा करीब 10 लाख अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार और रोजगार के अवसर प्रदान किए गए जिनमें 50 फीसदी से अधिक लाभुक महिलाएं हैं। इस प्रकार नरेंद्र मोदी जी जैसे दूरद्रष्टा के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उनके पूर्ण सामाजिक विकास का ध्यान रखा।

धारा 370 और धारा 35ए को निरस्त करना

5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने धारा 370 को समाप्त कर दिया जिसके तहत राज्यों को विशेष अधिकार प्राप्त था और इसमें हस्तक्षेप का अधिकार भारतीय संसद को भी नहीं था। इस विशेष अधिकार के कारण देश का सामाजिक-आर्थिक जीवन प्रभावित हो रहा था। तथापि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कुशल और देश के प्रति सकारात्मक दूरदृष्टि से इस ऐतिहासिक भूल को सुधारते हुए धारा 370 और धारा 35ए को खत्म कर दिया और इस प्रकार लद्दाख और जम्मू-कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। यह एक ऐतिहासिक फैसला था जिसने स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। इसके परिणामस्वरूप इन

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिमालयन रिकॉर्ड को बरकरार रखा गया

- लद्दाख को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने अलसतेंग-द्रास-करगिल-लेह ट्रांसमिशन सिस्टम शुरू की ताकि इस क्षेत्र में निर्बाध रूप से गुणवत्तापूर्ण बिजली की सप्लाई हो सके।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में लद्दाख के विकास के लिए 60 अरब रुपये निर्धारित किए गए। 214 अरब की परियोजना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को स्थानांतरित की गई।
- लद्दाख के लिए 23000 मेगावाट ग्रिड के मेगा सोलर परियोजना पाइपलाइन में है जिसका पहला हिस्सा 7500 मेगावाट का पैकेज होगा।
- जम्मू-कश्मीर की तरह लद्दाख में भी स्थानीय को रोजगार में आरक्षण देने के लिए नियम बनाए गए हैं। हाल ही में लद्दाख को पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय मिला और 10000 लद्दाखी छात्रों के लिए बुद्धिस्ट स्टडीज सेंटर स्थापित की गई।
- लद्दाख प्रशासन ने सांस्कृतिक पर्यटन को अपना प्रमुख विकास योजना बनाया है जिसके तहत पर्यटकों को मोनैस्ट्री में ठहराने, इको-टूरिज्म, बर्ड वॉचिंग और वाइल्डलाइफ सफारी की सुविधा दी जा रही है।
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पर्यटकों के लिए सियाचिन ग्लेशियर को खोलने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा पर्यटकों के लिए सीमा पर कुछ और गांवों को खोलने, सीमा पर सामरिक सड़क निर्माण आदि की बात कही है।
- साथ ही स्वीटजरलैंड के दावोस से भी मनमोहक एक हिल स्टेशन की योजना बनाई जा रही है जो 18 किलोमीटर क्षेत्र में लद्दाख के जोजीला टनल और जम्मू-कश्मीर के जेड-मोरह टनल के बीच होगा।

अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर में विकास

- आतंकी घटनाओं में 60% तक की गिरावट आई, जिसमें 2018 में 614 आतंकी घटनाएं हुई और 2020 में भारी गिरावट के साथ 244 मामले दर्ज हुए।
- दिसंबर 2020 में डीडीसी के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए, जहां पहली बार 100 महिलाएं चुनी गईं।
- पहली बार राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण लागू किया गया था, जिसके बाद 6 महिलाओं, एससी और एसटी से संबंधित दो नेताओं को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।
- गुर्जर बकरवाल जैसे समुदाय के नेता, जिनकी पहले उपेक्षा की जाती थी, अब राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल हो गए हैं। पंचायतों को 21 विषय आवंटित किए गए, जिनमें आंगनवाड़ी, मनरेगा निगरानी और खनन अधिकार शामिल थे, जिससे स्थानीय निकायों को अधिकार का एक सार्थक हिस्सा मिला।
- निवेश के लिए 13,600 करोड़ रुपये के 168 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और जम्मू-कश्मीर में उद्यमों की स्थापना के लिए 6,000 एकड़ सरकारी भूमि खरीदी गई है। एक दशक से अधिक समय से रुकी हुई कई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जम्मू-कश्मीर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की भी स्थापना की गई थी।
- विकास का चरण तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, जैसा कि श्रीनगर में रामबाग फ्लाईओवर के निर्माण से देखा जा सकता है, जो पांच साल से अधिक समय से विलंबित था।

प्रदेशों में पर्यटन, मूलभूत सुविधाओं, कृषि, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्रों में काफी विकास हुआ। दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर घृणित भेदभाव से आजाद हुआ और अब केंद्र सरकार द्वारा जारी विभिन्न योजनाओं का लाभ राज्य में रह रहे हर समुदाय के लोगों को मिल रहा है। आज भारत श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत की राह पर चलते हुए कश्मीर को शांति और समृद्धि का जन्नत बनाने का लाखों लोगों के सपनों को पूरा कर रहा है।

श्रीराम मंदिर विवाद का समाधान

9 नवंबर 2019 को अयोध्या में 1500 वर्ग गज जमीन के मालिकाना हक के 27 साल पुराने चले आ रहे विवाद पर फैसला हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अयोध्या में श्रीराम मंदिर बनाने के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट या कोई अन्य संस्था बनाने का

निर्देश दिया। इस ऐतिहासिक फैसले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने आध्यात्मिक महत्व और करोड़ों लोगों की जनभावनाओं को देखते हुए अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना की। साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने का अनुरोध किया जिसे राज्य सरकार ने मंजूर कर लिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड को निर्देशित जमीन शांतिपूर्ण तरीके से स्थानांतरित कर दी गई। भव्य श्रीराम मंदिर के निर्माण और भविष्य में उनके दर्शन के लिए मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाओं के मद्देनजर सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए करीब 67.703 एकड़ अधिकृत जमीन ट्रस्ट के नाम स्थानांतरित कर दिया।

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और न्यायपालिका के सार्थक प्रयासों के कारण वर्षों से चले आ रहे विवाद का शांतिपूर्ण समाधान हो गया। जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक भूल को सुधारा है उससे आज हर देशवासी आनंदित है और सच्चे मायनों में इसी में केंद्र सरकार का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मूल मंत्री परिलक्षित हो रहा है।

नागरिक संशोधन अधिनियम

पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक आधार पर

प्रताड़ना के बाद भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को देश की नागरिकता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 पारित कराया। अधिनियम के अनुसार धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध और जुर्दुस्त समुदाय के सभी सदस्य को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस अधिनियम के जरिये प्रकृतिकरण (नैचुरलाइजेशन) द्वारा नागरिकता की जरूरतों को भी लचीला बनाया गया। उन लोगों के लिए जो 6 धर्मों के अनुयायी हैं और इन 3 देशों से आए हैं उनके लिए प्रवास की अवधि के नियम को घटाकर 11 साल से 5 साल कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत ने एक बार फिर सर्वभौम सामंजस्य और इंसानियत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए इस अधिनियम के जरिये दूसरे देशों में धार्मिक प्रताड़ना के शिकार सभी लोगों को राहत देने की कोशिश की है।◆

- प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने गुरुद्वारा करतारपुर साहिब तक पहुंच सुनिश्चित कर सिख श्रद्धालुओं की लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान किया है।
- ब्रू-रियांग शरणार्थी समझौते के माध्यम से मोदी सरकार ने एक जटिल समस्या का स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान खोजा है जो 23 वर्षों से पूर्वोत्तर क्षेत्र में मौजूद थी। समझौते ने त्रिपुरा में ब्रू समुदाय के 34,000 लोगों के बसने का मार्ग प्रशस्त किया है। मोदी सरकार ने समुदाय की बुनियादी विकास जरूरतों को पूरा करने के लिए 600 करोड़ रुपये के पैकेज की भी घोषणा की।
- भारत में शांति और सुरक्षा के प्रति अपने समर्पण के अनुरूप मोदी सरकार ने लंबे समय से असम को परेशान करने वाली समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए बोडो समझौते पर हस्ताक्षर किए, इसने क्षेत्र में शांति की नींव रखी।

संदर्भ

21 https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-analysis/atal-pension-yojana
22 https://www.mudra.org.in/
25 http://www.7rcr.com/2013/12/25/powerful-christian-leaders-endorse-modi-and-his-work-in-gujarat/
26 https://www.india.gov.in/spotlight/pradhan-mantri-fasal-bima-yojana#tab=tab-1
27 http://janaushadhi.gov.in/pmjy.aspx
28 https://www.india.gov.in/spotlight/pradhan-mantri-garib-kalyan-package-pmgkp
29 https://pmjay.gov.in/about/pmjay
34 https://startup.gujarat.gov.in/home
35 https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1656664
36 https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2019-01/Strategy_for_New_India_2.pdf
37 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1738170
38 http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/176/AU1391.pdf
48 https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=200179
49 https://www.thehindu.com/news/national/coronavirus-pm-modi-participates-in-saarc-videoconference-to-formulate-joint-strategy-to-combat-covid-19/article31074653.ece
50 https://www.indiatoday.in/india/story/coronavirus-indian-defence-medical-team-in-maldives-to-help-deal-with-pandemic-1655369-2020-03-14
51 https://thediplomat.com/2020/03/india-evacuates-citizens-others-from-china-iran-amid-covid-19/
52 https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1731464
53 https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1731469
58 https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/view-indias-assertive-and-pragmatic-role-in-shanghai-cooperation-organisation/articleshow/79811313.cms
59 https://timesofindia.indiatimes.com/india/narendra-modi-swearing-in-ceremony-why-invitation-to-bimstec-leaders-is-relevant/articleshow/69554611.cms
60 http://mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/33569_MEA_annual_Report.pdf
(Endnotes)
1 https://www.timesnownews.com/india/article/pm-modi-continues-diwali-tradition-with-forces-to-celebrate-festival-with-jawans-at-western-border/681506
2 https://www.bestprojectsinindia.com/article/150/sauni-yojana-project?AspxAutoDetectCookieSupport=1
3 https://www.thehindubusinessline.com/opinion/columns/all-you-wanted-to-know-about-sagarmala/article8640858.ece
4 http://sagarmala.gov.in/sites/default/files/sagarmala-eng.pdf
5 Mishra, P. (2001). THE KUTCH EARTHQUAKE 2001 Recollections, Lessons and Insights. https://nidm.gov.in/PDF/pubs/KUTCH%202001.pdf
6 Sharma, R. (2001). India plans massive hospital rebuilding after earthquake. BMJ : British Medical Journal, 322(7284), 451. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1119681/
7 https://www.thehindubusinessline.com/news/Power-Minister-plans-to-roll-out-Gujarat%E2%80%99s-Jyoti-Gram-scheme-at-the-national-level/article20793910.ece
8 Speech of Narendra Modi, Chief Minister of Gujarat in the 55th NDC meeting, New Delhi.

https://niti.gov.in/planningcommission.gov.in/docs/plans/planrel/55ndc/gujarat_55ndc.pdf (pp 5-6)
9 http://www.gsdma.org/Content/gujarat-emergency-medical-services-act-2007-4242
10 Budget Speech 2009-10 No 5.
11 https://theprint.in/report/started-by-modi-cms-fellow-programme-a-big-hit-among-states/6280/
12 http://www.gudcltd.com/swarnim-jayanti-mukhya-mantri-shaheri-vikas-yojana
13 https://thelogicalindian.com/environment/wastewater-as-resource-learnings-from-gujarat-28491
14 http://archive.indianexpress.com/news/gujarat-to-get-special-courts-for-corruption-cases/467032
15 https://www.financialexpress.com/opinion/from-cm-narendra-modi-to-pm-modi-did-scaled-up-gujarat-model-work-on-pan-india-basis-find-out/886954/
16 https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/cm-keen-on-setting-up-gobar-bank/articleshow/1430853600.cms?from=mdr
17 https://www.financialexpress.com/archive/gujarats-soil-health-card-scheme-gets-good-farmer-response/108624/
18 https://agri.gujarat.gov.in/soil-health-card-project.htm
19 http://www.globalgujarat.com/Roads_and_Highways.html
20 https://pmjdy.gov.in/about
23 https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1575403
24 https://www.business-standard.com/about/what-is-pm-kisan-yojana#:~:text=The%20Pradhan%20Mantri%20Kisan%20Samman,of%20their%20landholding%20in%20India.
30 https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2021-02/Annual-Report2020-2021-English_0.pdf
31 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1652751
32 https://www.startupindia.gov.in/content/dam/invest-india/Templates/public/5_years_Achievement_report%20_%20final%20(1).pdf
33 http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/176/AU1391.pdf
39 https://pib.gov.in/newsite/printrelease.aspx?relid=133837
40 http://164.100.47.194/Loksabha/Questions/QResult15.aspx?qref=22375&lsno=17
41 Amrita Narlikar (2017), 'India's role in Global governance: a Modi-fication', International Affairs, 93: 1, p. 111.
42 https://www.investindia.gov.in/team-india-blogs/diplomacy-difficult-times-indias-vaccine-maitri-initiative
43 https://www.dailypioneer.com/2021/columnists/different-boats-in-the-same-storm.html
44 https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1732845
45 https://www.business-standard.com/article/current-affairs/cowin-goes-global-india-makes-tech-open-source-142-nations-show-interest-121070501046_1.html
46 https://news.un.org/en/story/2021/09/1101302
47 https://twitter.com/PMOIndia/status/1441753701807317000?s=08
54 https://www.mea.gov.in/images/pdf/Final-CTB-Book-English-28052018.pdf
55 https://indianexpress.com/article/opinion/columns/india-afghanistan-evacuation-taliban-7485553/
56 https://mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/India_UN_2020.pdf
57 https://www.orfonline.org/research/india-role-global-development

61 https://www.ndtv.com/india-news/in-2002-riots-pm-narendra-modi-then-gujarat-chief-minister-and-his-ministers-get-clean-chit-from-nan-2146976

62 https://www.outlookindia.com/newswire/story/gujarat-police-force-youngest-crime-rate-lowest-modi/762589

63 https://www.narendramodi.in/mobile/gujarats-police-force-is-the-youngest-in-india-narendra-modi

64 https://www.hindustantimes.com/delhi/truth-vs-hype-in-modi-s-boast-about-gujarat-s-women/story-EJ5SyLLW0KkcAaGDF0euWK.html

65 https://www.indiatoday.in/mail-today/story/operation-muskan-trace-missing-children-gujarat-281956-2015-07-12

66 Page 925, https://www.sci.gov.in/pdf/JUD_2.pdf

67 https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1601984

68 4 https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1591133

69 https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1601984

70 https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/citizenship-amendment-bill-decoded-what-it-holds-for-india/articleshow/72466056.cms